खण्ड-159, अंक-7
शुक्रवार, 29 आश्विन, शक संवत् 1877
(21 अक्टूबर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल,श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम, खां श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
(रामपुर)
महमूद अली खां, श्री
(सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री

मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मूरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद पोटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर शिष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रज भूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज विहारी मिश्र, श्री
व्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री

सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीतराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ अक्तूबर, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

**१-२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

रुड़की नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव

**३--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि रुड़की नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो जायेगा ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--चुनाव के लिये ३० अक्तूबर की तिथि निश्चित की गयी है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि नियमों के अनुसार नामजदगी भी उसी तारीख को होगी जिस दिन चुनाव है या किसी और तारीख को ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। नामजदगी उसी तिथि को नहीं होगी बल्कि नामजदगी के लिए प्रकाशन कर दिया गया है। नामजदगी २३ अक्तूबर को होने वाली है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि नामजदगी की तारीख वाले दिन कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए वह नामजदगी सही नहीं रहेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—नामजदगी के लिए जो तारीख निश्चित की गयी है उसमें समय निर्धारित नहीं है लेकिन जो कोर्ट का समय होता है उसी समय नामजदगी होगी ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुड़की नगरपालिका के अध्यक्ष का स्थान कैसे रिक्त हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—रुड़की नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि २३ तारीख को रविवार है, इसलिए अदालत न लगेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—अदालत न बैठे लेकिन समय उसका निर्धारित होता है और जिलाधीश महोदय उसका प्रबन्ध करेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपा करके समय भी नोटिफाई कर देगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिलाधीश ने समय निर्धारित किया होगा, नहीं किया होगा तो जिलाधीश को कह दिया जायगा ।

बनारस सेंट्रल जेल से बीमारी के कारण श्री भुवाल सिंह की मुक्ति

**४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस सेंट्रल जेल में श्री भुवाल सिंह, कैदी नम्बर ११०५२ बहुत सख्त बीमार हैं ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—वह बनारस सेन्ट्रल जेल में बीमार थे इसी कारण अब उनको छोड़ दिया गया है ।

**५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वक्त वे जिन्दा है या मर गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—जहां तक सरकार को ज्ञात है वे जिन्दा हैं ।

**६—श्री उमाशंकर—क्या सरकार के पास उनके भाई की तरफ से उनके प्रोबेशन (Probation) पर छोड़ने का प्रार्थना-पत्र आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

हरिद्वार के अर्धकुम्भ मेले के लिए परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने का विचार

**७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार हरिद्वार के अर्धकुम्भ मेले के प्रबन्ध के लिये सलाहकारी कमेटी बनाने का है । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ के अन्तर्गत नियमों के बन जाने के पश्चात् उक्त कमेटी बनाई जावेगी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मेला अफसर की नियुक्ति कब हुई है ?

†श्री कैलाश प्रकाश—मेले का प्रारम्भिक प्रबन्ध करने के लिये एक मेला आफिसर को ११ अगस्त, १९५६ से नियुक्त किया है और वह जिलाधीश की देखरेख में यह कार्य कर रहे हैं । जो कार्यवाही उन्हें यू० पी० मेलाज ऐक्ट के अन्तर्गत करना है, वह उक्त ऐक्ट के लागू होने के बाद ही की जा सकेगी । उक्त ऐक्ट के लागू करने के लिये विज्ञप्ति निकाली गयी है और उस पर एतराजात प्राप्त हो जाने के बाद ही वह पूर्णतः लागू किया जा सकेगा ।

---

†१२ जनवरी, १९५६ को उपमंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार श्री अध्यक्ष की आज्ञा से संशोधित ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अधिक काम मेले का इन दिनों हो रहा है, उसमें जनता की सलाह के बिना ही सब फैसले हो जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि विज्ञप्ति निकाली गई है। नियमानुसार उसमें एतराजात का समय देना था वह समय दिया गया है। जहां तक मेले का कार्य है जिलाधीश की देख-रेख में वहां के प्रबन्ध का कार्य हो रहा है।

टांडा, जिला फैजाबाद की मुख्य सड़क के थिरुआनाला से कटने के कारण असुविधा

८---श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष बाढ़ से टांडा, जिला फैजाबाद की मुख्य सड़क को थिरुआनाला ने १०० फीट की लम्बाई में काट दिया है जिसके कारण कोई सवारी आ-जा नहीं सकती, और जनता को अत्यन्त कष्ट है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---यह सड़क ५ वें मील में कट गई थी जिसके फलस्वरूप यातायात २६ जुलाई, १९५५ से ४ अगस्त, १९५५ तक बन्द रहा।

९---श्री रामसुमेर---क्या सरकार उपर्युक्त सड़क को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सड़क की मरम्मत हो चुकी है और वह ५ अगस्त से यातायात के लिये खोल दी गई है।

श्री रामसुमेर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था टांडा के बारे में और जवाब मिला है टांडा-अकबरपुर रोड के बारे में। यह सड़क थिरुआनाला से नहीं कटी बल्कि बाढ़ से कटी है, तो जो मुझे उत्तर दिया गया है, वह टांडा सड़क के बारे में नहीं दिया गया बल्कि टांडा-अकबरपुर के बारे में मिला है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसा उत्तर से स्पष्ट है यह टांडा की सड़क के संबंध में आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न इस प्रकार है, "इस वर्ष बाढ़ से टांडा, जिला फैजाबाद की मुख्य सड़क को थिरुआ नाला ने १०० फीट की लम्बाई में काट दिया है.....।" तो जो उत्तर है वह भी टांडा-अकबरपुर के सड़क के संबंध में है और इसी सड़क को थिरुआ नाला ने काटा है।

श्री रामसुमेर---अध्यक्ष महोदय मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी क्या समझ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं यह कि टांडा सड़क का उत्तर नहीं दिया गया है बल्कि टांडा-अकबरपुर सड़क का दिया गया है और मंत्री जी वहां गये भी हैं। आपको जानकारी होगी कि कौन.....

श्री अध्यक्ष---इसका स्पष्टीकरण उनके दफ्तर में कर लीजिये।

श्री रामसुमेर---कुछ दिन पूर्व मंत्री जी टांडा गये थे और किसी सड़क को देखा है वह कट गई थी। उसके लिये कुछ आश्वासन उन्होंने दिया था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, मैं टांडा स्वयं गया था और मैंने सड़क भी कटी देखी थी और उसी समय उसके संबंध में ऐसे आदेश भी दिये थे कि यह शीघ्र ठीक की जानी चाहिये।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---यह सड़क टांडा से कितने फासले पर है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिस सड़क का मैंने जिक्र किया है वह टांडा के काफी निकट है और टांडा से होकर ही जाती है।

सिधौली–महमूदाबाद सड़क की मरम्मत के लिए आश्वासन

**१०.—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सिधौली से महमूदाबाद (सीतापुर) जाने वाली सड़क छठे मील पर अत्यधिक खराब हो गई है, जिससे यातायात को बन्द करना पड़ा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सड़क सातवें मील में (न कि छठे मील में) सैलाब के कारण पानी में डूबी हुई है। सड़क की सतह टूट गई है जिसके कारण शीघ्रगामी यातायात संभव नहीं है।

**११.—श्री ताराचन्द्र महेश्वरी—यदि हां, तो क्या इसका कारण सड़क की सतह का नीचा होना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

**१२.—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या पूरी सड़क को पैमाइश करा कर सड़क की सतह को ऊंचा उठाने का आदेश देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सड़क के नीचे भागों को ऊंचा करने व पुलियों को बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि ४० मील लम्बी तहसील में यातायात के हेतु यही एक पोख्ता सड़क है ? यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों को शीघ्र कार्यान्वित करने के आदेश भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस क्षेत्र में जहाँ तक मुझे स्मरण है सड़क शायद यही है। और कुछ कच्ची सड़कें भी हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा, मैं इसके संबंध में काफी सतर्क हूं कि यह शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो।

वनस्पति घृत में रंग मिलाने के लिए बी० एल० ओझा ऐंड ब्रदर्स राजस्थान की योजना

**१३.—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उनके पास "बी० एल० ओझा एन्ड ब्रादर्स, पो० आ० नोहर, जिला गंगानगर (राजस्थान)" से कोई योजना किसी विशेषज्ञ की—जमाये हुये बनस्पति घी में रंग मिलाने के सिलसिले में प्राप्त हुई है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां।

**१४.—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उस योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री चंद्रभानु गुप्त—उक्त कम्पनी ने बनस्पति घी में रंग के लिये एक पाउडर बताया है जो कि घी को धूप या आग में पिघलाकर मिला दिये जाने से कुछ घंटों में रंग बदल जाता है।

**१५.—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—उस प्राप्त योजना के विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी जांच Public Analyst द्वारा कराई जायेगी।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १३–१५ श्री रामेश्वर लाल ने पूछे।

आगरे में बच्चों का अस्पताल खोलने के लिए विचाराधीन योजना

१६—श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जो बच्चों का अस्पताल खुलने वाला था, वह कब तक खुलेगा और उस योजना में अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—इस योजना पर सरकार विचार कर रही है और अंतिम निर्णय न होने तक इस दिशा में कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस अस्पताल के खोले जाने में अब विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की ओर से मैटरनल ऐंड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आगरा और लखनऊ में शिशु चिकित्सालय खोले जाने वाले थे। लखनऊ में वह खुल चुका है। आगरा के संबंध में आर्गेनाइजेशन की ओर से यह आया है कि उन्होंने विचार स्थगित कर दिया है। लेकिन, प्लान आपरेशन का जो ऐग्रीमेंट है वह इतना रिजिड नहीं है कि उस पर फिर से विचार न हो सके। इस संबंध में संचालक महोदय ने एक प्रोपोजल सरकार के पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि लेडी लायल हास्पिटल जो आगरा में है उसमें १३८ बेड्स हैं, उनको अगर सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज से साथ मिला दिया जाय या उसमें शामिल कर दिया जाय तो फिर से इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। तो यह चीज अभी सरकार के विचाराधीन है। अगर यह स्वीकार कर लिया गया तो इस पर फिर से वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के साथ संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में लिखा पढ़ी करेंगे।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि लेडी लायल हास्पिटल को और इस अस्पताल को मिलाने का क्या कारण है? अलग क्यों नहीं खोला जाता ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जगह की कमी को दूर करने की वजह से अगर यह मेडिकल कालेज के साथ मिला दिया जायगा तो यह १३८ बेड्स का जो हास्पिटल है वह शिशु चिकित्सालय जो वहां खुलने वाला है उसके लिये ये बेड्स उपलब्ध हो जायंगे।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, जिलाधीश ने एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि स्थानीय जनता इस प्रपोजल के विरुद्ध है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन शिशु चिकित्सालयों में जो लखनऊ और आगरा में खुलने वाले हैं किस अवस्था तक के बच्चों का इलाज होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न केवल आगरे के बारे आप पूछ सकते हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—जिस उम्र तक वह शिशु माने जाते हैं उसी उम्र तक उनका वहां इलाज होगा ।

रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंटल इग्जामिनेशन्स, इलाहाबाद के कार्यालय का गबन

१७—श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा की १४ अक्तूबर, १९५५, की बैठक के प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि इस ४३,१८१ रु० के गबन की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों पर है ? क्या इनमें कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो इस वर्ष सेवा से अवकाश प्राप्त करने वाले हैं ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर सीताराम)—गबन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों पर है—

१—श्री केशवचन्द्र एकाउन्टेन्ट,

२—श्री बहीदुल हसन, रजिस्ट्रार,

३—श्री आर० पी० किचलू,

४—श्री एन० डी० गोठी ।

इनमें से तीन अधिकारी अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और एक अधिकारी आगामी मार्च में अवकाश प्राप्त करने वाले हैं।

**१८—श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस गबन की जांच के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे उन्होंने इसके बारे में सरकार के समक्ष क्या रिपोर्ट पेश की है ?

डाक्टर सीताराम—रिपोर्ट में कहा गया है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रारों की असावधानी से गबन हुआ है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह गबन किस तरह से किया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—कैशबुक में जो बाहर से रुपया आता था वह बैंक से, जैसे कि अभी तक मालूम हुआ है, क्लर्क निकाल लिया करता था और काउन्टरफाइल में अगर १० रुपया लिखता था तो बैंक से १०० रुपया निकाल लेता था ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ये चौथे नम्बर के अफसर एन०डी०गोठी किस पद पर हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—गोठी सेक्रेटरी हैं इंटरमीजियट बोर्ड के ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि जब यह सरकार के सामने गबन आ गया था उसके बाद उनको इस पद पर तरक्की दी गयी ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो जांच करायी गयी वह किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

डाक्टर सीताराम—डिपार्टमेंटल आफिसर्स के द्वारा ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो गबन हुआ, वह कब हुआ और उसकी सूचना कब मिली ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह गबन बहुत दिनों से हो रहा था । इस समय जो सेक्रेटरी हैं उनके पहले जो ४—५ सेक्रेटरी थे तभी से यह हो रहा था और उसका पता बाद को चला ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने यह सोचा है कि जब सभी अधिकारी अवकाश प्राप्त कर लेंगे तभी उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू होगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—इसमें जो सूची दी गयी है इसमें सिवाय श्री गोठी के और सब लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और इसमें जिनको गबन करने वाला बताया जाता है वह मिल नहीं रहे हैं, वह कहा जाता है कि पाकिस्तान भाग गया है । इसलिये पूरी कार्यवाही नहीं हो सकती । जहां तक डिपार्टमेंटल तरीका है, तो गोठी को चार्जशीट दे दी गयी है और शायद उसका जवाब डायरेक्टर के यहां आ चुका है ।

गाजीपुर ज़िले के भीमपार में आयुर्वेदिक तथा सैदपुर में जनाना अस्पताल खोलने में अड़चनें

**१९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में भीमपार में आयुर्वेदिक और सैदपुर में जनाना अस्पताल खोलने के लिये इमारत होने के बावजूद भी अस्पताल नहीं खोला गया है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—भीमपार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिये निःशुल्क भवन २ वर्ष के लिये उपलब्ध है, किन्तु जिला परामर्शदात्री समिति की राय अभी प्राप्त नहीं हुयी है। उसके आने पर निश्चय किया जायगा।

सैयदपुर में जनाना चिकित्सालय के लिये सशुल्क भवन केवल आउटडोर के लिये उपलब्ध है। परन्तु बिना शैय्याओं के जनाना अस्पताल खोलना बेकार है। पूर्ण भवन मिलने पर ही खुल सकेगा।

**२०—श्री कमलासिंह—क्या सरकार सैदपुर तहसील के अस्पताल को प्रार्विंशियलाइज करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर परामर्शदात्री समिति ने दो साल पहले सरकार के पास अपनी राय भेज दी है और ५ महीने हुये प्लानिंग कमेटी ने भी अपनी राय भेजी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसकी अभी कोई सूचना नहीं है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इसकी इंक्वायरी करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, अगर परामर्शदात्री समिति ने कोई निर्णय भेज दिया होगा, तो वह पहुंच रहा होगा।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सैदपुर जनाना अस्पताल के लिये शैयाओं के स्थान के लिये कोई मांग की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह तो उत्तर में ही बताया गया है कि वहां जब तक शैय्याओं के लिये स्थान उपलब्ध नहीं होगा तब तक उस पर विचार नहीं होगा। ऐसा जान पड़ता है कि वहां शैय्याओं के लिये भवन का अभाव है।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जनाना अस्पताल देने के लिये इस साल तैयार थे, लेकिन चूंकि नम्बर ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से नहीं मिला ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, जनाना अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री जी न कहा था किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है वह तादाद अधिक हो गयी थी इसलिये भी उस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सका।

सचिवालय में नियुक्ति के लिए परीक्षा का स्थगन

**२१—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये जो परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अक्तूबर, १९५५ में होने वाली थी वह स्थगित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—परीक्षार्थियों के बैठने के लिये जगह (Examination halls) की व्यवस्था करने में कुछ कठिनाइयों के कारण परीक्षा अब नवम्बर में होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस परीक्षा के हटाने का एक यह भी कारण था कि पश्चिमी जिलों में जो अखबार पढ़े जाते हैं मसलन हिन्दुस्तान टाइम्स वगैरह उनमें इस परीक्षा के सिलसिले का विज्ञापन नेशनल हैराल्ड या पायोनियर के बहुत बाद में दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मुझे तो कोई इत्तला नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षा किन तिथियों में होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तिथि निश्चित नहीं हुयी है, इसलिये कि जो हाल कमीशन की तरफ से तय किया जा रहा है उसका बिलकुल निश्चय नहीं हुआ है । जब हाल का निश्चय हो जायगा तब तिथि भी निश्चित कर देंगे ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के निम्नश्रेणी के काडर में जो स्थान लीव रिजर्व के रिक्त हैं उनकी इसी परीक्षा से पूर्ति की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध की तो कोई सूचना इस प्रश्न के अन्दर मांगी नहीं गयी थी । इसलिये मैं इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकता ।

नरही, जिला बलिया में मवेशी अस्पताल खोलने में आर्थिक कठिनाई

**२२—श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नरही जिला बलिया में मवेशी अस्पताल खोलने का हुक्म हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक वह क्यों नहीं खोला गया ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां । अस्पताल अब तक इसलिये नहीं खुल सका है क्योंकि वहां के निवासी अपने वादे के अनुसार अस्पताल के भवन निर्माण हेतु १२,००० रुपया अभी तक जमा नहीं कर सके हैं ।

श्री मान्धाता सिंह—क्या सरकार को पता है कि वहां के लोग रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या रुपया इकट्ठा होते ही वहां अस्पताल खोल दिया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—रुपया अगर इकट्ठा करके जमा कर दिया जाय तो जरूर खोल दिया जायगा ।

श्री मान्धाता सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह उस अस्पताल को किसी दूसरी जगह हटा करले जाने का विचार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अभी तो अस्पताल कायम होने का सवाल है ।

रजा शुगर फैक्टरी, रामपुर के सम्बन्ध में पूछताछ

**२३—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजाशुगर फैक्टरी, रामपुर में सरकार के शेयर कितने धन के हैं तथा उसके बोर्ड आफ डाइरेक्टरों में सरकार की ओर से कौन अधिकारी नियत है ?

नियोजन उप मंत्री (श्री फूलसिंह)—कोई नहीं ।

कलेक्शन के नायब तहसीलदारों को स्थायी करने के लिये प्रार्थना

**२४—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्शन के नायब तहसीलदार का पद स्थायी है या अस्थायी ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—कलेक्शन के नायब तहसीलदार का पद अस्थायी है।

**२५—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—यदि उक्त पद अस्थायी है, तो वह कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने इस विषय पर अभी कोई विचार नहीं किया है।

**२६—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—यदि स्थायी है, तो कुल ऐसे नायब तहसीलदार कलक्शन की जिलेवार संख्या क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—क्या सरकार निकट भविष्य में नायब तहसीलदार के पद को स्थायी करने प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी यह योजना ही अस्थायी है, क्योंकि सरकार की यह मंशा है कि जो लैन्ड मैनेजिंग कमेटीज हैं वही वसूल करने लगें। तो असली मंशा तो गांव समाजों से वसूली कराने का है। तो चूंकि यह पूरी स्कीम ही अस्थायी है इसलिये अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

रूप कुण्ड रहस्य के सम्बन्ध में पूछताछ

**२७—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि रूपकुण्ड की मौजूदा शोहरत देश तथा विदेश में होने के कारण वहां पर बहुत से Expeditions जाने की संभावना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि रूपकुण्ड में जो वस्तुयें मिली हैं वे ऐतिहासिक महत्व की समझी जा रही हैं इसलिये सम्भव है कि लोग वहां पर जावें।

**२८—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो भी Expeditions वहां पर जायेंगे वहां से मनुष्य अस्थियां तथा अन्य पवित्र वस्तुयें लायेंगे, इन Expeditions के भविष्य में जाने पर कोई शर्तें लागू करेगी?

**२९—क्या सरकार रूपकुण्ड का रास्ता तथा रूपकुण्ड स्वयं के लिये जो कि Strategic Zone में पड़ते हैं भविष्य में जाने वाले Expeditions पर कोई प्रतिबन्ध लगयेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश विदेश से रूपकुन्ड क मामले में बहुत इंक्वायरी आ रही है और बहुत से आदमी वहां जाना चाहते हैं, ऐसी लोगों ने सरकार से ख्वाहिश जाहिर की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इस बात का पता है कि देश विदेश में लोगों को इस बाबत दिलचस्पी है और लोग शायद वहां जाना चाहते होंगे, लेकिन सरकार के पास किसी ने नहीं लिखा है जहां तक मुझे मालूम है ।

श्री भगवान सहाय—क्या वहां जो लोग जाना चाहते हैं और जिनको बोना फाइडीज के बारे में मालूम नहीं हैं और रूपकुंड स्ट्रेटेजिक एरिया में पड़ता है ऐसी बात मान कर सरकार क्या प्रतिबंध लगायेगी जिससे वह इसका मिसज न करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी बाबत कोई खास बात नहीं है जिनको बोना फाइडीज में संदेह है वह वहां जाही नहीं सकते, चाहे रूपकुन्ड या कोई और जगह हो क्योंकि ऐसी हालत में परमिट की जरूरत पड़ेगी उस समय उनकी बोनाफाइडीफ़ का पता लग जायगा ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रूपकुण्ड में जो अस्थियां वगैरा पड़ी हुयी हैं या जो वहां पर मूर्तियां मिली हैं वहां से वह हटाई न जा सकें इसके ऊपर सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रूपकुन्ड में कोई मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन मनुष्य की लाशें मिली हैं । उनके हटाने का सवाल यों नहीं है कि अगली गर्मी तक तो वहां कोई जा नहीं सकता है और न हटाने का प्रयत्न कर सकता है और तब तक पता भी लग जायगा कि उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है ? अभी समय काफी है ।

ग्राम रानी खेरा, जिला रायबरेली के निकट मोटर दुर्घटना

**३०—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ४ सितम्बर, सन् १९५५ को रानीखेरा ग्राम थाना बछरावां जिला रायबरेली के निकट एक पब्लिक कैरियर द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक व्यक्ति ४ सितम्बर, सन् १९५५ को रानी खेरा ग्राम के निकट पब्लिक कैरियर द्वारा जख्मी हुआ था । अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी ।

**३१—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अधिकारियों द्वारा अभियुक्त के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभियुक्त का चालान कर दिया गया है और मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु हुयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, प्रकाश मैं समझता हूं अदालत में पड़ सकता है, मैं तो अन्धकार या प्रकाश कुछ भी डालना नहीं चाहता ।

गलत इन्दराजों को दुरुस्त करने के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति

**३२—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ने प्रान्त के कुछ जिलों में कागजात दुरुस्ती (गलत इन्दराज) के लिये कुछ नायब तहसीलदार या तहसीलदार रखे थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । कागजात दुरुस्ती के लिये तहसीलदार रखे गये हैं ।

**३३—श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि गत जुलाई मास से इनको वापस बुला लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने जुलाई से अब तक कई बार सरकार को लिखा है कि नायब तहसीलदार वहां नहीं गये हैं, यह सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––सवाल तो तहसीलदारों के बारे में पूछा गया है, ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री केशव पांडेय ––जिस तहसीलदार के बारे में यह प्रश्न है, मैं उसी के बारे में पूछता हूं जो कागजात दुरुस्ती करने के लिये रखा गया था, वह जुलाई से वहां नहीं रह रहा है, इसके लिये उन्होंने लिखा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––जितने तहसीलदार वहां नियुक्त किये गये थे, उन सब का ऐक्स-टेंशन कर दिया गया है।

केन कोआपरेटिव आडीटर्स को नया वेतन क्रम देना

**३४––श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)––क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या केन कोआपरेटिव के आडीटर्स पहले रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत थे ? यदि हां, तो वे कब इस विभाग से पृथक किये गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––(अ) हां। १९४७ में।

**३५––श्री तेजप्रताप सिंह––दिनांक १० अक्तूबर, १९५५ के प्रश्न संख्या ४५ के संबंध में कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन कोआपरेटिव के आडीटर्स को नये वेतन क्रम में शामिल किये जाने के पहिले इस सम्बन्ध में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श किया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––हां।

श्री तेज प्रताप सिंह––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केन कोआपरेटिव आडीटर्स आज कल क्या चीफ आडिट आफिसर के अधीन हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––जैसा कि बताया गया है वह पहले कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के मातहत थे और अब वह बदल गया है जब से यह नया आया है।

श्री तेजप्रताप सिंह––मेरा प्रश्न यह था कि वह चीफ आडिटर के अन्तर्गत हैं या किसी और आफिसर के ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––जाहिर है कि आडिटर जो हैं वह चीफ आडिटर के मातहत हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो उन्होंने सलाह ली थी वह क्या थी और उन्होंने क्या परामर्श दिया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––जो १९ आदमी एप्रूव हो गये थे उनके लिये फिर से एप्रूवल की जरूरत नहीं, बाक़ी जो बचे थे उनके लिये उन्होंने एप्रूवल दे दिया था।

श्री तेजप्रताप सिंह––क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह सलाह दी थी कि आडिटर्स को नये वेतन क्रम में शामिल करने के पहिले उनकी परीक्षा ली जाय ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––जी नहीं, यह सही नहीं है।

देहरादून पुलिस के खिलाफ अखिल गढ़वाल सभा देहरादून की कथित शिकायत

**३६––श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस माह अक्तूबर में अखिल गढ़वाल सभा देहरादून की ओर से देहरादून की पुलिस के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मुख्य मन्त्री को मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

*३७---श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार ने उस पर कोई जांच करवाई है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार को विदित है कि देहरादून के एस० डी० ओर पुलिस के सम्बन्ध में जो शिकायतें अखिल गढ़वाल सभा, देहरादून की हैं वह उन्होंने एक पुस्तिका के रूप में छपाई हैं और क्या उसकी प्रति सरकार को मिली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझको तो नहीं मिली।

गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड में भ्रष्टाचार

**३८---श्री केशव पांडेय---क्या सरकार के पास गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड में कई मदों में लम्बी रकम गबन की तथा अन्य शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो वे क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश---गबन के सम्बन्ध में सरकार के पास केवल यह रिपोर्ट आयी है कि बोर्ड के टैक्स महकमें में गबन का संदेह किया जाता है। इस सम्बन्ध में बोर्ड के प्रेसीडेंट ने इक्जीक्यूटिव आफिसर को मुअत्तिल कर दिया है और छानबीन जारी है। स्वयं प्रेसीडेन्ट के विरुद्ध अन्य शिकायतें भी आयी हैं जिनमें प्रेसीडेंट पर इनकी सड़क निर्माण सम्बन्धी नीति, नई नियुक्तियों में पक्षपात की भावना, म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट तथा उसके अन्तर्गत बने हुये नियमों के प्राविधानों आदि की अवहेलना। म्युनिसिपल सीमा में अनधिकृत निर्माण कार्य तथा अन्य ऐसे ही आरोप लगाये गये हैं। सरकार इन शिकायतों पर विचार कर रही है।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में म्युनिसिपैलिटी के इन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---यहां से जिलाधीश को भेज दी जाती है जो शिकायतें होती हैं वह, और उन्हीं के द्वारा जांच करायी जाती है।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या ३८ के संबंध में शिकायतें कब म्युनिसिपैलिटी से सरकार के पास आई हैं?

श्री कैलाश प्रकाश---यह शिकायतें जुलाई, १९५५ से आनी शुरू हुई।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार उन शिकायतों की जांच करने के बाद निकट भविष्य में कोई प्रभावकारी कदम उठाने की सोच रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---जी, बिल्कुल सोच रही है। शिकायतों की जांच हो रही है।

जिलाधीश बलिया का किसानों के डेपुटेशन से मिलने से इन्कार

**३९---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि तारीख १० अक्तूबर, १९५५ को श्री रामनगीना सिंह, एम० पी० के नेतृत्व में बलिया जिले के जिलाधीश से कोई किसानों का डेपुटेशन मिलना चाहता था और जिलाधीश ने मिलने से इन्कार कर दिया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। जिस समय डेपुटेशन कचहरी पहुंचा उस समय जिलाधीश एक अपील के सुनने में लगे हुये थे। उन्होंने डेपुटेशन के प्रतिनिधियों से जो जिलाधीश के कोर्ट रूम में चले आये थे कहा कि वह डेपुटेशन से अदालत से काम समाप्त करने के बाद मिल सकते हैं।

**४०—श्री उमा शंकर—क्या यह सच है कि उक्त डेपुटेशन के साथ बाढ़ पीड़ित किसानों की तकलीफों को दूर करने की कोई मांग भी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कचहरी करते समय जिलाधीश के ज्ञान में किसानों की कोई विशेष मांग नहीं थी।

**४१—श्री उमा शंकर—क्या सरकार यह बता सकती है कि डेपुटेशन के मिलने की पूर्व सूचना के बावजूद जिलाधीश बलिया ने क्यों मिलना अस्वीकार किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कचहरी में डेपुटेशन के पहुंचने के पूर्व केवल एक आम घोषणा की गई थी कि जलूस निकाला जायगा। जिलाधीश को ठीक मांगों का ज्ञान नहीं था। प्रतिनिधियों ने इस बाबत जो सूचना भेजी थी वह जिलाधीश को कचहरी कार्य समाप्त करने के बाद ही प्राप्त हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि प्रजासोशलिस्ट पार्टी बलिया के सेक्रेटरी ने जिलाधीश के पास १० तारीख को २।। बजे मिलने के लिये निमन्त्रण पत्र भेजा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह अभी बतलाया गया है कि वह सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन जिलाधीश ने अपने वहां की अपील सुनने के लिये बहुत पहले से मुकर्रर कर रखा था, यह सब जानते हैं। यह चिट्ठी जो सेक्रेटरी साहब ने भेजी थी वह उस दिन चूंकि जिलाधीश एक दूसरे कार्य से टिकटलस ट्रेवलर्स को पकड़ने के लिये गये थे, प्रातः उनको नहीं मिली। वह सीधे कचहरी चले गये। वह कचहरी करने के बाद घर पहुंचे तब उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी महोदय का खत मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि २।। बजे के बाद जो मन्त्रिमंडल के लोग जिलाधीश से मिले थे, जिलाधीश ने यह कहा था कि १५ मिनट के बाद मिला जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, पौने तीन बजे के करीब यह लोग वहां पहुंचे उस वक्त जिलाधीश अपील सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जब यह अपीलें मैं खत्म कर लूंगा तब आप से बात करूंगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सूचना द्वारा जिलाधीश ने कोई टाइम निश्चित कर दिया था, यदि हां तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, कचहरी करते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं कचहरी करने के बाद मिलूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस कर्मचारी को प्रजासोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने मिलने की सूचना दी थी उसने वह जिलाधीश को नहीं दिया तो उसका क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह २।। बजे कचहरी में पहले उन्होंने कहा था कि डेपुटेशन मिलेगा। ११ से ४ तक कहचरी का समय होता है, यह सब जानते हैं। उसके बाद बंगले पर यह पर्चा भेजा गया था।

तारांकित प्रश्न

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा की कापियों का गायब होना

*१---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ ई० में हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें उत्तर की कापियों के कितने ऐसे बन्डल थे जो भेजने पर परीक्षक के पास नहीं पहुंचे ?

डाक्टर सीताराम---दो बंडल।

*२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---इस गलती के जिम्मेदार जो अधिकारी थे उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---मामले की जांच अभी जारी है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बंडल किन केन्द्रों से गायब हुये थे और उसका क्या कारण था ?

श्री हरगोविंद सिंह---इन सबकी जांच हो रही है। इन बंडलों की बाबत यह मालूम हुआ है कि रेल से गये थे और वहीं रेल में गायब हो गये।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन विद्यार्थियों की कापी इन बंडलों में थीं उनके परीक्षाफल का क्या हुआ ?

श्री हरगोविंद सिंह---उनका परीक्षाफल निकाला गया। उनको एप्रोक्सीमेट मार्क्स दिये गये। एक बंडल में १५ कापी थीं और दूसरे में शायद ६५ थीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जांच कब तक जारी रहेगी और तब तक यह विद्यार्थी पास समझे जायंगे ?

श्री हरगोविंद सिंह---जी हां, विद्यार्थियों का परीक्षाफल निकाला गया उसी आधार पर जैसा मैंने बतलाया। जांच का चूंकि रेल से सम्बन्ध है लिहाजा केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि वह उसकी जांच करे कि उन कापियों का क्या हुआ। हमारे यहां उनके दस्तखत मौजूद हैं कि कापियां गयीं, लेकिन वहां पहुंची नहीं। रेल से कापियां गयीं इसका नोट उनके लगेज के गार्ड के यहां है। कहा जाता है कि एक स्टेशन पर गायब हुई और एक रास्ते में गायब हुई।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार भविष्य के लिये कोई ऐसी तरकीब निकालेगी जिससे इस तरह कापी वगैरह गुम न हों ?

श्री हरगोविंद सिंह---हमेशा तो कापी गुम होती नहीं है और कोई तरकीब भी नहीं हो सकती सिवाय इसके कि हर जगह आदमी कापी ले कर भेजा जाय और यह एक असंभव सी बात है।

बस्ती शहर के निकट आकाश से गिरे हुये ठोस पदार्थ की जांच

*३---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को सूचना मिली है कि हाल ही में बस्ती शहर से निकट किसी स्थान पर आकाश से कोई चमकता और अत्यन्त गर्म ठोस पदार्थ का टुकड़ा गिरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर उस पर पूरा प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, एक लोहे के समान पदार्थ है जिसको Meterite कहते हैं।

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ठोस पदार्थ की रासायनिक जांच पड़ताल की जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, अभी जांच हो रही है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह घटना कब की है ?

डाक्टर सीताराम—२४ मार्च, सन् १९५५, की।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि यह पदार्थ जांच के लिये कब भेजा गया और उसका परिणाम निकलने की कब तक आशा है ?

डाक्टर सीताराम—यह भेज दिया गया है और उसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस लोहे के टुकड़े के सम्बन्ध में ऐवजामिनेशन कौन साहब कर रहे हैं और किस जगह हो रहा है ?

श्री हरगोविंद सिंह—इसकी कलकत्ता में जांच हो रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो वस्तु मिली है उसका आकार क्या है ?

डाक्टर सीताराम—आकार प्रकार तो नहीं मालूम। यह तो जांच करने के बाद ही बताया जायगा कि यह स्टोन मेटीरियल है या मेटेलिक मेटीरियल है।

गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, समोधपुर, को वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में सेशन्स जज जौनपुर का पत्र

*५—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, समोधपुर, जिला जौनपुर, के सम्बन्ध में स्पेशल जज, जौनपुर, ने मैनेजर द्वारा चलाये गये रिश्वत के एक मामले में अपनी तारीख २८ सितम्बर, १९५४ की तजवीज में सरकारी रकम लगभग १०,००० रु० की गबन की बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये स्कूल के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने को लिखा है ?

डाक्टर सीताराम—इस विद्यालय की वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में सेशन जज से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

*६—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक कागजात मंगाये गये हैं। उनके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसको सेशंस जज की बतायी हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? ऐसे कागजात कहां से मंगाये गये हैं और कब मांगे गये हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—यह ५४ में प्राप्त हुआ था। हाईकोर्ट में उसके कागजात हैं। वहां फैसला हो जाने के बाद ही वह प्राप्त हो सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बावजूद सेशन द्वारा इन अनियमितताओं के बताये जाने के ५४-५५ के वित्तीय वर्ष में १४,४०० रुपये की ग्रांट इस विद्यालय को दी गयी है ?

श्री हरगोविंद सिंह---१४ हजार रुपये की ग्रान्ट किसी को नहीं दी गयी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कुल मिलाकर १४,४०० रुपये की ग्रान्ट दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---यह सवाल पर सवाल अपने आपही हो रहे हैं। मेरी इजाजत से सवाल कीजिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैंने यह कहा कि जितने शीर्षक होते हैं उनमें कुल मिलाकर इस विद्यालय को १४,४०० रुपये की ग्रान्ट दी गयी ?

श्री हरगोविंद सिंह---ग्रान्ट के देने का एक नियम होता है, उस नियम के अनुकूल ही ग्रांट दी जाती है। जब उसकी ग्रान्ट बन्द नहीं हुयी तो उसको मिलती ही।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ग्रान्ट इस फैसले के बाद ही दी गयी है ?

श्री हरगोविंद सिंह---इसका खयाल नहीं है कि किस स्कूल को कब ग्रान्ट दी गयी, लेकिन जब तक उसकी ग्रान्ट बंद नहीं की जाती उसको ग्रान्ट मिलेगी ही।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सच है कि जिन-जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर है वही इस स्कूल के संचालक हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह---किसी स्कूल पर तो कोई मुकदमा दायर नहीं है। एक रिश्वत का मुकदमा था जो स्कूल के लोगों ने चलाया था।

श्री जोखावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन संस्थाओं में गबन के केस होते हैं, कोई ऐसा नियम है कि उनको ग्रांट न दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इनक्वारी के बाद यह होता है, इसमें तो गबन का केस है भी नहीं। एक आडिटर रिश्वत ले रहा था, मैनेजर को क्लर्क ने यह बतलाया कि ये रिश्वत ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दो डिप्टी कलेक्टरान को लेकर आडिटर को पकड़ा था, वे छूट गये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि इस विद्यालय के सम्बन्ध में और स्मृतिपत्र गये हैं, जज के फैसले के सम्बन्ध में ?

श्री हरगोविंद सिंह---श्री द्वारका प्रसाद जी तो रोज इस भवन में उसके बारे में निवेदन करते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो रिश्वत आडिटर ले रहे थे वह किसके द्वारा ले रहे थे और कौन उनको दे रहा था ?

श्री हरगोविंद सिंह---उस स्कूल का क्लर्क ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने १० हजार रुपये के गलत खर्च पर एतराज किया था और सेशन जज ने इसको अपनी तजवीज में लिखा है ?

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं, एतराज केवल यह था कि फर्नीचर और रिपेयर्स में जो स्कूल द्वारा खर्च होता है उसका मैनेजरियल रिटर्न जाता है और मेंटिनेंस ग्रान्ट लिखा जाता है। फर्नीचर ग्रांट के खर्चे का रिपेयर्स में खर्च करके उसे मैनेजरियल रिटर्न में दिखलाया था। उसमें केवल इतनी ही इररेगुलरिटी थी ।

*७---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---[१४ अक्तूबर, १९५५, को प्रश्न ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*८---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---[१४ अक्तूबर, १९५५, को प्रश्न ४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*९-१०---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---[१४ अक्तूबर, १९५५, को प्रश्न ४१-४२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*११---श्री नारायणदत्त तिवारी---[स्थानान्तरित किया गया ।]

संयोजक बारीवाला अत्याचार विरोध कमेटी, देहरादून, का आवेदन-पत्र

*१२---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)---क्या यह सही है कि मंत्री, चाय बागान मजदूर यूनियन, जिला किसान सभा और बारीवाला अत्याचार विरोध कमेटी देहरादून, का कोई आवेदन-पत्र बारी वालों के अत्याचार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी के पास आया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---संयोजक, बारीवाला अत्याचार विरोध कमेटी, देहरादून, का एक पत्र कमेटी के प्रस्तावों सहित सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश देहरादून से पूछताछ की जा रही है ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुआ है और मुख्य-मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रस्ताव तो बहुत लम्बा है । अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं पूरे प्रस्ताव को पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता । उसकी मुख्य मुख्य बातें जो आपको याद हों सुना दें ।

आचार्य जुगलकिशोर---एक तो उनके अत्याचार के सम्बन्ध में था कि वहां ज्यादा दर पर लोगों को रुपया दिया जाता है और दूसरा रुपये की वसूली के सम्बन्ध में था कि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज खोली जायं, जिससे जो ज्यादा सूदखोरी होती है वह बन्द हो जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---उनके इस प्रस्ताव पर विचार करते हुये क्या सरकार वहां कोआपरेटिव बैंक खोलने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, इस सम्बन्ध में कोआपरेटिव सोसाइटी को लिखा गया है कि वह वहां कोआपरेटिव बैंक खोलने का इन्तजाम करे ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय श्रम मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिन बारीवाला की सूदखोरी के खिलाफ यह शिकायती पत्र उनको प्राप्त हुआ है उसके बाद एक कत्ल भी इस सिलसिले में किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है ।

*१३---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[१४ अक्तूबर, १९५५, को प्रश्न ४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

*१४—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में जौनपुर जिले में कितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी ?

डाक्टर सीताराम—१४४ हरिजनों को छात्रवृत्तियां दी गयीं ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५४-५५ में हरिजन छात्रों को कुल कितना रुपया छात्रवृत्ति में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—एक मास में ६५० रुपया दिया गया था और उसी हिसाब से १२ मास का कैलकुलेट किया जा सकता है ।

हरिजन विभाग से जौनपुर जिले के हरिजनों को उद्योग धंधों के लिये सहायता

*१५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में हरिजन विभाग की तरफ से उद्योग धंधों के लिये कितने हरिजनों को सन् १९५४-५५ ई० में कितनी-कितनी सहायता दी गयी ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५४-५५ में हरिजन सहायक विभाग की तरफ से उद्योग-धंधों के लिये जिला जौनपुर के १८ हरिजनों को सहायता स्वीकृत हुयी, जिसकी तालिका संलग्न है । इनमें से पहले ११ व्यक्तियों को उनके समक्ष लिखी गयी धनराशि नकद रूप में दी जा चुकी है । शेष व्यक्ति अभी तक धन नहीं ले गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२९ पर)

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि किन उद्योग-धंधों के लिये सहायता दी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम—कपड़े की धुलाई के लिये, चमड़े के काम के लिये, जूते आदि के लिये, सूअर और मुर्गी पालने के लिये, भेड़ बकरी वगैरा के लिये और कालीन कम्बल आदि के लिये ।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि और व्यय करने के लिये धन क्यों नहीं लिया गया ?

डाक्टर सीताराम—हो सकता है कि जी० आर० ओ० की ओर से जो नियम हैं उन का पालन न हुआ होगा और उसी कारण से रुपया न दिया गया होगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है वह उन उद्योगों को चला रहे हैं या नहीं ?

श्री हरगोविंद सिंह—बहुत से लोग उनमें से वह काम नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से थोड़े दिन हुये हमने जांच करायी थी और शायद इसी वजह से बहुत से लोग मारे डर के अब नहीं ले रहे हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों से जिन्होंने उद्योग नहीं चलाया है रुपया सरकार वसूल करेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—यही नहीं कि जांच करने पर उन से रुपया वसूल किया जायगा बल्कि उन पर मुकदमा भी चलाया जायगा ।

नार्मल और हाई स्कूलों के हिन्दी-संस्कृत अध्यापकों के लिए अंग्रेजी की योग्यता

*१६--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्मल और हाई स्कूलों में हिन्दी-संस्कृत अध्यापकों के लिये अंग्रेजी के ज्ञान का प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

डाक्टर सीताराम---इन विषयों को पढ़ाने के लिये राजकीय विद्यालयों में जिन अध्यापकों की नियुक्ति ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में की जाती है, निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गयी है :

हिन्दी (१) बी० ए० हिन्दी विषय के साथ तथा एल०टी० या बी०टी०, या

(२) साहित्य रत्न २ वर्ष कोर्स साहित्य सम्मेलन प्रयाग से तथा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग,

या संस्कृत (१) बी०ए० संस्कृत विषय के साथ तथा एल०टी० या बी०टी०, या

(२) राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस, की शास्त्री परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) तथा एल०टी० या बी०टी०, या (३) राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस, की आचार्य या शास्त्री परीक्षा अंग्रेजी के साथ तथा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साहित्य रत्न और राजकीय संस्कृत कालेज के आचार्य और शास्त्री के शिक्षकों के साथ अंग्रेजी की योग्यता का कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री हरगोविंद सिंह---ग्रेजुएट ग्रेड के लिये ग्रेजुएट होना चाहिये ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि संस्कृत आचार्य और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशेष योग्यता प्राप्त लोगों के लिये क्यों यह आवश्यक है कि वे अंग्रेजी की शिक्षा अवश्य प्राप्त करें ?

श्री हरगोविंद सिंह---चूंकि यह नियम में है ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो गया है तो क्या अंग्रेजी का ज्ञान हिन्दी तथा संस्कृत अध्यापकों के लिये जरूरी है ?

श्री हरगोविंद सिंह---अब वह जरूरी हो या न हो लेकिन वह नियम में है । बी० ए० बी०टी० होना भी जरूरी है, ग्रेजुएट ग्रेड पाने के लिये इसलिये वह तो होना ही है ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी ऐसे रद्दी नियम को बदलने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह---यह नियम रद्दी नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह गैरजरूरी है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविंद सिंह---अभी तक तो जरूरी मालूम होता है लेकिन चूंकि बहुत से लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं इसलिये जरूरी है और जब गैरजरूरी हो जायगा तब वह आवश्यक नहीं होगा ।

हरिजन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें देने के लिए बस्ती जिला बोर्ड को सहायता

*१७---**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बस्ती में गत वर्ष व चालू वर्ष में हरिजन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के लिये कितना-कितना धन सरकार द्वारा जिला बोर्ड को दिया गया है ?

नोट---तारांकित प्रश्न १७ श्री धनुषधारी पांडे ने पूछा ।

श्री हरगोविंद सिंह—गत वर्ष २,१५० रु० दिया गया था। इस वर्ष बोर्ड ने इस अन्न दान के लिये आवश्यक विवरण नहीं भेजा। इसलिये बोर्ड को कोई धन स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

मैनपुरी जिले में सहायता प्राप्त अंग्रेजी स्कूल

*१८. **श्री विष्णु दयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—जिला मैनपुरी के उन स्कूलों में से जिनमें कक्षा १२ तक की शिक्षा दी जाती है किन-किन को नियमित सरकारी सहायता (Grant-in-aid) मिलती है और कितनी-कितनी ?

श्री हरगोविंद सिंह—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३० पर)

*१९—**श्री विष्णु दयाल वर्मा** (अनुपस्थित)—इन स्कूलों में से किस-किस को केवल हाई स्कूल तक की सहायता मिलती है और किस-कस को हाई स्कूल और इन्टर दोनों की और कब से ?

श्री हरगोविंद सिंह—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३१ पर)

कानपुर के सूती मिल मजदूरों का लेबर कमिश्नर को स्मृति-पत्र

*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर सूती मिल मजदूर सभा की ओर से ९ सितम्बर को मुख्य मंत्री से प्रतिनिधि मन्डल ने मिल कर कानपुर की विकट श्रम स्थिति के सम्बन्ध में स्मृति-पत्र दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*२१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो क्या उक्त स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ सितम्बर, १९५५, के आस-पास कानपुर के सूती मिलों के मालिकों और मजदूरों में छटनी के सम्बन्ध में कोई तनाव नहीं था ?

आचार्य जुगलकिशोर—तनाव तो होगा जरूर, संघर्ष तो था उस वक्त में।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के मजदूरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कोई स्मृतिपत्र इस सम्बन्ध में सरकार को दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर के मजदूरों का प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था, लेकिन उन्होंने सरकार के पास कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। उन्होंने लेबर कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया था उसकी नकल मुझे दिखा दी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मजदूरों का प्रतिनिधि मंडल उनके यहां कब मिला था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे तारीख तो ठीक याद नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्न का समय समाप्त हो गया।

कानपुर के सूती मिलों में हड़ताल कराने वाली ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच कथित समझौता

*२२—**श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत २ मई, १९५५, से कानपुर के सूती मिलों में हड़ताल कराने वाली ट्रेड यनियन और सरकार के बीच चौदह प्रश्नों को लेकर कोई समझौता हुआ था? अगर हां, तो वह चौदह प्रश्न क्या क्या थे और समझौता या स्पष्टीकरण किन-किन प्रश्नों पर क्या क्या हुआ?

आचार्य जुगलकिशोर—कानपुर के सूती मिलों में हड़ताल कराने वाली ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। अतः दूसरे प्रश्न नहीं उठते।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट के पाठ्य क्रम का गजट में प्रकाशन

*२३—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ के परीक्षा के कोर्स का Syllabus High School तथा Intermediate Board के कार्यालय से विभिन्न Schools तथा Intermediate Colleges के पास कब भेजा गया?

श्री हरगोविंद सिंह—सन् १९५६-५७ की परीक्षा का पाठ्य-क्रम उत्तर प्रदेश गजट दिनांक २३ जुलाई, १९५५ ई०, में प्रकाशित हुआ है। बोर्ड के कार्यालय से पाठ्य क्रम की प्रतियां किसी संस्था को नहीं भेजी जातीं।

देवनागरी लिपि सम्बन्धी सुधारों का विरोध

*२४—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या यह सत्य है कि देवनागरी लिपि में सुधार के रूप में जो परिवर्तन किया गया है उस के विरोध में अनेक संस्थाओं ने प्रस्ताव पारित करके सरकार के पास भेजे हैं?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां।

*२५—**श्री रामचन्द्र विकल**—[१४ अक्तूबर, १९५५, को प्रश्न ४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

इन्टरमीडियेट कक्षाओं को समाप्त करने का विचार

*२६—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या सरकार ने Intermediate परीक्षा को समाप्त कर उस की कक्षाओं को हाई स्कूल तथा बी० ए० के साथ मिलाने का निश्चय कर लिया है? यदि हां, तो इस पर कब तक अमल होगा?

श्री हरगोविंद सिंह—इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो शासन के विचाराधीन हैं।

*२७—**श्री रामेश्वर लाल**—[स्थगित किया गया।]

*२८—२९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[स्थगित किये गये।]

*३०-३२—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*३३—**श्री रामचन्द्र विकल**—[हटा दिया गया।]

*३४—**श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किया गया।]

*३५-३७—**श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी**—[स्थानान्तरित किये गये।]

हरिजन युवकों के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग

*३८—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कुछ हरिजन युवकों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में यह किसी किस्म की टेक्निकल ट्रेनिंग देने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां, हरिजनों को मिस्त्री और ट्रेसर की ट्रेनिंग देने की एक योजना बनायी गयी थी जो मार्च, १९५५ से चालू हो गई है।

*३९—श्री रामकृष्ण जैसवार—सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कमिश्नरी से कितने कितने हरिजन उम्मीदवार उक्त ट्रेनिंग के सम्बन्ध में लिये गये और कब, कहां-कहां इसकी ट्रेनिंग दी जायेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३२ पर)

*४०—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस ट्रेनिंग के कार्यकाल की अवधि क्या होगी और इस शिक्षा के समय में क्या छात्रवृत्ति दी जायेगी ? ट्रेनिंग के बाद इनकी नौकरी स्थायी या अस्थायी समझी जायगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—मिस्त्री की ट्रेनिंग २ साल दी जायगी और ट्रेसर की एक साल। मिस्त्रियों को ७५ रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है और ट्रेसरों को ५० रुपये मासिक की। ट्रेनिंग पूरी हो जाने पर नौकरी देने के लिये सरकार बचनबद्ध नहीं है। इसलिये नौकरी के स्थायी या अस्थायी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*४१—४३—श्री जोरावर वर्मा—[स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के समाज कल्याण केन्द्र

*४४—श्री कमला सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में समाज कल्याण केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं और उनके अन्तर्गत अब तक क्या क्या विशेष कार्य किये जा चुके हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—गाजीपुर जिले में समाज कल्याण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किये गये हैं :—

१—बरोवाल	२—आलूपुर
३—सुहावल	४—पटकनी
५—पकड़ी	६—डेढ़गावां
७—रेजलापुर	

ये केन्द्र राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित हैं। इन केन्द्रों में बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा तथा महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध है। घरेलू उद्योग धंधों तथा गृह विज्ञान के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। जच्चा बच्चा कार्य के लिये दाइयां रहती हैं और केन्द्रों में अन्धों, रोगियों तथा गर्भवती स्त्रियों को दूध बांटने की भी व्यवस्था है।

*४५—श्री कमला सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर जिले के समाज कल्याण केन्द्रों पर अब तक कितना-कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

आचार्य जुगल किशोर—राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार गाजीपुर जिले के विभिन्न केन्द्रों तथा प्रोजेक्ट (project) कार्यालय पर अक्तूबर १९५४ से मार्च ३१, १९५५ तक कुल १,८६० रु० ० आना ६ पाई व्यय किया गया है।

प्रश्नोत्तर का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—चूंकि आज दो प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि हाई स्कूल और इंटरमिडियेट के सिलेबस के सम्बन्ध में और देवनागरी के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या २३ और २४ इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन में कश्चेश्वन अवर १५—२० मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह नियम का सवाल है। प्रश्नों का समय बढ़ाने के लिये नियमों में परिवर्तन करना होगा, प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मैं चाहता हूं कि इस नियम को आज के लिये सस्पेंड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप का प्रस्ताव है कि नियम सस्पेंड कर दिया जाय और १५ मिनट प्रश्नों का समय और बढ़ा दिया जाय। मैं इस वक्त इसको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

६ सितम्बर, १९५५, के तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नो के उत्तर का शोधन

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ६ सितम्बर, १९५५ को तारांकित प्रश्न १ के सम्बन्ध में श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने एक अनुपूरक प्रश्न द्वारा यह जानना चाहा था कि बजट की वह कौन सी मद है जिससे कि २६ जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाने के सम्बन्ध में शासन की ओर से खर्च किया जाता है। इसके उत्तर में मैंने यह कहा था कि सूचना विभाग में कांटिजेंसी की मद है जिसमें से यह खर्च किया जाता है। वास्तव में उत्तर यह होना चाहिये कि स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती तथा गणतंत्र समारोहों का खर्च बजट की "५७—विविध व्यय—— ।विविध और अप्रत्याशित व्यय- झ—दूसरे व्यय (९) स्वतंत्रता दिवस संबंधी उत्सवों पर व्यय" मद से किया जाता है।

उपरोक्त तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में बाद में श्री भगवान सहाय ने एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि जब यह खर्च हर साल किया जाता है तो कांटिजेंसी में से क्यों खर्च किया जाता है, अलग मद क्यों नहीं इसकी बजट में दिखायी जाती है। उपरोक्त परिस्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—यह सुधरे हुये सवाल में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की मद है तो सूचना विभाग द्वारा यह कैसे खर्च किया गया?

श्री अध्यक्ष—यह उसकी मद होगी, उत्तर के ऊपर यह नहीं हो सकती।

बाराबंकी जिले के बड़ूपुर ग्राम में सर्वश्री अवधशरण वर्मा और सियाराम की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री राजनारायण जी का इस प्रकार एक कामरोको प्रस्ताव आया है। "गत १६ अक्तूबर, को जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बड़ूपुर गांव में जिस प्रकार स्थानीय पुलिस का अक्षम्य कर्तव्यहीनता से सोशलिस्ट पार्टी द्वारा पूर्व नियोजित आम सभा में स्थानीय गुंडों ने दिन दहाड़े श्री अवधशरण वर्मा, एम० एल० ए०, तथा सियाराम वर्मा की नृशंस हत्या की और जिस अमानवीय ढंग पर दोनों लाशों को जबरदस्ती जलाया गया

नोट—६ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में दोनों अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कर दिया गया है।

[श्री अध्यक्ष]

उसने प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता तथा मानव प्रेमी का दिल दहला दिया है, सारे प्रान्त का वातावरण आज इस घटना से उत्तेजित हो गया है।

अतः सदन इस आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न तथा घटना से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है। माननीय राजनारायण जी सदन की अनुमति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। मैं इसको उपस्थित करने के लिये और सदन से अनुमति लेने के लिये उनको इजाजत देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन, जो काम रोको प्रस्ताव मैंने उपस्थित किया है, उसकी गम्भीरता से परिचित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कल वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला उससे भी यह सदन परिचित है। हमारे इस सदन के माननीय सदस्य घटनास्थल पर हो भी आये हैं। कुछ लोगों से पूरी और जितनी जानकारी हासिल हो सकती थी हासिल करने की कोशिश भी की है। मैंने भी जिले के अन्तर्गत जा कर पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। अब यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह सदन अगर इस पर विचार नहीं करता, और आगे के लिये कोई रास्ता कोई हल नहीं निकालता तो मेरी धारणा है, श्रीमन्, कि हममें से एक एक कर के उठते चले जायंगे और यह मेरी धारणा निर्मूल नहीं है। मैंने इस धारणा के सम्बन्ध में कई बार इस सदन में भी बजट के भाषण पर बोलते हुए और दूसरे मौकों पर निवेदन किया है। श्रीमन्, हमारे पास काफी इसी घटना को अगर देखा जाय तो प्रमाण है कि जो कि तीन साल पहले से ही मैं इसी फतेहपुर थाने से सम्बन्धित और भगवती प्रसाद वर्मा से सम्बन्धित वहां के सरमायादारों से सम्बन्धित पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में भेज चुका हूं। उस पत्र की कापी मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—उस को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं पढ़ूंगा नहीं उसको।

श्री अध्यक्ष—क्योंकि आप को सिर्फ इतना कहना है कि क्यों आवश्यकता समझते कि काम रोक कर उस पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण—४ अप्रैल, १९५३, को भगवती प्रसाद वर्मा जो कि सियाराम के पिता थे, इससे और वहां की स्थानीय पुलिस से कितना कटु सम्बन्ध था मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह भी निवेदन कर दिया था। घटना स्थल पर गया था वहां पर मीटिंग हुई। उस दिन भी वहां के जमींदारों ने वहां की पुलिस से मिल कर हमको चैलेंज किया था और हमने यह कहा था भगवती प्रसाद वर्मा से कि मैं मीटिंग में आऊंगा अगर कत्ल हो जाऊंगा तो हंसते हंसते हो जाऊंगा, लेकिन मीटिंग हो कर रहेगी उस दिन। श्रीमन्, मैंने वहां से आ कर माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा। इसके अतिरिक्त भगवती प्रसाद वर्मा को लेकर दो बार माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल भी चुका हूं और यह बता चुका हूं कि किस तरह से पुलिस पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि, श्रीमन्, वहां पर सरमायादारों.....।

श्री अध्यक्ष—आप इसके विषय पर आ गये।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। सिर्फ आपका इशारा काफी है।

श्री राजनारायण—तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभाओं में जायंगे या इस सरकार के द्वारा आज जो निर्मित कानून हैं उन की रक्षा के लिये जायंगे क्योंकि आज ऐसा कानून बनाया है जिसमें वर्ग

विभेद हो गया है, जिनकी पहले की जमीनें थीं वह निकल रही हैं और कानूनी ढंग से निकल रही हैं, उस में जरूरी है कि जिनका धन जायगा वह चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से उनको फंसाएं, उनके मनोबल को तोड़ें। इसलिये वहां साजिश है। वहां की पुलिस और सरमायादार दोनों इसमें मिले हुये हैं, इसी घटना के संबंध में आज के सवा महीने पहले वहां के....

श्री अध्यक्ष—आप मेरिट पर आ गये। प्रान्त में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है। इस वास्ते, आप बहस करना चाहते हैं। इतना इशारा कर देना काफी है। लेकिन आप उस के ऊपर डिटेल में जायंगे तो बात मुश्किल हो जायगी, मैं उस की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—तो अब यह इतना बड़ा और अहम प्रश्न है कि इस को लेकर सारे प्रान्त में एक क्षोभ का वातावरण बना हुआ है और अभी तक श्रीमन्, हमारे पास करीब पचीस जिलों से इस संबंध में पत्र आ चुके हैं। कुछ जिलों का नाम भी हमारे पास है। जल्दी जल्दी में नोट किया था फोन पर।

श्री अध्यक्ष—जरा शान्ति रखें वहां पर।

श्री राजनारायण—यह प्रश्न केवल हमारे प्रान्त ही का नहीं बल्कि यह एक मानवता का प्रश्न है। हमारे प्रान्त के बाहर से भी यह तार अभी हमारे पास कलकत्ता से आया है वहां के लोगों ने यह जानकारी हासिल की है कि उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है जिसने दिन दहाड़े इतने बड़े फोर्स को साथ ले कत्ल कर डाला और लाश को भी लेकर जला डाला। उदाहरण के लिये यह तार मैं आपकी सेवा में भेज सकता हूं। इसके अलावा और कई जिलों से भी इन्क्वायरी मांगी गयी है बिजनौर, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, देहली, कानपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर, इन जिलों में तमाम लोग परेशान हैं कि कैसे पब्लिक लाइफ़ चलेगी। और ऐसी घटना जिसके बारे में तीन वर्षों से सरकार को सचेत करते रहे और सरकार उपेक्षा की नीति बरतती रही और पुलिस दिन दहाड़े हत्या कराती हो। श्रीमन्, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इस सम्बन्ध में मैं इतना ही समझता हूं कि जो आज प्रत्येक मानव प्रेमी का कर्तव्य है कि इस बात पर जोर दें कि इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। यह द्वितीय घटना है, ऐसी घटना हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। इसलिये इस सदन से मेरा यह निवेदन है कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करे और उसको सदन में रखने के लिये हमारा साथ दे।

श्री अध्यक्ष—जो लोग इसके पक्ष में हों कि आज का काम रोक कर इस प्रस्ताव के विषय के ऊपर विवाद होना चाहिये, वे कृपा कर के अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(५ सदस्य खड़े हुये)

केवल ५ सदस्य ही खड़े हुये जब कि ३६ सदस्यों का खड़ा होना आवश्यक है। तो सदन की अनुमति इस प्रस्ताव के उपस्थित करने के लिये और इस पर विवाद होने के लिये नहीं है।

पंचायत कर की माफी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला राजसमन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पंचायत टैक्स के सम्बन्ध में कि इधर जो जल्दी चुनाव होने वाले हैं पंचायतों के, और जब तकावी और मालगुजारी सरकार माफ़ करने जा रही है तो पंचायतों के सम्बन्ध में सरकार को आदेश जारी करना चाहिये कि जिससे पंचायत टैक्स माफ़ हो जाय और चुनाव में जो खड़े होने वाले हों वे हो सकें। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में आज स्पष्टीकरण करें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझको इत्तला है उन क्षेत्रों में पंचायत कर की वसूली सस्पेंड कर दी गयी है। और ज्यादा मैं इस वक्त सूचना नहीं दे सकता।

प्रलयंकारिणी वर्षा तथा बाढ़ से हुई हानि के सम्बन्ध में माल मंत्री का वक्तव्य

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सिलसिले में बयान देने का मुझे हुक्म हुआ है या एजेन्डा पर जो दूसरा आइटम है उस पर?

श्री अध्यक्ष—आपने अच्छी याद दिलायी। बाढ़ के सम्बन्ध में आप बयान दे दीजिये पहले।

श्री चरण सिंह—बहुत बेहतर। मान्यवर, जैसा कि सदन को मालूम ही हो चुका है समाचार पत्रों से और १३ तारीख को जो यहां वादविवाद हुआ था, पश्चिमी जिलों में बाढ़ और वाटर लागिंग से और अभी जो तूफ़ान आया, जिस रोज यहां वादविवाद हो रहा था उसी रोज जो साइक्लोन आया, उससे बड़ा भारी नुक्सान पश्चिमी जिलों को हुआ है। जो अब तक नुक्सान हुआ है तथा जिसकी इत्तला हमको उस सिलसिले में आपकी इजाजत से माननीय मित्रों को अवगत कराना चाहता हूं। अभी हमारे अफसरान केवल तहकीकात कर रहे हैं, प्रोलाम्निनरी रिपोर्ट्स उनकी हैं। तो इसीलिये जो मैं नुक्सान के आंकड़े यहां बयान करूंगा उस से ज्यादा नुक्सान हुआ है। पिछले साल अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में जितनी वर्षा हुई थी इन जिलों में उससे कई गुनी अधिक वर्षा इस वर्ष हुई है। बल्कि कई गुना क्या पिछले वर्ष तो मेरठ, सहारनपुर वगैरह और और भी कुछ जिलों में अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा था। इस वर्ष बदायूं में १०.५७ इंच बारिश हुई है, सब से ज्यादा बदायूं में हुई है। अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में जब कि पिछले वर्ष कुछ नहीं हुई थी और दूसरा नम्बर मुरादाबाद ८.६६, तीसरा नम्बर एटा ८.३२ और चौथा नम्बर रामपुर ७.४३, इन चार जिलों में अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जिलों में भी हुई है लेकिन वह ५ इंच, चार इंच, तीन इंच, उनका बतलाना मैं जरूरी नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल २४ सितम्बर से लेकर १५ अक्तूबर तक जो बारिश हुई थी अब की साल केवल मेरठ जिले को छोड़ कर जहां कि पिछले साल ९.७१ इंच बारिश हुई थी और इस साल १२ इंच हुई मतलब यह कि कम फर्क है लेकिन बाकी सब जिलों में दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी बारिश २४ सितम्बर से लेकर १४ अक्तूबर तक पिछले साल की अपेक्षा हुई। एटा और कानपुर में पिछले साल की अपेक्षा चौगुनी बारिश हुई। इस तरह दुगुने से कम कहीं नहीं हुई है। तो वर्षा इस साल बहुत ज्यादा हुई। गंगा की वजह से फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, एटा, कानपुर और उन्नाव को नुक्सान पहुंचा है। रामगंगा से फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली जिलों को नुक्सान हुआ है और छोटी-छोटी नदियों जैसे हिंडन से बुलन्दशहर को, कोसी से रामपुर को सारदा से खीरी को और बड़ी गंगा से एटा को नुक्सान पहुंचा है। अब जिनको कि एक तरह से दरिया नहीं कहा जा सकता, नाले कह लीजिये या रिव्यूलेट्स है अंग्रेजी का लफ्ज उनसे, सोंत से बदायूं को थेला और गंगोन से मुरादाबाद को कोसी और नीलम से अलीगढ़ को खीरी और काकरा से मुजफ्फरनगर और काली नदी से एटा और अलीगढ़ को बहुत नुक्सान हुआ है। इसके अलावा जैसा मैंने अर्ज किया कि साइक्लोन से बड़ा नुक्सान हुआ है तो जिन जिलों को साइक्लोन से नुक्सान हुआ है उनके नाम ये हैं—मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं। इन जिलों में १२, १३ अक्तूबर की रात को जो साइक्लोन आया जो उड़ीसा और मध्यप्रदेश से होता हुआ हमारे नार्थ वेस्ट यू० पी० में आया उससे बड़ा भारी नुक्सान हुआ। दरख्त बहुत ज्यादा तादाद में गिरे हैं यहां तक कि अधिकारियों को वक्त पर लोगों की सहायता करने में बड़ी भारी कठिनाई हुई। दस मील लम्बी सड़क पर एक ही लाइन में ५०० दरख्त एक सीधी लाइन में गिरे। इससे वन स्क्वायर माइल में कितने गिरे होंगे, इसका अन्दाजा लगाया जा

सकता है। आँवला कस्बे को जो बरेली जिले में है उस को इ अन्धड़ से बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। एक मुरब्बा माइल में ४०० मकान अगर मैं यह कहूं कि बिलकुल धराशायी हो गय,तो कोई अतिशयोक्ति न होगा। दस मौतें हुई हैं और १७ आदमियों को चोटें पहुचीं।

श्री अध्यक्ष—जरा शांति कायम रखें। सदन में बहुत जोर जोर से बातें हो रही हैं।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो लोग मकान के अन्दर सोये हुये थे, आंवला वगैरह में, जिस समय यह सोइक्लान आया, उस समय वह यह महसूस कर रहे थे कि अर्थ-क्वेक आ गया, यह उन्होंने कहा। तो जैसा मैंने कहा फसलों का बहुत नुक्सान पहुंचा है, ज्वार, बाजरा अरहर और धान को लकिन इन सब से ज्यादा नुक्सान ईख का हुआ है, क्योंकि ईख जरा ऊंचा फसल होता है और तेज हवा चलने से वह गिर जाता है।

मकान गिरने से ११३ आदमी मरे, जिनमें से ५० मेरठ में, १६ मुरादाबाद में, १२ अलीगढ़ में, १० बरेली में, ९ बदायूं में और इसके अलावा एक एक, और दो-दो, तीन-तीन कुछ और जिलों में। जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, रबी का फसल बोने में कुछ सारे सूबे में देर हो तो वहां भी देर होगा।

गंगा का पानी बढ़ने की वजह से कानपुर और उन्नाव में परसों १८ और १९ तारीख को बाढ़ आ गयी। २५० गांव उन्नाव में और ४४ कानपुर में इससे पीड़ित हुये हैं। गंगा ३ इंच खतरे के विन्दु से उन्नाव-कानपुर में चढ़ गया था। फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया के, जिलाधीशों को इत्तला कर दी है कि गंगा में पानी बढ़ने की वजह से खादर में जो उनके गांव स्थित हैं उनका नुक्सान पहुंचने का अन्देशा है इसलिये उसके लिये तैयार हो जायं।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जो नुक्सान का अनुमान है जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार एक लाख, दो हजार मकान गिरे हैं, जिनका नुक्सान हुआ है। और १०,१५,००० आदमी उस से प्रभावित हुये हैं और गांव का तादाद जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी तादाद २,७१५ है। इतने गांवों पर असर पड़ता है। और रकबा ५,९०,००० एकड़ है। ११३ आदमियों की मौत हुई, जानवरों की तादाद ११४६ है।

डिप्टी कमिश्नर उन्नाव ने १८ तारीख को गवर्नमेंट से चाहा कि उनको मोटर बोट्स दे दिये जायं, क्योंकि जो मामूली नाव हैं उनसे वह तेज धार होने की वजह से मदद नहीं कर सकते। मिलिटरी अथारिटीज से हमने सहायता मांगी और उन्होंने ४ मोटर बोट्स २४ घंटे के अन्दर सड़क के रास्ते उन्नाव पहुंचा दीं। अध्यक्ष महोदय, एक बरेली के मित्र ने और कुछ सहारनपुर के मित्रों ने यह दरख्वास्त की थी कि सीमेंट और टान शीट्स वहां के जिलों को ज्यादा भेज दी जाय ताकि लोगों को मकान बनाने में आसानी हो, तो इस तरह के अहकामात दे दिये गये।

ग्रेचुइट्स रिलीफ के अन्तर्गत ३,६५,००० रुपया इन १६ जिलों को दिया गया और १४,७३,६०० रुपया तकावी में दिया जा चुका है। इस तकावी में वह रकम भी शामिल है जो एक्ट १२ के मातहत हमने इनको इस मुसीबत के आने से पहले दे दी थी। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जिलाधीशों ने अपनी फर्म डिमांड्स, कि कितने रुपये की उनको जरूरत है यह वह बता नहीं पाये हैं। कुछ थोड़ा बहुत बतलाया है, उसके मुताबिक यहां से दे दिया गया है, बल्कि उस से ज्यादा भी कहीं जिलों को दे दिया गया है।

५ अक्तूबर को इस गवर्नमेंट को इस मुसीबत का मुकाबला करने में, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं इलाहाबाद की मिलिटरी अथारिटीज और देहली की मिलिटरी अथारिटीज ने खास तौर से मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर में मदद की। मुजफ्फरनगर में कई रोज के लिये

[श्री चरण सिंह]

भीषण परिस्थिति पैदा हो गयी। ५ अक्तूबर को जमुना ने बढ़ना शुरू किया और ६ अक्तूबर को एक गांव खाली करा लिया गया। ७ अक्तूबर को दो दर्जन गांव पानी से घिर गये और उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। तो ९ अक्तूबर को इंजीनियर्स की तरफ से दरख्वास्त की गयी कि ४ मोटर बोट्स दें और वह १३ अक्तूबर को भेज दीं और कुछ गांवों को १६ को इमदाद भेज सकें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गांव रह गये कि जहां ये मोटर बोट्स भी नहीं पहुंच सकती थीं। तो फिर यहां से एयर हेडक्वार्टर्स जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं उनसे दरख्वास्त की गयी और उन्होंने अपना एक डकोटा दिया और ४ हजार पौंड आटा, गुड़ और नमक उसके जरिये उन गांवों को पहुंचाया गया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली ने भी बुलन्दशहर के कुछ गांवों की इमदाद की जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। उसकी तफसील में यहां जाना बेकार है। अब अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह सदन मुझसे सहमत होगा अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के सम्बन्ध में एयर हेडक्वार्टर्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिलिटरी एथारिटीज एंड इलाहाबाद और डिप्टी कमिश्नर, देहली के तईं।

जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में कृत संशोधन

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ (४) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८ १९/१—अ— १०४२—५५, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५५, जिससे जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५३—५४ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्र

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५३—५४ के वार्षिक प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी स्मृति-पत्र सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस के लिये एक दिन मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष—इस विषय के ऊपर मैं समझता हूं कि पहले भी प्रतिवेदन आ चुका है। तो इस प्रतिवेदन के ऊपर उस वक्त निर्णय होगा जिस वक्त कि वह सदन के सम्मुख आ जायगा तभी यह बात तय होगी।

भूमि संरक्षण मंडल के लिए ३ व्यक्ति निर्वाचित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ की धारा ३ के अनुसार भूमि संरक्षण मंडल, के लिये ३ व्यक्ति निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ की धारा ३ के अनुसार 'भूमि संरक्षण मंडल' के लिये ३ व्यक्ति निर्वाचित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इस प्रस्ताव के अनुसार मैं आज नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि नियुक्त करता हूं और उस के लिये ३ बजे तक समय रहेगा। नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा आज ही सायंकाल ४ बजे तक हो जा'गी। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल, यानी २२ अक्तूबर को १२ बजे दिन तक रहेगी। निर्वाचन की तिथि और स्थान यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किये जायेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विवाद जारी होगा।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करीब तीन दिन से प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या प्रगति हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी क्या योजनायें हैं इस पर बहस हो रही है। इसके पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं हमारे नियोजन मंत्री जी से हमारी कुछ शिकायत है और वह शिकायत इसलिये है कि माननीय मंत्री जी ने जब गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास अपनी पहली स्कीम भेजी जो कि ७२० करोड़ रुपये की थी, उस समय उन्होंने हमसे यह कहा था कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की स्टैंडर्ड प्लानिंग कमेटी है उसके सामने वह इस स्कीम को रखेंगे परन्तु आज तक माननीय मंत्री जी उस पर सोये हुये हैं और वह दिल्ली भी हो आये, पहली स्कीम बदल भी गयी और रुपया भी कम मिला, लेकिन बावजूद इन सब बातों के, उन्होंने आज तक इस कमेटी को अपने कांफीडेंस में नहीं लिया है।

आज जो हमारे सामने पंचवर्षीय योजना रखी गयी है, जिसमें ३१७ करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह हमारे सामने केवल कागज पर ही स्कीम है लेकिन आज तक हमें यह पता नहीं है कि किस तरह से यह रुपया खर्च होगा और कहां खर्च होगा, सिर्फ माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में और इस पुस्तक में यह लिख दिया है कि हम लोग स्टेट में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करना चाहते हैं और इसके लिये हम इतने करोड़ रुपया खर्च करेंगे और यह पता नहीं चल सकता कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कैसे कायम होने वाली है? इस किताब को यदि मैं देख कर कहूं तो मैं इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना न कह कर यह कहूं कि यह नेक्स्ट इलेक्शन कांग्रेस का प्लान है तो इसमें कोई गलती नहीं करूंगा।

पहली मर्तबा जब पहला प्लान एक्जीक्यूट हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि यह कोई प्लान नहीं है जैसे-जैसे रुपया आता रहा हम खर्च करते रहे, इसलिये इसको प्लान का नाम देना ठीक नहीं होगा। अब इसी तरह से इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रुपया खर्च होगा। कहीं बिजली में, कहीं सड़क में, कहीं उद्योग-धंधों में, कुछ टूरिस्ट्स पर और कुछ रुपया काटेज इंडस्ट्रीज पर खर्च होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसको इलेक्शन प्लान कहने के लिये तैयार नहीं हूं। बल्कि इलेक्शन स्टंट कहने के लिये तैयार हूं। यह जनता के लिये एक इलेक्शन स्टंट है। इससे सूबे में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम होने वाली नहीं है। मैं जानना चाहता हूं और गढ़वाल के रहने वाले हमारे साथी चन्द्रसिंह रावत जी जानना चाहते हैं कि इस प्लान में गढ़वाल में बिजली पहुंचने वाली है या नहीं। कहीं और कुछ काम होने वाले हैं या नहीं। हमें पता नहीं है कि क्या होगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

आज हमसे कहा जाता है कि यह पीपुल्स प्लान है, इसके माने तो यह हैं कि जनता को धोखा देना है। इसी विभाग ने और हमारे मंत्री जी ने सारे जिलों के अन्दर ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी बना रखी है। चाहे वहां नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स हों या न हों, चाहे कम्युनिटी ब्लाक्स हों या न हों। जहां पंचायत का एक सरपंच होता है वहां यह कमेटी बनी हुई है। आज तक मंत्री जी ने एक भी ब्लाक डेवेलपमेंट कमेटी के सामने इसको नहीं रखा है। अगर यह पीपुल्स प्लान है तो जो जिस एरिया से ताल्लुक रखता है वहां की इन कमेटियों को मालूम होना चाहिये कि हमारे इलाके की तरक्की के लिये यह प्रोग्राम रखा गया है। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम टैक्स वसूल करने के लिये कैसे पब्लिक से कह सकेंगे। मैंने परसों कहा था कि फायनेन्सेज कहां से आयेंगे तो मंत्री जी डर गये, हिचक गये, कि टैक्स लगायेंगे। आखिर डर की क्या बात है, आप को रुपये की जरूरत होगी और आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और कहेंगे कि रुपया कहां से आयगा तो यह कह दिया जाय कि पहले इलेक्शन हो जाने दिया जाय फिर देखा जायगा तब तो मैं समझता हूं कि आप जनता को गलतफहमी में डाल रहे हैं और हमसे कहा जाता है कि विरोध करते हो। जब जनता को यह मालूम हो जायगा कि यह प्लान उनकी भलाई के लिये है और इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो टैक्सेज देने के लिये तैयार न हो। पर यह बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकारी अफसरों की मोटरें दौड़ने के लिये और सरकारी एक्स्ट्रा वैगेन्स के लिये रुपया देने के लिये कभी तैयार नहीं है। यह बात मैं साफ़ कह देना चाहता हूं। हम रुपया देंगे, इकट्ठा किया जायगा लेकिन मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वह यह कि गवर्नमेंट आफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन कहता है कि आपकी टैक्सेशन कैपैसिटी कितनी है उसको आप बतलाइये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन में जो टैक्सेशन की बिना पर रुपया बांटा गया है यह बिलकुल गलत चीज है। हमारा प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रदेश है और टैक्सेशन में हम बम्बई का मुकाबिला कभी नहीं कर सकते जहां कि बड़े बड़े कल और कारखाने हैं। अगर उस हिसाब से हमको रुपया बांटा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के साथ यह बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। अभी हमारा प्लान ३२५ करोड़ रुपये का है। आगे इसे कुछ और बढ़ाने के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है और शायद इसका कुल टोटल ३७० करोड़ रुपये का हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से कहूंगा कि वह इस बात पर जोर दें कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जो रुपया डिस्ट्रिब्यूट होने जा रहा है २,२०० करोड़ रुपया, उस में से आबादी के हिसाब से भी हमको उसका १/६ हिस्सा मिलना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी ने जो थोड़ा सा रुपया मिला है उसके लिये कह दिया कि बहुत रुपया मिला और बहुत सी और बातें कह दीं। लेकिन मैं यह भी साबित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का एलेक्शन प्लान किस तरह का है। अभी हाल ही में माननीय नियोजन मंत्री हमारे यहां एक चुनाव के सिल-सिले में गये थे। हमारे यहां प्रचार हुआ कि माननीय नियोजन, स्वास्थ्य, खाद्य और उद्योग, चारों चीजों के मंत्री आ रहे हैं। एक ही मंत्री इन चारों के बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा बेचारों को। आप की गाड़ी का सामान एक खड्ड में गिर गया लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहां बड़े आराम के साथ आ गये। लेकिन जब माननीय मंत्री जी वहां गये तो वहां उनको कुछ बातें देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उनसे यह तो सम्मीद नहीं कर सकता कि वे किसी को रुपया न दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह बड़े दानी हैं, जब जरूरत होती है और मैं कहता हूं तो मुझे रुपया दे देते हैं, लेकिन वहां एलेक्शन के मौके पर उन्होंने अपनी तरफ से दो आदमी खड़े कराये। उन्होंने कहा कि हमको रुपये की जरूरत है और मंत्री जी ने कहीं कुछ, कहीं कुछ दिया। एक जगह २०० रुपये दिये, साढ़े १२ हजार रुपया अस्पताल को दिया। तो मैं आपका यह कार्य एलेक्शन के सिलसिले में उचित नहीं समझता। माननीय कमलापति जी अल्मोड़े गये थे वहां उनके साथ

इंजीनियर्स चलते थे इरिगेशन के। वहां के एक गांव में उनको मानपत्र भी दिया गया जिसमें बताया गया कि हमको पानी की बड़ी कमी है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह एलेक्शन स्टंट है।.....

श्री अध्यक्ष——लेकिन यह व्यक्तिगत हो रहा है।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)——क्या एलेक्शन का गुस्सा प्लानिंग पर उतारा जायगा?

श्री अध्यक्ष——उसी के रोकने के लिये मैं संकेत कर रहा हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय मंत्री जी ने कहा कि पानी जरूर मिलेगा लेकिन कांग्रेस को वोट देना। ऐसी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहीं। जब एलेक्शन हो रहा हो, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सड़क बनवा दी। क्या माननीय मंत्री जी अपने घर से पैसा लाये? अगर वह कहते कि हमारी हुकूमत ने बनाई, हमारे प्रान्त ने बनाई तब तो मैं उसको मान लेता। वहां माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी भी गये थे। उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी। उनकी स्पीच की लोगों ने बड़ी तारीफ की। उन्होंने वहां के लोगों को खूब समझाया। लेकिन जब हमारे व्रजभूषण मिश्र जी वहां गये...

श्री अध्यक्ष——यह कोई तरीका भाषण का नहीं है। यह बिल्कुल व्यक्तिगत आक्षेप हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं प्लानिंग पर ही आ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह हमको समझायें कि यह जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनने जा रही है इसको हमें किस तरह से पता चलेगा? इसको किस तरह से हम समझें? क्योंकि न तो मैं परकैपिटा इन्कम को समझता हूं और न किसी और चीज को। मैं देखना चाहता हूं कि यदि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, योजना नहीं थी तो ठीक है कि सिंचाई के लिये नहर खोदी गई, सड़कें बनाई गयीं। इसी तरह के और काम भी हुये उनसे मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आज हमारे सामने आ रही है उसमें किस तरह से हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम होने जा रही है। वह माननीय मंत्री जी हमको समझाने की बातें करें। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को जो तजुर्बा कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन० ई० एस० ब्लाक के अन्दर हुआ उसको हम माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहते हैं, उससे उनको सबक मिलेगा और वह कुछ सीखेंगे। मैं यह नहीं देखना चाहता कि हमारे उत्तर प्रदेश की किसी तरह से बदनामी हो। गवर्नमेंट आफ इंडिया यह कहने न पाये कि उत्तर प्रदेश के लोग नालायक हैं और इतना रुपया उनको दिया गया था वह खर्च नहीं हुआ या गलत तरीके से खर्च हुआ। बहुत सी बातें जो मैं इस सदन में कहता हूं वह अखबारों में छपेंगी और उससे उत्तर प्रदेश की बदनामी होगी। इसलिये मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट की वर्किंग देखी गयी है और एन० ई० एस० ब्लाक की वर्किंग देखी गयी है उससे आपको तजुर्बा हासिल करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि आपने इनमें तजुर्बा हासिल किया तो हम जो १८ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं वह ठीक तरीके से खर्च होगा। यदि आप उससे तजुर्बा हासिल नहीं करेंगे तो आप गलती में पड़ जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, काटेज इंडस्ट्रीज की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। क्या काटेज इंडस्ट्रीज होंगी इसके विषय में कुछ तो माननीय मंत्री जी बतावें काटेज इंडस्ट्रीज

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के लिये रा मैटीरियल कहां से आयेगा। मैं जब इस किताब को पढ़ता हूं तो मैं यह देखता हूं कि हमारे फारेस्ट प्रोड्यूस के लिये, जंगलात के डेवलपमेंट के लिये कोई रुपया इसमें नहीं रखा गया है। थोड़ा सा रुपया स्वायल इरोजन के लिये इसमें रखा गया है। जहां तक हमारे फारेस्ट का सम्बन्ध है जब तक आप फारेस्ट को और फारेस्ट प्रोड्यूस को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको रा मैटीरियल प्राप्त नहीं हो सकता। हमको सेमल की लकड़ी की जरूरत होती है। हमारे पहाड़ों में सेमल की लकड़ी नहीं मिलती है। उसको हमें सी० पी० से मंगाना पड़ता है तब हम अपने यहां बरेली की दियासलाई की लकड़ी की जरूरत पूरी करते हैं। हमारे यहां रेजिन और टरपेन्टाइन बहुत अधिक हो रही है लेकिन उसको फारेन कन्ट्रीज में भेजा जाता है। लाखों लोग रेजिन निकालने के काम में लगे रहते हैं और बहुत लोगों को रोजगार रहता है लेकिन आज सरकार उस काटेज इंडस्ट्रीज की बात को बन्द करने जा रही है। वह इसलिये कि पेड़ हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं और उनसे बहुत ज्यादा माल निकलता है। बरेली की फैक्टरी उतने माल को अश नहीं कर सकती है इसलिये यह रेजिन निकालने का काम बन्द किया जा रहा है। हम कहते हैं कि काटेज इंडस्ट्रीज का यह काम तो केवल एक ब्वायलर लगाकर किया जा सकता है। हमारे यहां लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि काटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिये रेजिन दिया जाय। इससे हमारा उद्योग-धंधा बढ़ेगा। लेकिन इसको माननीय मंत्री जी करने के लिये तैयार नहीं होंगे। वह कहेंगे कि बरेली की फैक्टरी जो टरपेन्टाइन की है वह कौन सी कम है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें टूरिस्ट के सम्बन्ध में कही जाती हैं कि उससे पहाड़ी एरिया की तरक्की होगी। यह पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले लोगों से कहा जाता है। वहां पर टूरिस्ट की योजना के लिये २५ लाख रुपया दिया गया है और वह ५ वर्ष में दिया जायगा। अगर देहरादून को भी उसमें शामिल किया जाय तो एक लाख रुपया प्रति जिला पड़ता है। वहां पर ओमनी बस सर्विस चलायी जायगी। २, ४ मकान भी बनाये जायेंगे और यह रुपया इसमें ही चला जायगा। इससे क्या टूरिस्ट्स का फायदा होगा और क्या पर्वतीय प्रदेश के लोगों का फायदा होगा यह समझ में नहीं आया।

काटेज इंडस्ट्रीज के बाबत मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कोआपरेटिव की बहुत बातें करते हैं तो आपने कोआपरेटिव के कामों को डेवलप करने के लिये कौन सा रास्ता निकाला है? क्या यह कोआपरेटिव मूवमेंट को तरक्की देना है कि थोड़े से सीड स्टोर खोल दिये जायं और कुछ कोआपरेटिव सोसाइटी कन्ज्यूमर के लिये खोल दी जायं। उनमें जो बदनामी होती है उसको मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके डेवलपमेंट के लिये क्या आपके पास काम नहीं है? आप उनको तरक्की करने का मौका क्यों नहीं देते जब कि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्रीज को यहां पर बुला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप कोआपरेटिव की मूवमेंट को बहुत तरक्की दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव को डेवलप करके आप अपने यहां बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं? मैं माननीय मंत्री जी के खोखलेपन को इसलिये कह रहा हूं कि इसमें सचाई या सिंसियरिटी नहीं है। आपको पहले इंडस्ट्री कायम करना चाहिये लेकिन आप तो पहले ही जनता से रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं। इंडस्ट्री रहेगी तो इतने काफी लोग इसमें लगेंगे और उनको फायदा होगा। वहां जो कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं उनको आप इकट्ठा कीजिये, उनको पूंजी दीजिये, उनको सब्सीडी दीजिये तभी वह वहां पनप सकती हैं। मगर एक बात है इलेक्शन के मौके पर आपको जो रुपया कैपिटलिस्ट्स से मिल सकता है वह कोआपरेटिव सोसाइटीज से नहीं मिल सकता। आप सोचते हैं कि अगर कोई कैपेटलिस्ट आ जायगा तो १५ लाख रुपया दे देगा।

श्री अध्यक्ष—आप नीयत पर हमला कर रहे हैं। आपको इन्सिन्युयेशन नहीं करना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मंत्री महोदय की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय को इलेक्शन का एक्सपर्ट जरूर समझता हूं।

***श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आज हमारे नियोजन के वाद-विवाद का अन्तिम दिन है। यहां बैठ कर, जो बड़े-बड़े भाषण हुए उनको सुनने की चेष्टा कर रहा था। और मुझे उस समय एक ऐसी बात ध्यान में आयी कि मैंने सोचा कि जब कभी आप अवसर देंगे, मैं अपने विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उनके व्याख्यान ने मुझे एक चीज सिखा दी और वह यह कि कहने के लिये कुछ न होते हुए भी किस प्रकार से आदमी दो घंटे तक बोल सकता है, इसकी जीती-जागती मिसाल उनका व्याख्यान था। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सदन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में, स्वाधीन देशों के इतिहास में क्या कोई ऐसा स्वतंत्र नागरिक हुआ जो मुल्क की परतंत्रता के जमाने के सपने देखा करता है। जिसकी राष्ट्रीयता इतनी मुर्दा हो गयी हो, जीका पानी इतना मर गया हो कि स्वतंत्रता के ज़माने में भ' परतंत्रता की कथा कहने लगा हो। क्या कोई ऐसी चिड़िया होगी जो सोने के पिंजड़े से निकल जाने के बाद भी उस सोने के पिंजड़े के लिये रोती हो। कल विरोधी दल के माननीय नेता कुछ तालिकायें पढ़ रहे थे और वह उस समय की और उन कामों की जो कि अंग्रेजों के ज़माने में हुए थे। मैं श्रीमन्, क्या बताऊं मुझे ऐसा लगा कि कहीं माननीय सदस्य उसको सुन कर इतने उत्तेजित न हो जायं कि उनसे क्षमा मांगने लगें, कि पराधीनता के सपने ईश्वर करे आप देखें हम नहीं देखना चाहते, हम तो पंचवर्षीय योजना में विचरण कर रहे हैं। जब माननीय सदस्य पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पूंजीवाद की बात भी करते हैं। पूंजीवाद पंचवर्षीय योजना के साथ नहीं चल सकता। वामपक्षी लोग शायद १८ वीं सदी के इंगलैण्ड में रहने वाले (लासोफेरे) की पालिसी को मानने वाले हैं। किन्तु, २०० वर्ष से वामपक्षी दल पूंजीवाद के विरोध में नियोजन का पक्ष ले रहा है। लेकिन नियोजन ही एक ऐसी चीज है जो पूंजीवाद का सही उत्तर है। पूंजीवाद कभी भी कंट्रोल्ड एकोनामी को पसन्द नहीं करता और न उसमें जिन्दा रह सकता है। अगर पूंजीवाद प्लानिंग में पनप सकता होता तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका में, आस्ट्रेलिया में और कनाडा में प्लानिंग चालू होती। प्लानिंग तो उन देशों में पायी जाती है जो सोशलिस्टिक ऐकोनोमी में विश्वास करते हैं, वही लोग प्लानिंग की योजनायें बनाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। मैं वामपक्षियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्लानिंग के इतिहास को पढ़ें। उनका यह सोचना भी भूल होगी कि इस प्लानिंग का जन्म रूस से ही हुआ। समाज बदल जाता है, समाज की परिपाटी बदल जाती है कार्ल मार्क्स ने तो डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरियट को ही आधार माना है लेकिन इस प्रकार के स्टेट कंट्रोल की थियोरी सिडनी वैब ने भी संसार के सामने रक्खी जो आज के समाजवाद के नेता थे। लेकिन सिडनी वैब के समाजवाद को जमाने ने छोड़ दिया है। जी० डी० एच० कोल ने जो लिखा है उसे भी आप पढ़ लें तो उनकी बात समझ में आ जायगी। उन्होंने लिखा है कि वहां प्लांड एकनामी होगी वहां पूंजीवाद नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं और निवेदन कर दूं कि कंट्रोल्ड इकनामी की बात जहां करते हैं वहां प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में सब से बड़ी चीज है कि सही प्लानिंग करने वाला होना चाहिये। कुछ सदस्यों ने

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

इधर के और उधर के इसकी शिकायत की। किसी ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लिये कहा, किसी ने असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये कहा कि इसको प्लानिंग के सम्बन्ध में बहुत काफी ऊहापोह करने का मौका मिलना चाहिये। आज तक कहीं भी प्लानिंग ऐसा कभी नहीं हुआ, प्लानिंग का इतिहास इसके विरुद्ध है और विरुद्ध इसलिये है, मेरे समाजवादी भाई फेबियन सोसाइटी की थेसिस को पढ़ लें। आर्थर लूई ने लिखा है—

"The plan cannot be made by the people or Parliament or by the Cabinet, it can be made only by the Officials."

और इसके साथ ही श्रीमन्, एक बात और निवेदन कर दूं कि आज जो गवर्नमेंट की बड़ी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने यह किया, वह नहीं किया, मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेंट की सब से बड़ी विजय है कि उसकी इतनी आलोचना होती है। आलोचना को मैं इसलिये विजय कहता हूं कि मेरे समाजवादी भाई समाजवादी थेसिस के द्वारा इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं—

"When Government is doing a few things, we can look into its work".

अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा काम करती है तो हम उसको देखकर, परख लेंगे।

"But if Government does every thing, even it cannot look itself."

लेकिन यदि वह सभी काम करती हैं तो सरकार अपने को नहीं कंट्रोल कर पाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेलफेयर स्टेट बनाना हमारा काम है। और आलोचना करना तथा उसके काम को आगे बढ़ते जाना ही इस बात का द्योतक है कि सरकार वेलफेयर स्टेट की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन मैं इतना और कहना चाहता हूं कि आखिर पूंजीवाद के माने क्या है? कई इधर-उधर के सदस्यों ने कहा कि सरकार पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। कहां है पूंजीवाद इस देश में, जिस देश में ५ लाख रुपये की आमदनी वाले सिर्फ लगभग १२५ आदमी रहते हों, जिस देश में गवर्नमेंट प्रति ५ लाख रु० की आमदनी में सिर्फ ९४ हजार रु० छोड़ कर बाकी इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त कर लेती हो, उस देश में पूंजीवाद कहां रहा?

दूसरी बात यह है कि ५ लाख रुपये में ९४ हजार छोड़ कर जो गवर्नमेंट ले लेती है उस पर भी केन्द्रीय सरकार की आमदनी जो इनकम टैक्स के जरिये होती है १९५ करोड़ रुपये से घटते घटते १७० करोड़ रह गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह पूंजीवाद का परिणाम है? इसके सिवा जो हमारे देश के कारखानों के शेयर थे उनको भी देख लीजिये। वेस्टर्न जर्मनी में जहां शेयर की कीमत १०० थी वहां उसकी कीमत ९४० हो गयी, फ्रांस में जिसकी कीमत ९ थी सन् ४६ में, उसकी कीमत २४० हो गयी, और हमारे भारतवर्ष में जिन शेयरों की कीमत केवल ६६ थी आज केवल ८० हो गयी है। तो ऐसी हालत में जब शेयर के दाम बढ़े नहीं तो फिर कैपिटलिज्म कैसे बढ़ा? मैं पूछना चाहता हूं कि और देशों का हिसाब लगाया जाय तो उनकी तुलना में १९३९ में जिन औद्योगिक शेयरों की कीमत प्रचलित मूल्य के अनुपात से उनकी अवहेलना के लिये फ्रान्स में जिसकी कीमत १०० थी उसकी कीमत १२४ हो गयी तो इतना अन्तर क्यों है, कि भारत में जिसका मूल्य ४५ हो गया है इतना उद्योग धंधा कम क्यों हुआ है। इतना कम हो जाने पर भी कहां पूंजीवाद है और किस आधार पर कहां से रुपया लाकर हम अपने देश की प्रगति कर सकते हैं? लेकिन एक बात और बढ़ जाती है कि हमारे मित्र आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। आंकड़ों के बारे में उनको कोई विश्वास नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोड़ दें भारत के आंकड़े को, और भी तो देश हैं जहां कि पंचवर्षीय योजना लागू है पोलैण्ड एक कम्युनिस्ट देश है, वहां भी पंचवर्षीय योजना लागू है, वहां उनकी सन् ४७ से ४९ तक एक योजना चली और ४९ से ५५ तक दूसरी योजना चली। उन दोनों योजनाओं में चीन में भी जिसका बड़ा नाम है उनकी सन् ५२ से ५७ तक की योजना है

यानी ५ साल की योजना है। मैं चाहता हूं कि जो इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले सज्जन हैं वह अगर इन दोनों योजनाओं का अध्ययन करें तो उन योजनाओं के आंकड़ों के अध्ययन के बाद एक नई जानकारी उनको होगी कि उन दोनों में एक ही मद के भिन्न आंकड़े मौजूद हैं। वह उन दोनों रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अन्तर को देखें, केवल पढ़ने से काम न चलेगा, उनको समझने की भीजरूरत है। जब यह कहा जाता है कि परकैपिटा आमदनी सन् ४६ में यह थी और अब इतनी रह गई उस समय कहने वालों को यह ध्यान नहीं रह जाता कि जो परकेपिटा इनकम लगाई जाती है वह उसके पहले के मूल्यों के इंडेक्स के अनुसार लगाई जाती है, सन् ५३–५४ में जो परकेपिटा इनकम लगाई गई तो सन् ५२–५३ के इन्डेक्स पर आधारित होती है। अगर इन्डेक्स में अन्तर हुआ तो परकेपिटा में भी अन्तर जरूर आ जायगा। पोलैण्ड के भी उसी हिसाब किताब को अगर हमारे मित्र देखेंगे तो मालूम होगा कि वहां भी सन् ५४–५५ में परसेंटेज में अन्तर हो गया है। अगर आप वहां के बिजली प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखें तो उसमें भी आपको विशेष अन्तर मिलेगा, जब कोई वैसी बात नहीं है। यह एक फैक्ट है। अगर आप गल्ले को ही देखें तो सन् ४६–४७ में उत्तर प्रदेश में ७८ लाख टन गल्ला पैदा किया गया और सन् ५३–५४ में १२४ लाख टन गल्ला पैदा किया गया। कितना बड़ा अन्तर है। इसी तरह से नेशनल इनकम की बात है। सन् ४६–४७ में १,३३८ करोड़ थी और वह राष्ट्रीय इनकम १,५०८ हो गई ३१ मार्च, ५५ को, यह अन्तर क्यों हुआ और आंकड़े में कहां अन्तर होता है। हरएक चीज को जरा समझने की कोशिश करनी होगी।

एक बात और है, बहुत कुछ कहा जाता है कि हिसाब-किताब योजना का ऐसा है कि देश का दुख मुसीबत बढ़ जाता है लेकिन सोचना यह है कि वह योजना कोई भी नहीं हो सकती जिसमें देश को दुख और मुसीबत न उठानी पड़े। इसी जुलाई सन् ५५ में पेकिंग की एक नेशनल कान्फ्रेंस में चीन के डिप्टी मिनिस्टर फूचीन ने एक भाषण दिया था वहां की पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में और उन्होंने अपने उस भाषण में ३ खास बातें कही थीं। पहली बात उन्होंने कही थी कि सन् ५० से जब से हमने अपनी यह योजना शुरू की तब से २ वर्ष तक हमारे धन का बहुत वेस्टेज हुआ, बहुत अपव्यय हुआ। जो माननीय सदस्य चाहें उनको मैं उनका वह भाषण पढ़ा सकता हूं वह देख लें। उन्होंने साफ कहा है कि २ वर्ष तक धन का बहुत अपव्यय हुआ है। दूसरी बात उन्होंने उस भाषण में यह कही कि हमें अभी आगे बढ़ना है और जिस प्रगति तक दूसरे माडर्न कन्ट्रीज पहुंच चुके हैं वहां तक पहुंचने में हमें अभी ५० साल लगेंगे। यह उनके शब्द हैं भाषण के। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि हमें अभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टच नहीं करना है और साथ ही एक चौथी और बात कही कि कैपिटल गुड्स के बारे में जिनको धन की आवश्यकता होगी उनको हम सहायता देंगे और यहां पर ऐग्रीकल्चर के लिए ८ प्रतिशत धन दिया गया और उसी चीन में सन् ५६ में १,६३२ लाख टन पैदावार हो जायगी और सन् ५७ तक १,९३२ लाख टन तक वह पहुंच जायंगे और इतने पर भी वह ८ प्रतिशत दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उद्योग-धंधों के लिए वह ८९·४ परसेंट दे रहे हैं जिससे केपिटल गुड्स तैयार होगा। यह मैंने आपके समक्ष कम्युनिस्ट योजना की बात कही।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—यह आंकड़े आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—यह मैं कहां से पढ़ रहा हूं, यह मैं आप को क्या बताऊं, आप मेरे पास आवें तो मैं आपको पढ़वा दूं, इस प्रकार आपको नहीं समझाया जा सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग लिख गए हैं कि ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी नहीं समझा पाते, वह बात हो तो मैं क्या समझा सकता हूं ?

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

एक बात मैं और निवेदन कर दूं अपने मित्रों से चाहे वह इधर के सदस्य हों या उधर के हों, कि डाक्टर फूचीन ने एक और बात कही थी और वह भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी हिसाब-किताब हो लेकिन "Major sin in a country is shirking the hardship" इसलिये जो साहब कहते हैं कि उन को कठिनाई न हो उनसे मैं कहता हूं कि जो योजना काल में कठिनाई न होने की बात कहते हैं उनकी राष्ट्रीयता गिर गई है। वह कहते हैं कि कठिनाई से मुंह मोड़ना मेजर सिन है, बड़ा भारी पाप है। हार्डशिप न हो, कष्ट न हो यह कहना बड़ा भारी पाप है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस बड़े पाप के भागी बनें। मैं नहीं चाहता कि हम यहां रूस के ताना शाही के स्वप्न देखें लेकिन कितने नियोजन करने वाले इस प्रदेश में हैं। मेरे मित्रों ने देखा होगा कि रूस में सरकार को नियोजन करने के लिये एक क्लास बनाना होता है प्लानर्स का, उनको एक नामिस्ट कहते हैं। उनकी पिछली जनसंख्या ८ लाख थी रूस के सेंसस के अनुसार। लेकिन कितने इस देश और इस प्रदेश में हैं जो यह कहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम नियोजन में भाग लेंगे, केवल कल्पना से काम नहीं चलता ठोस तत्वों से काम लेना पड़ेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बहुत से व्याख्यान अपने भाइयों के सुने और उनको सुनने के बाद तलाश कर रहा था कि एक बार कम से कम कोई तो यह कहे कि हमें गर्व है कि हमने इतने सालों में इतना इतना कर डाला लेकिन मुझे यहां पर यह देख कर दुःख हुआ कि किसी को भी इतना कहने का साहस नहीं रहा, न किसी में यह गर्व आया। मुझे एक घटना याद आती है। मुझे बर्लिन के उस भाग की याद आती है जो रूस के अधीन है। पूर्वी जर्मनी में जहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रूस का जोड़े का परदा पड़ा हुआ है। उसमें सम्भवतः इसी ६ सितम्बर की बात है। मैं दोपहर के समय कुछ मित्रों से बातें कर रहा था। उसमें एक समाजवादी थे भारत के, एक उसमें जनसंघी थे भारत के और उसमें एक कम्यूनिस्ट थे भारत के और सब के सब रूसी सरकार के खर्चे से वहां उत्सव में बुलाये गये थे। उन सब ने वहां पर कहा कि एक बात तो है। यहां आकर घूमने के बाद तो एक बात पता लगता है और सब कुछ देखने के बाद हमारी यह धारणा होती है कि हमारे भारतवर्ष ने जितना कर दिया है उस पर हमें गर्व होना चाहिये। यह उन्होंने सबने बर्लिन में कहा था। उस समय मैंने सोचा कि सम्भवतः हमारे देश के रहने वाले जब बाहर आते हैं उसी समय उनको गर्व नहीं होता होगा, उनको अपने देश के भीतर रहते हुये भी गर्व होता होगा लेकिन मैं यहां तलाश करता-करता थक गया। कोई नहीं यहां ऐसा दिखाई देता। यहां तक कि तीन हफ्ते हुये अशोक मेहता जी जो इस देश के एक बहुत बड़े एकनामिस्ट हैं, उन्होंने हमारे नियोजन की काश्मीर में प्रशंसा कर दी थी। उस प्रशंसा का भी एक शब्द यहां किसी के मुंह से नहीं निकला। किसी नियोजन को चलाने के लिये और सफलतापूर्वक चलाने के लिये और एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है लेकिन जहां प्रेरणा की आवश्यकता होती है वहां पर उसके साथ-साथ हमें कुछ ठोस तत्वों पर भी विचार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किस सीमा तक हम अपने नियोजन को ले जा सकते हैं।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और पहले ही मान चुका हूं कि नियोजन के बारे में हर एक अपनी राय दे करके पक्की योजना नहीं बना सकते हैं। किन्तु कोई दो-तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर हर एक आदमी अपनी बात को गवर्नमेंट से कहने का अधिकार रखता है कि तुम हमसे पैसा मांगते हो तो अपने खर्चे को किस सीमा तक फैला सकते हो। यह हमको देखना होगा कि कहां तक तुम अपनी गाड़ी को चला सकते हो। यह कम से कम बड़े अफसोस की बात है। ३८ और ३९ के जमाने में लाहौर में एक आल इंडिया स्टेटिस्टिकल कांग्रेस हुई थी। उसमें महान् एकनामिस्ट प्रोफेसर महालोनोविस का जो मतभेद मेरा था, उस समय से आज भी कायम

हूं। मैं सैम्पुलिंग में बिलीव नहीं कर सकता और फिजीकल एकानामी में मैं आज भी उतना विश्वास नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि हमें और भी गौर करना पड़ेगा और इस विचार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज ५६ सौ करोड़ की योजना बन रही है और उसमें उत्तर प्रदेश का भाग ३३६ करोड़ है। अब इसमें हमको ८ सौ करोड़ रुपये के करीब कर्जा भी लेना पड़ेगा और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के अनुसार केवल ४ सौ करोड़ रुपये तक ही ऐसी अधिक रकम है जिसको हम टैक्स से निकाल सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमन् राष्ट्रीय इन्कम में ८ फीसदी तो उस टैक्सेशन से इन्कम होती है। तो ८०० करोड़ के लिये १ हजार करोड़ को डेफिसिट फाइनेंसिंग होते हुये भी यानी १००० करोड़ निकालने के बाद ८ सौ करोड़ रूपये हमें कर भार से कैसे लेना चाहिये। श्रीमन्, इतना हम कर भार से नहीं दे सकते। इतना कर भार हम पर लादा नहीं जा सकता और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के अनुसार ४ करोड़ से अधिक वसूल भी नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में नियोजन के लिये ३३६ करोड़ रुपये हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश के इतने मंत्री केन्द्र में हैं इसलिये शायद उत्तर प्रदेश के बारे में वह लोग वहां बड़े जोरों से बातें नहीं कर सकते।

हमें यह भी अफसोस है कि हमारे देश में जो केन्द्रीय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज हैं वह उत्तर प्रदेश के लिये एक या दो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग देने के लिये भी वे तैयार नहीं हैं लेकिन और जगहों में वह खोली जाती हैं। हमारा जो शेयर है वह और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम पड़ता है लेकीन मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से अनुरोध करना पड़ेगा कि वह अपने खर्चों को नियंत्रित करे। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने महकमों के अधिकारियों को बढ़ाने से क्या ज्यादा अच्छा काम होता है? ६ चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग में रखने से क्या काम अच्छा हो जायगा? उनका नाम चाहे महाप्रमुख क्यों न रख दिया जाय तो क्या काम अच्छा हो जायगा? बिजली में ऐड़ीशनल चीफ रख देने से काम अच्छा हो जायगा? या शिक्षा में एडीशनल रखने से मैं यह समझता हूं कि नियोजन में बैठ कर सब सच्चे दिल से सहयोग और साथ दें लेकिन यहां ऐसी आदत हो गई है हमेशा हर एक की बुरी चीज को देखना और समझने की। एक चीज मुझे याद आती है। एक साहब ने कहा---

"दर्दे दिल इतने दिनों से है कि आदत हो गई।
अब जरा तस्कीन होती है तो घबराता हूं मैं।"

इस घबराहट की जरूरत नहीं है। हम साहस और प्रेरणा से चल रहे हैं। समूचा संसार इस बात को जानता है जो लोग बाहर गये हैं, वे जानते हैं कि भारत ने प्रगति की है और यह सब सम्मिलित प्रयत्न और सम्मिलित प्रेरणा से हुआ है।

श्री गेंदा सिंह---प्वाइन्ट आफ आर्डर। अभी परिपूर्णानन्द जी ने अशोक मेहता के सम्बन्ध में एक गलत बात कही। उन्होंने कहा कि अशोक मेहता जी ने उत्तर प्रदेश की योजना की प्रशंसा काश्मीर में की। मैं समझता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत जिम्मेदार हो उसे गलत ढंग पर पेश कर दिया जाय, जिसका कोई प्रमाण उनके पास न हो, अनुचित है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें आज्ञा दें कि वे इस बात को वापस लें या आप कोई निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं है। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कुछ जानते हों वे अपने भाषण में इसका प्रतिवाद करके स्पष्ट कर दें। यह बात हो सकती है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अशोक मेहता जी ने कई बार इस योजना की तारीफ की है। अलीगढ़ में भी ताईद की थी। लेकिन वे सोशलिस्ट हैं कहां, वे कंपेटलिस्ट हैं। इसीलिये छोड़ कर चले आये।

श्री गेंदा सिंह---अशोक मेहता जी के सामने तो इस प्रदेश की योजना रखी थी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---आप तो अपनी बात कह चुके।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वराज्य मिलने के बाद इस देश ने जितनी तरक्की की है वह काबिले तारीफ है और जिस तरह से दूसरे आंकड़ों के, दूसरे किसी स्टेटिस्टिक्स और डेटा के पहली पंचवर्षीय योजना बनायी गयी थी जैसे कि सब लोग इसे मंजूर करते हैं वह योजना न हो कर जो काम उस वक्त हाथ में थे उन सबको पूरा करने की कोशिश की गयी। उसमें क्या-क्या गलतियां हुयीं, किस तरह से वह योजना पूरी हुयी वह सब देखने की बात है। अगर आज हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखें तो इस ख्याल से हमको देखना चाहिये कि उसमें जो गलतियां हुईं वे आगे न हों ताकि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना ज्यादा कामयाब हो। जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा हमारे प्रदेश को सेंटर से जो सहायता मिली है वह बहुत कम रही और दूसरे सूबों ने हमसे कहीं ज्यादा सहायता ली। हमको पहले तीन साल में १०.८ करोड़ मिला जबकि दूसरे बहुत से सूबों को हमसे ज्यादा मिल गया, जिनकी आबादी हमसे बहुत कम थी। केवल यही नहीं, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने खुले करीब २२ के और जिन पर ८४-८५ करोड़ रुपया खर्च हुआ, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यू०पी० में एक भी कारखाना नहीं खोला। कहा जाता है कि यहां रा मेटीरियल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर उन सब कारखानों की लिस्ट को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि कुछ चीजें ऐसी जरूर थीं जो यहां खुल सकती थीं और जिनके लिये मैटीरियल की ऐसी जरूरत नहीं थी जो यहां मुहइया न हो। पहले तीन साल में जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें जो मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुआ है करीब २५४ करोड़ रुपये के उसमें एक पाई भी यू०पी० में नहीं खर्च हुई। अब यह कहा जा सकता है कि अगर यू०पी० को कम हिस्सा मिला एक भी कारखाना नहीं बना, मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ तो हो सकता है कि यू०पी० की हालत अच्छी थी इसलिये बैकवर्ड एरियाज को रुपया दे दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बात भी ठीक नहीं है। हमारे यहां जो बजट पर खर्च होता है वह १२.८ रुपया पर हेड है। पंजाब में १८.३ रुपया है, आसाम में १८.८ रु० है बम्बई में २० १ रु० है पश्चिमी बंगाल में २१.५ रु०, बजट में इतना खर्च होता है। उसमें डेवलपमेंट में कितना खर्च होता है वह भी मैं आंकड़े आपके सामने रख दूं। यू०पी० में पहले तीन सालों में जो डेवलपमेंट पर खर्च हुआ वह ९.३ रु० पर हेड है, मद्रास में १२.५ रु०, पश्चिमी बंगाल में १४.८ रु०, बम्बई में २३.५ रु० पर हेड था। हमने सवा नौ रुपया खर्च किया की इंसान, पहले तीन सालों में और बम्बई ने साढ़े २३ रुपया खर्च किया। इस तरह से दूसरे सूबों से हम पिछड़े हुये हैं और फिर भी हमको केन्द्रीय सहायता बहुत कम मिली।

शिक्षा के बारे में मैंने एक दफा अर्ज किया था फिर उसको एक इशारे के तौर पर दोहरा देना चाहता हूं। जहां तक सेंसस का ताल्लुक है, सेंसस रिपोर्ट में सारे देश के छः हिस्से किये हैं। यू०पी० उसमें एक हिस्सा है। और लिटरेसी के दृष्टिकोण से हम सबसे पिछड़े हुये हैं। हमसे सारा देश आगे है। अगर हर एक स्टेट को अलग लें तो १९ स्टेट्स हम से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं। हमारा नम्बर बीसवां आता है। उसके बाद बच्चों की तादाद बढ़ रही है। प्राइमरी एजूकेशन में विद्यार्थियों की तादाद घट रही है। जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं वह हैं २८ लाख, १९५१-५२ में थे, १९५२-५३ में २७ लाख और १९५३-५४ में २६ लाख हो गये। प्राइमरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एजूकेशन में बच्चों की तादाद घट रही है और बच्चों की आबादी बढ़ रही है। हम बीसवां हिस्सा पहले हैं और संविधान ने हम पर यह पाबन्दी रखी है कि इतने अरसे के अन्दर दस साल के अन्दर फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन हो। १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों में फैलाया जाय। १४ वर्ष की आयु तक मैं समझता हूं कि बच्चा जूनियर हाई स्कूल तक पहुंच सकता है। उसमें कितना खर्चा होगा, उसको हम पूरा कर सकेंगे या नहीं, इस सम्बन्ध में मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब नहीं मिला।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एजूकेशन के मामले में पिछली बार मैंने यह प्रश्न किया था कि जो डाइरेक्टिव प्रिंसयल कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है जिसके मुताबिक Free and compulsory education up to the age of 14 जो कि जूनियर हाई स्कूल तक की एजूकेशन के माने हैं उस डाइरेक्टिव को अगर पूरा किया जाय तो हमको करीब-करीब ५० करोड़ रुपये की और जरूरत होगी। उसमें अब फीस भी अगर माफ कर दी जाय तो वह रकम और बढ़ती जायगी और जो सहुलियतें कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान का फ्रेम देना चाहता हूं कि फ्री बोर्डिंग हाउसेज हों गरीबों के लिये, फ्री लौजिंग का इतजाम हो, बोर्डिंग का इंतजाम हो, ट्यूशन का भी इंतजाम हो न सिर्फ प्राइमरी एजूकेशन में बल्कि पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज तक इसका इंतजाम हो तो यह रकम और बढ़ जाती है। इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कलासेज, यूनिवर्सिटीज इनका खर्चा अलग रहा और यूनिवर्सिटियां भी बढ़ती जायंगी, खर्चा भी बढ़ जायगा, टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो यह तमाम स्कीमें हैं इनको २३ करोड़ रुपये में कैसे पूरा किया जायगा या २८ करोड़ में, यह अभी हमारी समझ में नहीं आया। वह डायरेक्टिव प्रिंसिपिल पूरा हो सकेगा; हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले शिक्षित जितना कि इस वक्त कम है उससे कुछ ऊपर उठ सकेगा, यह प्रश्न पिछली बार हुआ था और मैं चाहता हूं कि इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान में क्या उसकी रूप रेखा होगी यह अगर हमको समझा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें बहुत दिक्कतें हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज, यह पुस्तिका है "उत्तर प्रदेश थ्रू फीगर्स" १९५१ से १९५४ तक। सन् १९५१–५२ में वार्षिक लाभ हुआ ८९.२८ लैक्स आफ रुपीज, १९५२–५३ में ३८.५५ हुआ और १९५३–५४ में ३१.३४ हुआ। यानी दो साल के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो मुनाफा हुआ वह ८९.२८ लाख से घटाकर ३१.३४ हो गया। यह हमारी कोआपरेटिव कौमनवेल्थ की तरक्की की निशानी नहीं है। हमको देखना है और यह क्यों हुआ, इसको आगे कैसे रोका जायगा, यह भी अगर समझ में आ जाय तो ज्यादा अच्छा है।

इंडस्ट्रीज के मामले में हमारी हालत खराब है। बहुत सा रुपया ग्रान्ट्स में दिया गया है, लोन्स में दिया गया। मालूम नहीं कि जिनको ग्रान्ट और लोन दिया गया था उससे कितनी इंडस्ट्रीज अब तक चल रही हैं और कितनी कम हो गयीं, उसका कितना रुपया माफ करना है जो लोन में दिया गया था, यह भी अन्दाज यहां नहीं है। लेकिन इन आंकड़ों से मालूम यह होता है कि जो लेबर इंडस्ट्रीज में थे वह घटते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में। यानी गवर्नमेंट की जो फैक्टरीज हैं उनमें तो लेबर की तादाद बढ़ी। बाकी जो लेबर इंडस्ट्रीज में ऐम्प्लायएड है उसकी तादाद घटती जा रही है। तो सब तरफ हम पिछड़े हुये हैं बैकवर्ड हैं। इसको किस तरह से सेकेंड फाइव ईयर प्लान में पूरा किया जायगा यह समझने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ इस तमाम लिट्रेचर से जो दिया जाता है यह नहीं मालूम होता कि जो रुपया खर्च किया जाता है उसका क्या आधार है, किस तरह से किया जाता है। मिसाल के तौर पर हौसिपटल खोले जा रहे हैं, हास्पिटल गांवों में खोले जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो सब जगह है ही । पहले तहसील हेडक्वार्टर्स में बनाये जायं और जब वहां खत्म हो जायं तब गांवों में बनाये जायं । मेरा यह अन्दाज है कि बहुत सी तहसीलों में नहीं है और गांवों में खुल गया है । उनका कोई प्लान अगर हो और वह समझ में आये तो हम भी लोगों को समझा सकें कि हम इस तरह से चल रहे हैं। इन-इन तहसीलों में अगर अभी नहीं बना है तो आगे चलकर बन जायगा । स्कूल्स हैं उन्हें ग्रान्ट मिलती है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं उनको नहीं मिलती और जिनके खराब होते हैं, उनको मिलती है । तो इसके लिये अगर कोई मेथड बना दिया जाय और वह हमको बता दिया जाय तो हम ज्यादा अच्छी तरह लोगों को समझा सकेंगे कि जो कुछ हो रहा है वह एक ढंग से हो रहा है, कायदे से हो रहा है और अगर आज उनके यहां नहीं हो सका है तो कल हो जायगा ।

इसमें फिर सवाल आता है ह्यूमन मैटीरियल का । प्लानिंग में एक बहुत बड़ी इम्पार्टेन्ट चीज यह है कि सही तरीके के आदमी रिक्रूट हों, वह ट्रेन किये जायं और उनको वह काम एलाट हो । अधिष्ठाता महोदय, मुझे माफ करेंगे अगर मैं एक बात अर्ज करूं कि रिक्रूटमेंट का तरीका जिस तरह से है उसको अगर बदल दिया जाय तो अच्छा है । मेरी अपनी बिल्कुल साफ राय है और मैं कई बार कह चुका हूं अगर सब रिक्रूटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच जायं तो ज्यादा अच्छा है । यह मैं नहीं जानता हूं कि वहां कोई गलती होती है या बेईमानी होती है, यह मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन उसका जो असर पड़ता है वह बिलकुल दूसरा होता है । हम लाख ईमानदारी से काम करें लेकिन अगर हमारे बारे में यह सोचा जाय कि यहां तो बगैर सिफारिश से कोई काम हो ही नहीं सकता तो सारा किया कराया बेकार चला जाता है । पिछली दफा अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ मैं अर्ज करूं सही हुआ हो या गलत हुआ हो, इसके ऊपर कुछ कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । चार प्रेलिमिनरी सेलेक्शन कमेटीज बनीं, दो डिप्टी मिनिस्टर्स दो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज उसके चेयरमैन थे और एक फाइनल सेलेक्शन कमेटी बैठी उसमें एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हुये । मिनिस्टर्स को अप्वाइंटिंग एथारिटीज को चाहे यह ठीक मालूम होता हो कि कौन ज्यादा ठीक होगा लेकिन बाहर की दुनिया, देखने वाला यह समझते हैं कि प्रेलिमिनरी सेलेक्शन कमेटी में अगर डिप्टी मिनिस्टर हो तो फाइनल सेलेक्शन कमेटी में मिनिस्टर को या कम से कम डिप्टी मिनिस्टर को होना चाहिये । मैं यह अर्ज करूं कि यह जो सेलेक्शन हुआ, कम्बख्त ऐसे समय में हुआ जब कि वहां असेम्बली का सेशन चल रहा था । हरएक आदमी के पास सिफारिश कराने के लिये लोग गये । किसी की हिम्मत नहीं कि वह सिफारिश न करे । हरएक ने सिफारिश की । सारा प्रदेश जानता है, जो चुनकर गये, वह भी और जो नाकामयाब होकर गये, वह भी सब यही कहते हैं कि सब कुछ सिफारिश से हुआ है । मालूम हो जाता है कि कौन-कौन सेलेक्शन कमेटी में हैं, सिफारिश करायी जाती है, रिजल्ट आउट होने से पहले टेलीफोन पर बता दिया जाता है कि तुम ले लिये गये । तो आपकी सारी स्कीम एक तरफ और लोगों का यह ख्याल दूसरी तरफ कि जो कुछ भी होता है वह सिफारिश से ही होता है, इससे जो कुछ भी काम हम करते हैं वह सब बेकार हो जाता है । मैं समझता हूं कि यही सिर्फ काफी नहीं है कि जस्टिस की जाय बल्कि यह भी जरूरी है कि जस्टिस लोगों को भी मालूम हो । जो कुछ भी सेलेक्शन यहां हुआ है, उसको अगर कोई अच्छी तरह से देखे तो हरएक आदमी आज यही कहता है जो सेलेक्ट हुआ वह सिफारिश से हुआ और जो नहीं हो सका उसकी सिफारिश नहीं थी । तो राइट टाइप आफ रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी चीज है । गोरवाला कमेटी ने इस पर बहुत जोर दिया है और प्लानिंग कमेटी ने भी गोरवाला कमेटी की यह सिफारिश को माना है । जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है वह अभी हमारे सामने नहीं है लिहाजा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स हैं वह कुछ सबार्डिनेट हैं और उनके मातहत जो हैं वह उनसे बहुत सीनियर हैं । तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि हेड आफ दि प्लानिंग डिपार्टमेंट सीनियर आदमी हो ताकि वह सब से काम ले सकें । हो सके

तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कर दिया जाय । यह भी देखना है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का पूल बन गया है क्या वह ठीक-ठीक फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है । यह सारा जोर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का जो काम करने की तरफ होती है कि कोआपरेटिव सोसाइटी बने या न बने, कोआपरेटिव सोसाइटी का दफ्तर जरूर बन जाय उसका फाउंडेशन स्टोन जरूर रख दिया जाय, यह कहां तक ठीक है? तो इस तरह से डिमांस्ट्रेशन पर कम जोर दिया गया है । आर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यह सोचने की बात है । कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुगुणा साहब की बात को ऐप्रोशिएट किया कि मिनिस्टरी में प्लानिंग होनी चाहिये और कहा कि अगर बिजली के साथ-साथ ऐग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को मिला दिया जाय तो बहुत बोझ हो जायगा । मैं समझता हूं कि एक मिनिस्टर साहब को ४ पोर्टफोलियो दे दिये गये हैं, इसका मतलब है कि वह बहुत बोझ हो जायगा । मैं यह भी समझता हूं कि इस से और ज्यादा बोझ और मिनिस्टरों के ऊपर है और ज्यादा अच्छा हो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास हो ताकि जितने मिनिस्टर्स हैं उन सब का प्लान ठीक हो सके । साथ ही प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई और स्पेंडिंग डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिये । फाइनेंस हो सकता है , जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है , लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट न हों तो ज्यादा अच्छा है ।

इसके साथ अब मैं दो लफ्ज सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बारे में कहना चाहता हूं । कल श्री नौरंगलाल ने कहा कि यहां तो बजट स्पीचेज हो रही हैं । लेकिन मेम्बर साहबान क्या करें । जो लिट्रेचर सप्लाई किया गया है वह सिवाय आंकड़ों के कुछ भी नहीं है । एक छोटी सी किताब है, सेकेंड फाइव ईयर प्लान इसमें सिर्फ यह दिया हुआ है कि इतना खर्चा इस पर होगा , इतना इस पर होगा । तो उसमें मेरी राय यह है कि वह बहुत थोड़ा है और हर डिपार्टमेंट में थोड़ा है । अगर आप कहें कि ३२५ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा, इसी को बांटो, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी । जिस-जिस को जो प्रेजुडिस होगा , उधर खींचना चाहेगा । तो सिवाय इसके कि यह कहा जाय कि यह थोड़ी रकम है, और होनी चाहिये और क्या कहा जा सकता है ? इसमें यह भी पता नहीं है कि यह आये कहां से ? कहां से आयेगी ? कितने टैक्सेज होंगे ? क्योंकि इसके मानी यह हैं कि जब हम इसको मंजूर कर रहे हैं तो इसके लिये क्या टैक्सेज होंगे, यह रुपया कहां से आयेगा, हमारे बजट से कितना आयेगा, सेंटर से कितना आयेगा, यह भी हमें मालूम होना चाहिये । पर यह नहीं मालूम होता । ३२५ करोड़ की इस स्कीम के मंजूर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती, लेकिन जो इसका बटवारा है उसमें ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता । सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जितना रुपया दिया गया है वह थोड़ा है । इसलिये अगर यह कहूं कि इसमें बढ़ा दिया जाय तो इतनी हिम्मत नहीं है लेकिन इस रुपये को कैसे सजेस्ट किया जाय यह कैबिनेट अपने आप तय कर ले ।

मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि सी०डी० देशमुख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं उन्होंने एक बार कहा था कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के आखिर तक हम हर शहर और हर गांव को पानी दे देंगे । मैंने उस वक्त कहा था कि अगर आप आधा भी दे दें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा । अब अगर सेकेंड फाइव ईयर प्लान में सब शहरों और गांवों को पानी दिया जाय और पानी के साथ ड्रेनेज जरूरी है , वाटर-वर्क्स के साथ ड्रेनेज भी होना चाहिये तो साढ़े पांच सौ करोड़ तो अरबन एरिया में और इतना ही रूरल एरिया में रुपया चाहिये । और इस एक हजार करोड़ रूपये में कुल साढ़े पांच करोड़ रुपया है । अब कहां से क्या होगा ? अब हर मिनिस्टर कैसे हर चीज कर सकते हैं हर गांव चाहता है कि हमारे यहां पक्की सड़क आ जाय । हर गांव चाहता है कि हमारे यहां खेती के लिये काफी पानी हो । इसलिये कहीं ज्यादा होना चाहिये, इस पर तो कहने की हिम्मत नहीं है । अब वाद-विवाद हो सकता है यही कि किन सिद्धांतों को लेकर यह प्लान रखा गया जो सिद्धांत कि हमारे प्लानिंग कमीशन ने मांगे थे जिनको लेकर हम चलना चाहते हैं,सोशलिस्टिक

[श्री मोहन लाल गौतम]

पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। जो आखिरी पैरा में दिया हुआ है जो ८९-३० पेज पर है। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता, समय कम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी न करती हो या जिस से कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ जाने में मदद मिलती हो। एक चीज भी मुझे नहीं मिली मिसाल के तौर पर, टैक्सेशन एंक्वायरी कमेटी ने यह कहा कि परसनल इनकम आफ्टर टैक्सेज पर कोई सीलिंग होनी चाहिये। हमने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। ३० गुने से ज्यादा फर्क न हो लोगों की आमदनी में, हम इस तरफ क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान बनायी है, जो सिद्धांत सामने रखे हैं क्या हम उन सिद्धांतों को मानते हैं? हमारी कितनी आमदनी बढ़ी हुयी पिछली प्लान में और कितनी हम अगले प्लान में बढ़ायेंगे यह हमको नहीं मालूम कि कितने आदमियों को हम रोजगार देंगे। ये सब चीजें इसमें नहीं हैं। जो आल-इंडिया प्लान के सिद्धांत हैं उनमें से कितनों को हमने माना है, कितनों को नहीं माना है इसका कोई अन्दाज नहीं मिलता है। कितने आदमियों की बेकारी दूर होगी इसका पता नहीं। कितनी चीजों को कोआर्डिनेट करेंगे इसका हमें कोई अन्दाज नहीं। हमने क्या स्टेप्स लिये हैं जिससे कि ट्रेडिंग और प्राफिट मेकिंग क्लासेज में कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ न हो। इसलिये ज्यादा अच्छा हो अगर हमको यह बता दिया जाय कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बाद यह हालत है, इतना हम पहुंच चुके हैं और इतना पहुंचना चाहते हैं। सोशल जस्टिस इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह से सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी लाना चाहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज को किस तरह से तरक्की देना चाहते हैं और किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। इस सब का कोई अन्दाज हमको इसमें नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि कुछ आइटम्स दिये हुये हैं, रकमें दी हुयी हैं, डिपार्टमेंट्स दिये हुये हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि कहां रुपया कैसे खर्च होगा, किस-किस जगह खर्च होगा, क्या क्या होगा। इन सब वजहों से इस प्लान के बारे में बहुत ज्यादा डिसकस करने से हम मजबूर हो जाते हैं। सड़कें बनेंगी तो उसका आधार क्या होगा, सिंचाई बढ़ेगी तो उसका आधार क्या होगा, स्कूल खुलेंगे तो उसका आधार क्या होगा। अगर इन सब चीजों का हमें अन्दाज हो जायगा तो हममें ज्यादा शक्ति आयेगी, जनता इसमें ज्यादा कोआपरेट कर सकेगी और इस प्लान को ज्यादा सफल बना सकेगी और जितनी यह सफल होगी उससे जनता खुश होगी और हमारे नजदीक आयेगी और हमारा एहसान मानेगी।

अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त हो गया।

मैं देख रहा हूं कि बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। अगर किसी माननीय सदस्य को ऐतराज न हो तो बजाय १५ मिनट के हम १० मिनट कर दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मेरा तो एतराज है क्योंकि कल निवेदन किया गया था कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय। माननीय मंत्री जी से बातचीत हो चुकी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो समय बढ़ा दिया जाय।

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटा के लिये बढ़ा दिया जाय।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता तो अवश्य था कि एक घंटा या दो घंटे का समय दिया जाता मगर मेरी दिक्कत यह है कि आज हैन्डलूम बोर्ड की मीटिंग भी है। वह पहले ३ बजे रखी गयी थी चूंकि पहले ऐसा विचार था कि २० तारीख को ही बहस खत्म हो जायगी। फिर एक दिन और बढ़ा दिया गया। तो आज मैंने उनको ५ बजे के लिये आमंत्रित कर रखा है। कई सदस्य बाहर से आये होंगे। इसलिये मुझे कुछ दिक्कत सी मालूम होती है। मैं अभी अपने पी० ए० से पुछवाता हूं, यदि वह स्थगित की जा सके एक घंटे के लिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ६ बजे तक आप बैठें।

अधिष्ठाता—फिलहाल तो हम ऐसा करते हैं कि हर माननीय सदस्य के लिये १० मिनट कर देते हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले तीन दिनों से जो इस सदन में नियोजन के सम्बन्ध में भाषण हो रहे हैं उनका मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की, उसका विश्लेषण भी करने की कोशिश की, किन्तु मुझे दुख है कि अधिकांश भाषणों से मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, इस सम्पूर्ण नियोजन को समझने में। दरअसल बात यह है कि इस नियोजन को आज की परिस्थितियों के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है। यह कि कल क्या होगा इसको जानने के लिये, आज क्या हमारी हालत है और कल क्या थी और इस नियोजन के पूर्व क्या थी, इन सब बातों के सामने रखने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। नियोजन जो इस देश में चल रहा है अथवा इस प्रदेश में चल रहा है, वह कुछ बुनियादी बातों पर मुनहसिर है, आज और कल क्या स्थिति थी, इस पर मुनहसिर है। नियोजन कोई हवा में प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है, नियोजन आज की परिस्थितियों को सामने न रखकर प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो इस देश में स्थिति है, वह हमारे सामने है। हम सदियों से गुलाम रहे हैं, हमारा आर्थिक ढांचा चकनाचूर हो गया था, और हमारा नैतिक स्तर भी खत्म हो गया था, समाप्तप्राय करीब-करीब हो गया था ।

श्रीमन्, इन सब हालतों को सामने रखकर हमने नियोजन को प्रारम्भ किया था, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी ने न तो इस प्रदेश में और न इस देश में यह हर्गिज नहीं कहा कि इस प्रथम पंच वर्षीय योजना, अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना अथवा पांच योजनाओं के फलस्वरूप भी इस देश में से भुखमरी, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक असमानता समाप्त करके सम्पूर्ण समाज के ढांचे को बदलकर समाजवाद को स्थापित करने में सफल हो जायेंगे ।

श्रीमन्, यह स्वाभाविक है कि जो टारजेट इसमें रखे हैं हम उन तक न पहुंच पायें, गल्तियां होना भी स्वाभाविक है, और जितनी हम उम्मीद करते हैं उन उम्मीदों से कम होना भी स्वाभाविक है, इसलिये यदि हम इस आयोजन में अथवा दूसरे नियोजन में गल्तियां देखने का प्रयास करेंगे अथवा जो नहीं कर पाये हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे तो श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि वह ठीक नहीं होगा। इससे ठीक नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं ।

हमें तीन-चार बुनियादी बातों को देखना चाहिये। पहली तो यह है कि क्या हम इस नियोजन के जरिये जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, उस पर चलने का मार्ग सुविधाजनक और प्रशस्त होता है या नहीं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवाद के आधार पर समाज की रचना करना है। यदि हम समझते हैं कि उसके आधार पर हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है, हमें सुविधा मिली है जिससे हमें ऐसा समाज बनाने में सहायक हो सकते है तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि सारी बुराइयों के बावजूद, सारे ऐब के बावजूद, यह योजना हमारी सर्वश्रेष्ठ योजना है और खामियों के बावजूद भी हम समझते है कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिये ।

श्रीमन्, हम निश्चित रूप से अगर इसको तौलें इस आधार पर तो हम समझते हैं कि सचमुच हम इस योजना के फलस्वरूप उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं जिसके आधार पर हम समाजवादी आधार पर समाज बना सकेंगे। आखिर आज इस भुखमरी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, देहात में कृषि की सुविधा दी जा रही है और आज यह कोशिश की जा रही है कि लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन मुहैय्या हों और लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें और जो मशीनरी है वह भी लोगों के हाथ में आये, इसके अलावा हम गरीबी और अशिक्षा को मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज को विकसित करने का प्रयास समाज को सुन्दर बनाने का प्रयास, समाज में से बुराइयों को दूर करने का प्रयास, यदि समाजवाद की ओर पहला कदम नहीं है तो क्या है ? इसलिये श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण संतोष है कि यह जो नियोजन हो रहा है यह सचमुच ही हमारे मार्ग को प्रशस्त बनायेगा ।

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

दूसरी एक जरूरी चीज, जिसको कि नियोजन में देखना चाहिये वह यह है कि क्या हम इस नियोजन के लिये ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र के और देश के साधनों का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना जो कि हमने रखी है यह समर्थ है कि वह अधिक से अधिक साधनों का उपयोग कर सके? निश्चितरूप से समर्थ है बशर्ते कि हम और हमारे अफसरान और हमारे नेता लोग उन साधनों का उपयोग करने की चेष्टा करें और उनका उपयोग करना चाहें। हमारे देश में दो असेट्स हैं, एक धन और दूसरा श्रम। श्रीमान्, इस बात के बावजूद भी कि पूंजीवाद के पक्ष में कहा गया है और हो सकता है कि बहुत सी चीजें पूंजीवाद के पक्ष में हों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं कि जब तक इस ढांचे का विनाश नहीं किया जायगा, इसको जब तक लाफ, स्टाक ऐंड बैरेल नहीं समाप्त किया जायगा तब तक समाज में न्याय नहीं हो सकता। इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अभी भी हमको उन क्षेत्रों से कर मिल सकता है धन मिल सकता है जहां पर कि आज धन विद्यमान है। हमको जरूर वहां से धन लेना चाहिये। कोशिश करनी चाहिये हमको जरूर वहां से पूंजी लेने की। दूसरी चीज श्रम के संबंध में। श्रम हमारा सबसे बड़ा असेट है इस गरीब मुल्क में और इसलिये हमको इसके लिये एक निर्माण सेना बनाना चाहिये। हम को हर जिले में, हर देहात में, हर नगर में इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी एक निर्माण सेना बना लें। तीसरी बात श्रीमन् यह है जो कि नियोजन के लिये आवश्यक है वह यह है कि हम प्रायरिटीज फिक्स करते हैं या नहीं और वह ठीक है या नहीं। हमें कहां एग्रीकल्चर को प्रारिटी देनी है, कहां उद्योग को, कहां सिंचाई को और कहां स्वास्थ्य को, यह देखना है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस किताब से हमको नहीं मालूम होता है कि प्रदेश के किन हिस्सों में इस सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने किस बात को लिये प्रायरिटी फिक्स की है। मैं चाहता हूं कि अगर वह भी स्पष्ट हो जाता इस पुस्तक से कि कहां पर किस बात के लिये इम्फैसिस किया जा रहा है तो बड़ी सहूलियत हो जाती।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, प्लानिंग के माने जैसा मैं समझता हूं किसी भी मुल्क के नेचुरल रिसोरसेज का एक्सप्लायटेशन है। और वह एक्सप्लायटेशन वहां की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये उसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिये इस्तेमाल करना ही प्लानिंग के माने हैं। तो श्रीमन्, इस परिभाषा से जब प्लानिंग को हम देखते हैं तब हमको बहुत सी बातें कुछ संदेह में डालती हैं। सब से बड़ी बात यह है कि प्लानिंग उस समय तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि जनता का सहयोग उसमें न हो। आज तक का हमारा तजुर्बा यह है कि जो भी प्लानिंग हमारे यहां हो रही है उसमें जनता का सहयोग नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर हम इसी तरीके से चले और जनता का एक्टिव कोआपरेशन हमको नहीं मिला तो हमारी प्लानिंग कितनी कामयाब होगी यह एक बहुत बड़े संदेह की बात है।

दूसरी सबसे बड़ी बात एक यह भी है कि हम प्लानिंग में कुवें बनाते हैं, सुन्दर-सुन्दर हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिजली लाते हैं, किस लिये? यह इसलिये कि हम को यह सब चीजें लानी हैं। बिजली लाना मुल्क के अन्दर हमारा काम है। यह इसलिये कि उससे हम अच्छे नागरिक पैदा करना चाहते हैं। इन सब चीजों के द्वारा हम देश को उच्चतर और ऊंचे स्तर के नागरिक देना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से जब हम प्लानिंग को देखते हैं तो आज जिस पहलू से देखिये उसमें हमारा दृष्टिकोण जो ह्यूमन मैटीरियल का है वह बराबर गिरता चला जाता है। तो फिर इससे साफ जाहिर है कि इस हमारी प्लानिंग के तरीके में न कहीं कुछ कसर जरूर है। तो उसको खोजने का हमको प्रयत्न करना चाहिये और वह कसर कहां है इसको खोजकर इसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्रीमन्, प्लानिंग के लिये शिक्षा एक बहुत अहम चीज है। मैं उस शिक्षा के बारे में कुछ थोड़ा सा यहां पर आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि जहां भी किसी स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये रिकग्नीशन मांगा जाता है तो उसको दे दिया जाता है। आप लखनऊ को ही ले लीजिये कि जहां पर ६०,७० स्कूल हैं लेकिन अगर यहां पर ५ स्कूलों के लिये और रिकग्नीशन मांगा जाता है तो वह दे दिया जाता है यद्यपि लखनऊ की आबादी के हिसाब से यहां के स्कूल पर्याप्त है लेकिन फिर भी रिकग्नीशन दे दिया जाता है। हम इस बात को नहीं सोचते कि अमुक एरिया के अन्दर इतनी आबादी है वहां पर इतने बच्चे होंगे, इतने लड़के होंगे और इतनी लड़कियां होंगी जिनके लिये वह प्लानिंग की जा रही है। उसकी बेसिस पर हम प्राइमरी स्कूल निर्धारित करें, उसकी बेसिस पर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल को रिकग्नीशन देने की नीति हमको निर्धारित करनी चाहिये। आज ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि बड़े-बड़े शहरों में एजूकेशन कंसन्ट्रेट है। बहुत से एरिया ऐसे पड़े हुये हैं कि जहां पर कोई भी एजूकेशन का प्रबन्ध नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि एजूकेशन की प्लानिंग इस तरह से करें कि जिसमें अपनी पूरी आबादी का ध्यान रखा जाय, एरिया की जनसंख्या का ख्याल रहे और वहां की सारी कंडीशन्स को देखते हुये हमें अपनी प्लानिंग निर्धारित करनी चाहिये। इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि एक जमाने में सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने यहां पर स्कूल खोले और वह इसलिये खोले कि वहां पर शिक्षा नहीं थी। उन स्कूलों के द्वारा शुरू में लोगों को अंग्रेजी शिक्षा मिली। उसके बाद वह स्कूल न्यूक्लियस बन गये। वह आवश्यकता के जमाने में स्कूल खुले। मैं जानना चाहता हूं कि आज जुबिली इन्टर कालेज की यहां पर क्या आवश्यकता है? इसको तोड़कर किसी और स्थान में रख दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट स्कूल की क्या आवश्यकता है जहां पर इतने ज्यादा संख्या में स्कूल पड़े हुये हैं? इसको तोड़कर आप ऐसा करें कि वहां पर ले जायं जहां पर शिक्षा नहीं है। वहां पर शिक्षा का प्रचार किया जाय। वहां पर लोग शिक्षा चाहते हैं। आज बहुत से लोग इन जगहों में जाकर वही काम कर रहे हैं जो कि १८५७ में लोगों ने काम किया था। इन स्कूलों में जो रिकग्नीशन दी जाती है उनमें सब्जेक्ट का रिपीटीशन किया जाता है। यह नहीं होता है कि अगर किसी स्कूल को सायन्स की रिकग्नीशन दी गयी है तो वहीं पर दूसरे स्कूल को ऐग्रीकल्चर की रिकग्नीशन दी जाय और फिर सब से अव्वल और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह भी हम देखें कि हमारी शिक्षा का संचालन ऐसे आदमियों के द्वारा हो जो ईमानदार हों। इसमें थोड़ी सी खोज की जरूरत है। जहां पर हम यह समझें कि आदमी ईमानदार नहीं है वहां पर उन आदमियों को हटाकर ईमानदार आदमी रखें ताकि शिक्षा का काम सही तरीके से चल सके।

फिर जब हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहां एग्रीकल्चर के अन्दर गन्ना एक मुख्य साधन है जो कि काश्तकारों को कैश रुपया देने वाली चीज है। इसमें हम यह देखते हैं कि इसके ऊपर कोई तवज्जह नहीं है। गन्ने के बाइप्रोडेक्ट क्या-क्या हैं उनको डेवलप करके बहुत काम किया जा सकता है। गन्ने में बहुत बड़ा हिस्सा खोई का मौजूद रहता है जो कि जला दिया जाता है उससे कोई काम नहीं लिया जाता। यदि अनुसन्धान करके देखा जाय तो इसमें से बहुत सी चीजें कीमती पैदा कर सकते हैं जो कि मैटीरियल के रूप में यूटिलाइज हो सकती है उससे हमारे प्रांत में नई इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं। जंगल हमारी लिये आबादी के हिसाब से कितने होने चाहिये यह सब हमने किया लेकिन जंगल के बाइप्रोडेक्ट की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं हेनरी फोर्ड की एक किताब पढ़ रहा था जो "टू डे ऐन्ड टूमारो" के नाम से थी। हेनरी फोर्ड ने जंगल के एक पेड़ का साइन्टिफिक एक्सप्लायटेशन किया और उसके जो शाख, टहनी और पत्ते बच जाते थे उससे उन्होंने पयूअल गैस तैयार की थी। इस तरह से जो चीज बेकार जाती थी उससे वे लाखों और करोड़ों रुपया पैदा कर रहे हैं। इस ओर मैं समझता हूं प्लानिंग में वास्तविक ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी जंगलों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हे हम नहीं जानते हैं। उनकी तरफ भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

ऐग्रीकल्चरल प्लानिंग में सबसे बड़ी समस्या खाद की है। लेकिन आज की हालत यह है कि किसान लोग गोबर को जो कि खाद के लिये एक विशेष चीज है कंडे बनाकर जला डालते

[श्री भगवान सहाय]

हैं। जब तक इस प्रथा को नहीं रोका जायगा तब तक आप ऐग्रीकल्चर की कोई भी प्लानिंग करें कामयाब नहीं होगी। हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिये कितने फ्यूअल की आवश्यकता है इसके ऊपर भी हमारा अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। फिर हमारे यहां कास्ट हिन्दूज में यह प्रथा चली आती है कि मरने के बाद शव को जलाया जाता है। इसमें लाखों मन लकड़ी हर रोज खर्च हो जाती है। लेकिन बाहर के देशों के लोग इस विषय में भी साइंटिफिक मीन्स को इस्तेमाल करते हैं। जब आप इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं तो अधिक नहीं तो कम से कम बड़े-बड़े शहरों में बिजली के क्यूनरल पायर्स लगा दिये जायं। इससे मैं समझता हूं कि लाखों मन लकड़ी की बचत हो सकती है तथा उसको हम दूसरे कामों में ला सकते हैं।

मैं एक और खास बात की ओर माननीय गुप्ता जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल माननीया चन्द्रवती जी ने माननीय मंत्री जी से विशेषरूप से प्रार्थना की थी कि वे औरतों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि क्या इस मुल्क में कोई भी ऐसी औरत नहीं है जिसके ऊपर वे विश्वास ला सकते हों।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, दो दिन से इस सदन में नियोजन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं अब थोड़ी सी बातें श्रीमन् के सामने निवेदन करूंगा और आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण उनको सुनने की कृपा करेंगे। मान्यवर, मुझे यह कहने में हिचक नहीं होती और निस्संदेह यह ठीक है कि किसी भी देश के पास एक योजना है और उसको पूरा करने के लिये, उसको कार्यान्वित करने के लिये, उसके पास साधन हों और उसको भलीभांति कार्यान्वित किया तो सफलता की आशा हो सकती है। मान्यवर, मैं इस वादविवाद में यह कहने का साहस रखता हूं कि बहुत से क्षेत्रों में आपने अपने लक्ष की पूर्ति की परन्तु दुख के साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि बहुत से क्षेत्रों में और बहुत से स्थानों में आप पूर्णतया सफल नहीं हुये। मान्यवर, देहात के रहने वालों को यह आश्वासन दिया गया था, यह बताया गया था कि भारत एक सुन्दर देश होकर रहेगा। कहने वाले तो इसको इन्द्रपुरी बनाना चाहते थे लेकिन यह बात वास्तविकता से दूर रही। मैं यह मानता हूं कि आप ५ सालों में इसकी रूपरेखा एक दम से नहीं बदल सकते। और भी देशों में समय लगा है, उसके लिये समय की आवश्यकता होती है। परन्तु दुर्भाग्यवश आज जब कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी हो रही है और दूसरी योजना के लिये हम तत्पर हो रहे हैं, उस समय हमको यह कहना आवश्यक हो जाता है कि जो हमको आश्वासन दिया गया था, उससे हम बहुत दूर रहे। श्रीमन्, आज इस सदन के निवासी अधिकतर देहातों में रहते हैं यह निस्संदेह है परन्तु उनके लिये इस सरकार ने क्या किया है? उनकी आमदनी में क्या वृद्धि हुई है यह सब को अच्छी तरह से मालूम है। यह हो सकता है कि परकैपिटा इन्कम शहरों में बढ़ सकी हो लेकिन देहातों में, मैं आपके आंकड़े पर भरोसा करूं या जो आंखों से देखता हूं? यही नहीं बल्कि देहातों में जो लोग, जिनके सर पर छतें थीं, जो दोनों वक्त खाना खा सकते थे या जिनके तन पर कुछ वस्त्र थे उनको लेने में आप जरूर कुछ आगे बढ़े रहे। परन्तु जिनके लिये आपने यह किया और जिनके लिये आपने यह सब कुकर्म किया है उनके लिये क्या कर रखा है, यही एक देखने की चीज है। यदि आपने उन लोगों को कुछ फायदा पहुंचाया होता, उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ होता, वे किसी भी क्षेत्र में अग्रसर और सफलीभूत हुये होते तो हम समझते और सोचते कि ठीक है, सरकार ने जो किया वह प्रजातांत्रिक नियमों के अनुसार "दि ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट पीपुल" किया। श्रीमन्, आपने जो किया वह यह है कि जहां पर देहातों की हालत कुछ अच्छी रही उसको तो बरबाद करने में सफल रहे परन्तु उनकी स्थिति को सुधारने में पूर्णतया असफल रहे हैं। श्रीमन्, यही नहीं कि सरकार के सामने एक भूत है, बल्कि अनेकों भूत हैं जिनसे भयभीत होकर वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो रही है। एक नया सिद्धांत हमारे सामने रख रहे हैं और वे कहते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के लिये जो कुछ भी उनको करना होगा उसे करने के लिये तैयार हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैंने यह भी सुना कि एक तरफ पुकार सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी की है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी आश्वासन देने में माननीय मंत्री जी पीछे नहीं होंगे ताकि उनके धन को लेकर आगे बढ़ें और देश के हित के लिये, जनता के हित के लिये उसको लगावें। यह भावना जो है वह ठीक है, उद्देश्य बहुत सुन्दर है परन्तु वास्तविकता से बहुत दूर है। यह मैंने माना कि अगर वे पूंजी का विनाश नहीं चाहते हैं, यदि वे मानव समाज में रहते हुये, पाशविकता के अन्दर पशु नहीं हैं तो अपना वादा जो उन्होंने किया है उनको पब्लिक समझती है कि यह ठीक है। लेकिन अपनी जगह पर वे रहेंगे इसको मैं नहीं मानने का। इस सदन के माननीय सदस्य जो यह समझते हैं कि यह उचित हो सकता है, यह मान सकते हैं और इनका इसके ऊपर विश्वास भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ चल सकते हैं लेकिन जब वे कांग्रेस के काम न आवेंगे तो आप ही उनका विनाश कर सकते हैं। जहां पर दूसरे भाई जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, उनको न मौका मिल सका है न मिल पायेगा, इनको भी आप साफ कर देंगे। मैंने यह माना, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपोजीशन की तरफ से बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जो उचित नहीं हैं। यह मैंने माना कि यह कहना कि अंग्रेज हमसे काबिल थे, हम से होशियार थे, गलत होगा। अगर ऐसी बात हम कहते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा सिर नीचे झुकता है और हम अपने उस गौरव और स्वाभिमान को भूल जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं तो था नहीं उस समय लेकिन मैंने सुना कि माननीय परिपूर्णानन्द ने यह भी कहा कि हमने जो उन्नति और तरक्की की है उससे विदेशियों को संतोष है। यह सुनकर संतोष हुआ परन्तु कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी इसी सदन में यह कह रहे थे कि यह हमारा पहला अवसर था, गलतियां हो सकती हैं और अनुभव की न्यूनता के कारण हमने उस तरह से प्लानिंग न किया हो जिस तरह से होना चाहिये था। तो यह गलती किस की थी यह तो वह खुद समझें और सदन समझे। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि प्लानिंग दुनिया में कोई नई चीज नहीं थी, रूस में पहले यह काम हो चुका था, आपके सामने वहां की एक रूपरेखा थी, एक नकशा था जिससे आप को सहायता मिल सकती थी और गलतियों में कमी हो सकती थी। मैं ज्यादा न कह कर अपोजीशन की तरफ से आप को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक राष्ट्र के कल्याण की बात है उसके लिये हम किसी के आगे नहीं तो किसी से पीछे भी रहने को तैयार नहीं हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना की ४ साल की रिपोर्ट और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट प्लान हमारे सामने हैं। जो कुछ लिटरेचर हमको दिया गया है उससे तो निश्चिततापूर्वक अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम उसमें कहां तक सफल हुये हैं। यह तो अवश्य है कि जिस वक्त प्रथम योजना प्रारम्भ हुई उस समय से हमारी दशा में सुधार हुआ है लेकिन आज कोई प्रापर बेलेंस शीट हम अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का अपने सामने नहीं रख सकते और न इतनी सामग्री हमारे पास है क्योंकि उसके लिये हमें जानना होगा कि कितने रिसोर्सेज का हमने उसमें प्रयोग किया और उसका क्या परिणाम हुआ। आज जो आंकड़े हमारे सामने नेशनल डिविडेंड के हैं वह सन् ५४ तक के हैं और इनवेस्टमेंट्स के सन् ५५ तक के हैं और जो प्लान पर खर्च हुआ है उसके अलावा और भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है वह भी इस में शामिल नहीं है। जो नेशनल डिविडेंड में वृद्धि हुई है उसमें दोनों का ही योग है इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि हमने जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह हमारे लिये हर्ष की बात है और उससे जनता में एक नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है; लेकिन हमें जानना यह है कि प्रथम योजना को कार्यान्वित करके हम किन नतीजों पर पहुंचे और उनके आधार पर द्वितीय योजना की कैसी रूपरेखा बनाना चाहते हैं। पहला सवाल तो जो हमारे सामने है वह इन्सटीट्यूशनल सेटअप का है। हमने सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने की बात कही है उसका सेटअप हमारा कैसा होगा उसकी रूपरेखा हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। उसके २ आस्पेक्ट हो सकते हैं। जहाँ तक उसके डिस्ट्रीब्यूटिव आसपेक्ट का संबंध है मैं समझता हूं उस ओर हमने

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

प्रयास किया है और प्रोग्रेसिव ली स्टीप इन्कमटैक्स (progressively steep incometax) डेथ ड्यूटीज, जमींदारी अबालीशन इत्यादि के द्वारा हमने समाज में समानता स्थापित करने की चेष्टा की है और उसमें हमें सफलता भी मिली है। लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसके लिये हम क्या करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन का जहां तक संबंध है यह अभी तक के अनुभव से नहीं कह सकते कि वह बहुत सफल हुआ है। न तो हम यह कह सकते कि जितना रुपया हमारा नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज में लगा उसमें हमको रिटर्न अच्छा मिला उसके मुकाबिले में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में मिलता है। न हम यह कह सकते हैं कि उसमें एफीशियेंसी ज्यादा रही है और न हम यह कह सकते हैं कि लेबर की हालत ज्यादा सुधरी, न उनकी तनख्वाह ही बढ़ी और न उनका इंवेस्ट ही बढ़ा। जब नेशनलाइजेशन की यह हालत है तो हमें सोचना होगा कि इसमें क्या दोष है और उसका कैसे निवारण हो सकता है। इस संबंध में यदि हम दूसरे देशों की ओर देखें, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़कर और देश जो है वहां पर जो आज जो कि बड़े-बड़े सोशलिस्ट्स हैं उनको भी डिसइलूजनमेंट (desillusionment) हो रहा है। जी० डी० एच० कोल जिनका परिपूर्णानन्द जी ने जिक्र किया उनके कथनानुसार Socialism is either dead or dying उन्होंने न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशनल में एक सवाल प्रस्तुत किया है :

"How much of socialism survives in Western Europe?"

और उसका उत्तर इस प्रकार दिया है :

"In France, in Belgium and in Holland, hardly anything; for socialist parties these are supported by only a fraction of the working class and show no signs of increasing their influence and are clearly helpless in the matter of changing the social order. Social democracy is stronger in Western Germany but even there it does not seem likely to win a majority of the electors to its side. As for Britain the contents of recent Labour programmes furnish enough evidence that the Labour Party has very little notion of what it wants to do next and is basing its hopes of electoral victory on its opponents mistakes."

इंगलैन्ड में अभी हाल ही में मारगेट में एक लेबर पार्टी कांफ्रेंस हुई जिसमें दो रिजोल्यूशन्स आये थे। एक तो बैंक्स को नेशनलाइज करने का और दूसरा बिना कम्पेंसेशन के स्टील टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग और बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वगैरः को नेशनलाइज करने का। और श्रीमन्, वह दोनों रिजोल्यूशन्स गिर गये और निश्चय किया गया कि पब्लिक ओनरशिप का रोल आगे क्या होने वाला है उसको वह अब से लेकर ५८ तक पार्टी डिसकस करेगी। तो हमारे सामने जो नेशनलाइजेशन की बात है उसका हश्र तो यह है। समय बहुत कम है लेकिन मैं मसानी साहब, जो किसी जमाने में बड़े आर्डेन्ट सोशलिस्ट रहे हैं उनका भी जिक्र कर देना चाहता हूं उनको भी इसी तरह का डिसइलूजनमेंट है और वह भी कहते हैं कि जर्मनी में तो यह नारा है कि "Turn the people and the money loose and they will make the country strong".

अधिष्ठाता—आप जो कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसका हिन्दी में तर्जुमा कर दें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—आपके जितने आदमी और रिसोर्सेज हैं उनको दीजिये छोड़ दो और वे सब अपने आप देश को मजबूत बना लेंगे। मैं यह नहीं कहता कि कैपिटलिज्म ही इसका आलटरनेटिव है। लेकिन हमें इस संबंध में विचार अवश्य करना है। दूसरा इस्टीट्यूशन कोआपरेटिव्ज का है। अभी आपको बतलाया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कोआपरेटिव्ज की हालत हो रही है वह यह है कि जहां उनकी आमदनी पहले ८६ लाख थी वहां अब ३१ लाख रह गई है। मैं समझ सकता हूं कि इसका कारण शायद यह भी था कि पहले कंट्रोल के जमाने में उनको कुछ आर्टिफिशियल ऐड्स दी गई। पर जो आंकड़े हमको प्रथम पंच-

वर्षीय योजना के मिले हैं उनसे बड़ी निराशा होती है। पहले मल्टिपिल पर्पज सोसाइटीज को लीजिये। ८,३७४ सोसाइटीज में ३८,०४७ मेम्बरशिप रही यानी करीब पूरी-पूरी प्रति सोसाइटी नहीं पड़ती। इसी तरह से एग्रिकल्चरल सोसाइटीज में १७ से ज्यादा नहीं पड़ती और इंडस्ट्रीयल सोसाइटीज जिन के बल पर इंडस्ट्रीज चलाने की सोचते हैं उनकी संख्या ८२ और मेम्बर्स की संख्या ९३५ रही यानी १२ से भी कम है। इस कोआपरेटिव स्ट्रक्चर पर हम किस तरह से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। इस दिशा में हमारी तैयारी बिल्कुल अपूर्ण है।

दूसरी बात जो आती है वह ह्युमैन मेटीरियल की है। ह्यूमैन फैक्टर का हमारा सबसे बड़ा फैल्योर रहा है। हम अच्छे व्यक्ति नहीं पैदा कर सके और करते भी कैसे? परिवार जिसके द्वारा हम लिविंग फार अदर्स का पाठ पढ़ते थे, कुछ कर्त्तव्य की भावना जागृत होती थी उसका विघटन होता जा रहा है। रिलीजन का प्रभाव भी हमारे जीवन में निरन्तर कम होता जा रहा है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम लोगों में एक नई भावना पैदा कर सकते हैं। आज तो राइटस् की खींचातानी में सब आदर्श नष्ट हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम कैसे ऐसे आदमी पैदा कर सकते हैं जो देश के लिये मरें और देश के लिये जियें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं न केवल प्राइमरी बेसिक शिक्षा सब लोगों को मिल सके बल्कि अच्छे और सस्ते साहित्य की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। यह सर्वसाधारण को नाममात्र के मूल्य में उपलब्ध होना चाहिये और इसका प्रकाशन सरकार को सबसीडाइज करना चाहिये दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है विशेष कर कम्युनिस्ट देशों में वहां इनडौक्ट्रीनेशन (indoctrination) हैं लेकिन हम तो अपनी संस्कृति और साहित्य को भी भुलाये हुये हैं यदि यह कार्य हमारे मुख्य मंत्री ने नहीं किया जो हमारी संस्कृति के पूर्ण रूप हैं तो यह कब होने वाला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, चार दिन से इस प्लानिंग पर जो बहस चल रही है उसमें इस सदन के ---जहां तक मैं समझ पाया हूं---ज्यादातर माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने माननीय नियोजन मंत्री की ही हां में हां मिलाने की कोशिश की। श्रीमन्, उन सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नियोजन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय प्रकट की है।

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य के केवल १० मिनट हैं। भूमिका में ज्यादा समय नष्ट न करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सदन में यह कहा था कि जब हमारे सम्मानित सदस्य इस नियोजन के सबध में इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो जनता के मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि सरकार कुछ नहीं करती है। श्रीमन्, यह बात सही है कि जनता के मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है लेकिन श्रीमन्, मैं आप के द्वारा नियोजन मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जनता की जैसी भावनायें हैं और सम्मानित सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की हैं क्या उसमें अन्तर है? यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या जनता का पंचवर्षीय योजना से स्तर बढ़ा है, उसको रोजी मिली है, उसको खाना कपड़ा मिला है? माननीय श्रीपति सहाय ने कहा कि हर गरीब आदमी को जिसको एक धोती मुश्किल से मिलती थी। आज वह दो धोती पहनने लगा है। मैं तो अचम्भे में पड़ता हूं। इस तरह की बातें सुनकर ताज्जुब होता है। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन झोपड़ियों में, उन हरिजनों के घरों में जाइये, जो हरिजन चैत के महीने में गोबरहा खाता था...

अधिष्ठाता—काफी शोर हो रहा है। जरा शान्ति होनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडे—आज भी वह गोबरहा खाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि बाजारों में कुछ गल्ला भरा पड़ा हो, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है खास कर उन लोगों की नहीं बढ़ी है जो खतिहर मजदूर हैं। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बनारस, जौनपुर, बहराइच, गोंडा जितने पूर्वी जिले हैं मैं आप के द्वारा नियोजन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर इन जिलों में नियोजन का काम हुआ है, कुछ ट्यूबवेल लगाये गये, कुछ नहरें खोदी गयीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो खेतिहर मजदूर हैं जिनकी जिन्दगी किसानों में काम करके कटती है उनके लिये उन्होंने क्या किया ? मैं जानना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन पूर्वी जिलों में खेतिहर मजदूरों की हालत बदतर होती चली जा रही है। सरकार ने जो पिछली योजना चलायी और जो योजना आगे चलाने वाली है उसमें कोई स्थान उनके लिये नहीं है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने विरोधी दल के नेता से जवाब तलब किया कि स्वतंत्रता के युग में परतन्त्रता की बात नहीं होनी चाहिये। यह बात सही है कि स्वतंत्रता के युग में अगर किसान को खाने को नहीं मिलता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, हमारे गांवों में ८०, ८५ फीसदी घरों में हमारी मातायें और बहनें, अर्द्ध नग्न अवस्था में रहती हैं, उनके तन दिखलायी देते हैं। ऐसी अवस्था में परिपूर्णानन्द ही स्वतंत्रता के गीत गा सकते हैं। पर जिस हरिजन को दो दिन के बाद खाने को मिलता है, जिसको मजदूरी नहीं मिलती है, वह स्वतंत्रता का गीत नहीं गा सकता है।

मैं कहता हूं कि यह जो पंचवर्षीय योजना है और जो आज पंचवर्षीय योजना की कीमतें इतनी तेजी के साथ आंकी जा रही हैं उसमें आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी जो समस्यायें हमारे प्रदेश की हैं वह हल होने वाली नहीं हैं। श्रीमान्, आप जानते हैं कि बहुत से देशों में सहकारिता के आधार पर सारे उत्पादन के सामान एकत्रित किये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा वितरित किये जाते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था के साधन पूंजी, भूमि, श्रम विनमय और वितरण हैं। इन साधनों पर यदि सरकार द्वारा नियोजन नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि सरकार नियोजन नहीं कर सकती है और नियोजन के मानी यह होते हैं कि किस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो, उतना सामान उसको मिल जाय और जितना सामान वह पैदा करता है उसकी खपत हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन उत्पादन बढ़ेगा, सस्ती आयेंगी, उसके बाद क्या उत्पादन करने वाला गरीब आदमी उन सामानों को खरीद सकेगा ? नहीं खरीद सकेगा। जहां पर हमें और सारे देश की जनता को यह आवाहन दिया जाता है कि सहयोग कीजिये, सहयोग नहीं हो सकता है। प्लानिंग कमेटियों की ओर ध्यान दें। जिले की प्लानिंग कमेटियां पार्टी बन्दी पर बनी हुई हैं। तीन चार साल प्लानिंग कमेटियों को बने हुये हो गये हैं। कुछ लोग गांव सभा से आये हैं, उनमें जो उपसमितियां बनी हैं, उनमें भी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रखे गये। कांग्रेस दल की ही भरमार प्लानिंग कमेटी में है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सारे जिलों में कांग्रेसी ही लोग भरे पड़े हैं। श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात बताता हूं। माननीय फूल सिंह जी बैठे हुए हैं। माननीय फूल सिंह ने एक सड़क के बारे में हमारे जिले की प्लानिंग कमेटी को दो-दो बार लिखा। लेकिन वहां की प्लानिंग कमेटी के सत्ताधारी, जो कांग्रेसी हैं, वह नहीं चाहते हैं कि विरोधी दल के क्षेत्र में कोई काम हो। नहरें जहां बनी वहीं ट्यूबवेल लगे हैं, और वहीं पर कुयें भी बन रहे हैं। अब तक सरकार का जो कारनामा रहा है वह कोई नियोजित नहीं रहा है, ऊटपटांग रहा है और मनमाने ढंग से रहा है।

एक बात और कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि हम बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं माननीय नियोजन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो ट्यूबवेल्स लगाये,

कुछ बिजली पैदा कर दी, नहरों का कुछ निर्माण किया, स्कूल कालेज हमारे प्रदेश में जनता के सहयोग से बहुत तेजी से खुले, इतना काम होने के बाद हमारे प्रदेश में बेरोजगारी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। श्रीमन्, हम सब लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते हैं कि रिक्शा हांकने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। जिस प्रदेश में रिक्शा वालों की तादाद बढ़ती जाय, जिस प्रदेश में बेकारों की तादाद बढ़ती जाय उसमें यह कह देना कि बेरोजगारी का हमने खात्मा किया है बिल्कुल गलत है। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। बड़े २ उद्योगधंधों की चर्चा की जाती है। लेकिन जब मैं इस पंचवर्षीय योजना को देखता हूं तो श्रीमन्, केवल ४ करोड़ ९० लाख रुपया बड़े उद्योग धंधों के लिये रखा गया है जिसमें का अधिक अंश चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये रखा गया है। मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि इस ४ करोड़ ९० लाख में से आप कौन सी मिल, कौन सा बड़ा उद्योग इस प्रदेश में खोल सकते हैं और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इतना और कहना चाहता हूं कि इस तरह की योजनाओं से हमारे देश की समस्यायें हल होने वाली नहीं है। जब तक कि उत्पादन पूंजी, श्रम और वितरण पर सरकार कन्ट्रोल नहीं करती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है और मुझे विश्वास है कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक इन चीजों पर कब्जा नहीं कर सकती है और कब्जा नहीं कर सकती तो हमारे प्रदेश में बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती है।

*श्री शिवनारायण—अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत से मैं आज कहना चाहता हूं कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना की नींव डालने वाला .....

अधिष्ठाता—आपके ७ मिनट हैं केवल।

श्री शिवनारायण—श्रीमन् ने कहा था कि १५ मिनट देंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हमारी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना उस सेनानी ने की थी जिसने साइमन कमीशन का मुकाबला किया था। वह हमारा महान् नेता आज केन्द्र में है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर आज इस सदन को और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनकी स्थापित की हुयी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हुयी जिसमें हमने फूड प्राबलम को हल किया और दूसरे प्रान्तों को भी खाना दिया है। इसके बाद मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो हमारी सेकेंड फाइव ईयर प्लान है यह हमारा लक्ष्य है, हमारा निशान है, हमको आगे बढ़ना है। हमको इसके जरिये अपने प्रान्तो को खाना कपड़ा और रहने को मकान देना है। गरीबों को, यह हमारा सेम्पिल है, लक्ष्य है। देश की आर्थिक दशा को सुधारना है, ऊंचे उठाना है। मैं अपने प्लानिंग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग में आप लाखों रुपया देंगे, सेंट्रल से रुपया लाकर लगायेंगे। लेकिन मैं आपके प्लानिंग के ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर कौन हों, वह कितने हैं उनको लोयल होना चाहिये, आइडियल होना चाहिये और सुयोग्य होना चाहिये और पीपुल्स से उनका कन्टेक्ट होना चाहिये, गरीबपरवर होना चाहिये। तो मैं श्रीमन्, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उस तरफ भी उनका ध्यान हो। आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं मुझे खेद है कि विरोधी दल उठ गया, सुनने की तवक्को नहीं हुयी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुयी कि हमारे मुख्य मंत्री जी को इसका श्रेय है कि अपनी कैबिनेट से पहले उन्होंने नेता विरोधी दल से इस बारे में यानी पंचवर्षीय योजना पर कनकल्टेशन किया, उन्होंने उनसे बातें की, चाहे एक मिनट के लिये उनसे बातें की। पूरे प्वाइन्ट्स उनके सामने गये तो उनकी यह ड्यूटी थी कि कोई सजेशन्स बनाकर उनको गवर्नमेंट के पास भेजने चाहिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

थे। लेकिन मुझे उनकी स्पीच सुनकर ताज्जुब हुआ कि किस तरह की उनकी स्पीच हुयी, मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर शिवनारायण और हम एम० एल० ए० न होते तो रिक्शा हांकते होते। तो मैं तो बड़ा खुश हूं अगर हमारी बिरादरी बढ़ती। लेकिन मैं गेंदा सिंह जी से चाहता हूं कि मेरा स्टैन्डर्ड वही है, मैं जहां पहले था वहीं आज भी हूं, मैं तब भी अध्यापक था और रहूंगा, चाहे एम० एल० ए० शिप रहे या न रहे।

अधिष्ठाता---माननीय शिव नारायण पर्सनल बातें न कहें।

श्री शिवनारायण---मुझे कहा गया। मान्यवर, उसके बारे में मेरे विरोधी भाइयों ने कहा, किसी ने कहा कि यह तो बेसलेस है, कैपिटलिस्ट प्लान है, गेंदा सिंह ने कहा कि पीपुल्स प्लान नहीं है। संस्कृत में कहावत है "पश्यन्नपि न पश्यति श्रणवन्नपि न श्रृणोति" यानी देखते हुये भी नहीं देखता, सुनते हुये भी नहीं सुनता तो यह जिम्मेदारी किसकी है। यह पातंजलि ने कहा था जो एक बहुत बड़े विद्वान् माने जाते हैं और गांधी जी ने भी कहा था। वाइसराय के यहां से लौटकर आने के पश्चात् आगरे में गांधी जी ने भी कहा था कि 'हू हीयर्स नाट सीइंग सी नाट' सुनने वाले को सुनाई देता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, देखता है लेकिन उसको दिखायी नहीं देता है। तो वह हालत हमारे विरोधी दल के लोगों की है। मेरे भाई परिपूर्णानन्द ने इस सदन में बताया कि फारेन कंट्रीज के लोग कितनी प्रशंसा हमारी करते हैं। इसका सबूत है जवाहर लाल नेहरू की रूस यात्रा, वह हमारे समक्ष है। हम नंगे हों, भूखे हों, देश में नंगे घूमते हों लेकिन आज हमारी मान मर्यादा देश के बाहर है। हमने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। भगवान बुद्ध के बाद नेहरू वह दूसरे आदमी हैं जो चीन गये, रूस गये, और और देशों को गये और सबने उनका आदर और सम्मान किया। वह सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं जिनके बदौलत हम आज आगे बढ़ रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर में हमने काफी तरक्की की। मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि "डाईवर्ट दैट मनी इन्टू एजूकेशन ऐन्ड हेल्थ"। शिक्षा मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक गड़बड़ी है। न जाने कैसे-कैसे डाइरेक्टर्स हमारे ऊपर लदे हुये हैं 'हो इज ओनली ए लेटर बाक्स' मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया जाय। मैंने इस सदन में बार बार कहा कि मुफ्त एजूकेशन हो जाय, हमारे लड़के जो ५५ में फेल हुये उनको इजाजत मिलनी चाहिये। इंटरमीडियट बोर्ड को ठीक काम करना चाहिये, अगर वह ठीक काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट को उसको जब्त कर लेना चाहिये।

आज हरिजनों की क्या दशा है? वह अपने सिरों पर घड़े रख रख कर मीलों से पानी लाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है उनकी दयनीय दशा आपसे छिपी नहीं है। आपको मालूम है इसी लखनऊ में एक मुकारिबनगर है जहां न नर बसते हैं न नारी बसती हैं, उनकी दशा की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। मैं श्रीमती चन्द्रवती वैश्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें अपने प्लानिंग मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के ऊपर गुमान है जिनकी माता ने जीरा बाई के समान हमको ऐसा लाल दिया जो आजन्म ब्रह्मचारी रहकर हमारी सेवा कर रहा है।

अधिष्ठाता---समय समाप्त हो गया।

श्री शिवनारायण---अधिष्ठाता महोदय, दो मिनट और चाहता हूं, केवल दो मिनट।

अधिष्ठाता---लेकिन अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवनारायण---अधिष्ठाता महोदय, केवल दो मिनट और चाहता हूं। आपने और लोगों को दस-दस मिनट दिये हैं मुझे केवल दो मिनट और दे दीजिये।

अधिष्ठाता---अच्छी बात है ।

श्री शिवनारायण---मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने दो मिनट मुझे और दिया । मैं आपकी दया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात का ख्याल रखे कि समाज में जो दशा है उसको उसे ठीक करना है और ऐसा करते वक्त हमें अपनी भारतीय संस्कृति अपने सामने रखनी चाहिये । हमारी बहू बेटियां, हमारे भाई, हमारे लड़के सिनेमा देखते हैं, नंगे सिर घूमते हैं, हमारे छोटे-छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं । मैं टीचर होने के नाते कभी कभी चेक कर लेता हूं तो वह हमारा मुंह ताकने लगते हैं । तो यह गिरी हालत आज हमारी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर द्रोणाचार्य का स्थान आपने इन गुरुजनों को न दिया और उनको बिलो डिगनिटी रखा, ड्यून्स से भी बिलो रखा तो आप यह निश्चय जान रखिये आपकी सन्तान भी चपरासी ही पैदा होंगी । मैं यह कोई अभिशाप नहीं दे रहा हूं बल्कि जो फैक्ट है वह रख रहा हूं । आज आपके सामने यह कत्लेआम हो रहा है । मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरफ वह ध्यान दे; "गरीबों को मिले रोटी तो हमारी जान सस्ती है ।"तो हमको और आपको आगे आना है और मैं अपने बाराबंकी के दो शहीदों के नाम पर दो आंसू बहाना चाहता हूं ।

पी० आर० डी० का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और पुलिस को चेंज करके पी० आर० डी० को पावर डेलीगेट करे, तो हमारा सब काम ठीक हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने प्लानिंग मंत्री को धन्यवाद देता हूं । इर्रीगेशन मंत्री जो यहां मौजूद हैं । उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जल दें । भागीरथ ने तपस्या की थी और स्वर्ग से गंगा को लाये थे, आप पाताल से ला रहे हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां भी दिखायी देता है इर्रीगेशन ही दिखायी देता है और ट्यूबवेल्स दिखायी देते हैं । और हमारा यह गर्व है कि वह सेनानी हमारा मुख्य मंत्री है कि जिस गुरु के शिष्य भी उसकी कैबिनट में मौजूद हैं । जो कार्य भार उनके सर पर है वह बड़े सुन्दर ढंग पर चलेगा, हमारी पंचवर्षीय योजना सफल होगी और देश का कल्याण होगा ।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---जो वाद-विवाद इस भवन में इस योजना के सम्बन्ध में चल रहा है वह कभी कभी तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि बजट शायद इस भवन के सामने पेश है और जिस प्रकार से जनरल बजट पर बहस हुआ करती है कम से कम जहां तक मेरे विभाग का सम्बन्ध है उसकी निस्वत तो ऐसी ही बातें कही गयीं । इसमें संदेह नहीं कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक योजना बनाना प्रजातंत्र देश में बड़ी मुश्किल चीज है और जो उन्होंने इसका इतिहास बताया, यह बताया ही था कि इसका पहला आरम्भ रूस में हुआ और आप जानते हैं कि रूस के बाद जब "न्यु जील" के नाम से एक चीज अमरीका में चलायी गयी अमरीका में तो जहांतक पूंजीवादी अर्थशास्त्रीयों का सम्बन्ध था उन्होंने यह कहा कि योजना और प्रजातंत्र यह दोनों साथ में नहीं चल सकते । लेकिन थोड़े दिन के अभ्यास के बाद ऐसा मालूम हुआ कि यह सम्भव है कि हम देश में एक योजना बनादें और उसका केवल एक मात्र उद्देश्य यह हुआ करता है कि हम किस प्रकार से देश में उपलब्ध धन सामग्री को एकत्रित करके समाज के विकास और कल्याण का काम करें । पूंजीवादी देशों में भी अब यह माना जाने लगा कि यह चीज सम्भव है । तो किसी भी योजना का उद्देश्य किसी प्रजातंत्रवादी या एकतंत्रवादी देश में यही हुआ करता है, यही उसका अभिप्राय हुआ करता है । उस दृष्टि से अब जो आपके प्रान्त की योजना आपके सम्मुख प्रस्तुत है उस पर यदि आप विचार करें तो कम से कम आप स्वयं यह सोचेंगे कि हमें इस योजना के संशोधन में या क्रिटिसिजम में या इसके और सुधार में क्या करना चाहिये ।

शिक्षा का स्तर तो सचमुच में, कल मैंने देखा कि कितना गिर गया है । मुझे अफसोस है कि श्री राजनारायण जी यहां हैं नहीं, लेकिन वह बी० ए० पास हैं, एल० एल० बी० भी हैं,

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इस स्थान पर बोलते भी थे और वह इलाहाबाद में जो अब कमेटी मुकर्रर है उनका इससे क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया और उसको किसी चीज से इस योजना से क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। तो स्तर तो गिर गया है। वह यहां के लीडर आफ अपोजीशन थे, इसमें संदेह नहीं, लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर स्तर गिरता भी जा रहा है तो आप किसी योजना को देश के सामने इस कारण रोक नहीं सकते कि हमारा स्तर गिरता जा रहा है इसलिये हम शिक्षा का प्रसार नहीं करना चाहते। यह आप कभी भी प्रजातंत्रवादी देश हो तब तो कर ही नहीं सकते लेकिन अगर एकतंत्रवादी देश भी हो तो वहां भी सिवाय तलवार और जेल के जोर से उसकी प्रगति को रोक नहीं सकते हैं। मुझे अफसोस है कि माननीय गौतम जी जब बोल रहे थे तो मैं मौजूद नहीं था। मैंने उनसे कल कहा भी था कि जब आप बोलें तो मैं रहना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं रह सका। ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हमारी व्यवस्था इस माने में ठीक नहीं है कि जितनी सामग्री हमें अपनी पाठशालाओं को देना चाहिये वह हम दे सकें। हमारे पास धन की इतनी कमी है। लेकिन फिर भी यह स्वीकार करते हुये भी हम यह नहीं कह सकते कि अब हम स्कूलों की संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे, अब हम लोगों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये जितनी सुविधायें हैं वे प्रदान नहीं करें। यह किसी योजना का अंग नहीं हो सकता। यहां बहुत से आंकड़े सुनाये गये कि बम्बई में यह होता है, मद्रास में यह होता है, त्रावणकोर कोचीन में यह होता है। ठीक है, होता है। लेकिन अगर आक्षेप यह हो कि यह सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती और इसलिये धन पर्याप्त होते हुये भी शिक्षा में वृद्धि नहीं कर रही है तो यह ठीक हो सकता है और अगर यह आक्षेप है तो हमारे लिये सचमुच निन्दनीय और शर्म की बात है। हमारे पास रुपया भी है, हमारे पास सज्जा और सामग्री भी है, हम उसका इन्तजाम भी कर सकते हैं मगर फिर भी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ा नहीं रहे हैं जिसमें सबको शिक्षा मिल सके। तो एक आक्षेप यह हो सकता है। दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि हमारे पास जितना धन चाहिये उसके लिये हमारे प्रान्त में उतनी आमदनी नहीं है। हमारे प्रान्त की और समस्यायें शायद शिक्षा से ऊपर रखी जायें। मैं समझता हूं कि शायद यही आक्षेप ठीक भी है। हम यह नहीं कह सकते कि बम्बई जितना खर्च करता है उतना हम खर्च करते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं और इसके कहने में कोई लज्जा की बात भी नहीं है और जो किया गया है उसके लिये लज्जित होने की आवश्यकता भी नहीं है कि जितना आपके यहां हुआ है इस परिस्थिति में देश के किसी और प्रान्त में उतना होना सम्भव नहीं था। मैं बताऊं सन् ४५-४६ में शिक्षा का आपका ढाई करोड़ का बजट होता था जो आज १० करोड़ ३८ लाख का होता है। उसमें दिखलाया गया कि बम्बई अपने बजट का इतना खर्च करता है और यू० पी० सबसे कम खर्च करता है। यह चीज सचमुच में मुझे भी बड़ी खटकी और मैंने इसके हिन्दुस्तान भर के आंकड़े इकट्ठे किये। मालूम यह हुआ कि हमारे बजेटिंग में और उनके बजेटिंग में फर्क है। हम जनरल एजूकेशन को एक स्थान देकर बजट में उसके लिये रुपया प्रोवाइड करते हैं। हमारी बजेटिंग में मेडिकल नहीं है, हमारी बजेटिंग इंडस्ट्री नहीं है, हमारी बजेटिंग में इंजीनियरिंग नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, ऐग्रीकल्चर अलग है। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हम भी अपने बजट का १७ फीसदी खर्च करते हैं। वह बम्बई से १ फीसदी जरूर कम है लेकिन फिर भी १७ फीसदी अपने बजट का तो हम भी खर्च करते हैं। तो यदि आप इस दृष्टि से देखें तो यह भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लज्जित होना चाहिए तो उसके आंकड़ों में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार होगा तो दो चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। एक तो यह कि शिक्षा का प्रसार हो और दूसरी ओर इस बात का प्रबंध हो कि हम उसे सुव्यवस्थित बनायें, उसमें ठोसपन पैदा करें। यह ठीक है कि समय-समय पर एक नीति, दूसरी नीति और दोनों को साथ भी बरतना पड़ता है, लड़ाई के बाद ऐसी अवस्था हमारे प्रान्त में हो गयी है कि शिक्षा के लिये लोगों में इतनी प्यास बढ़ी कि यह नामुमकिन था कि आप उसको रोक सकते और उस समय जो आपके सामने एक स्कीम आयी कि हम इतने दिनों में इतनी प्राइमरी

स्कूल खोल देंगे कि किसी भी बच्चे को अपने गांव से मील डेढ़ मील से ज्यादा दूर न जाना पड़ेगा। यह चले कुछ दिन लेकिन बाद को उसे रोकना पड़ा।

आप जानते हैं कि हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत है उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास रुपया नहीं था इसलिये गवर्नमेंट ने अपने पास से वह स्कूल खोले और बाद को यह देखा गया कि कहीं कहीं ऐसा हो गया है कि एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है और उसके थोड़ी दूर पर ही राजकीय पाठशाला भी है तो जो लड़के उस स्कूल में दर्ज थे वही लड़के इस पाठशाला में दर्ज पाये गये। वह इसलिये कि उनको भी तीन मास्टर मिल जायं क्योंकि मास्टरों की तादाद लड़कों की तादाद के ऊपर निश्चित होती है। इसलिये इसकी छानबीन की गयी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह स्कूल दे दिये गये और उनसे कहा गया कि आप इनका प्रबंध अपने हाथ में ले लीजिये और हम आपको रुपया उतना ही देते रहेंगे। लेकिन आप इस प्रकार से इन स्कूलों को फैलायें कि डुप्लीकेशन न हो। नतीजा यह हुआ कि जो एक विलक्षण चीज है। रुपया इस साल में अधिक दिया गया लेकिन लड़कों की संख्या कम हो गयी और किस प्रकार से हुयी? वह इस प्रकार हुयी कि एक ही गांव के पास तीन स्कूल हैं तो तीनों जगहों उन्हीं लड़कों के नाम दर्ज हैं इसलिये लड़कों की संख्या ज्यादा थी लेकिन रिआर्गनाइजेशन हुआ तो यह बात मालूम हुयी। हरिजनों की फीस नहीं देनी पड़ती है। कितने लड़के हैं इस पर मास्टर की संख्या निर्धारित होती है इसलिये १०-१५ नाम फर्जी लिख लेते हैं, इसलिये कि तीन मास्टर यहां रहें जो उसी गांव के रहने वाले हैं या कुर्बोजवार के रहने वाले हैं। इसलिये रिपोर्ट में यह है कि लड़कों की संख्या कम हो गयी तो वह इस कारण से कम हो गयी और यह जरूरी भी था।

जहां तक बम्बई की बड़ी प्रशंसा है कि वहां पर ६६ प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देते हैं तो हम भी उतना ही देते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल नहीं खोल रहे हैं। हम इस योजना में ५ हजार प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, उसका भार सरकार ने अपने ऊपर लिया है और बाद को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे देंगे और उतना रुपया भी देंगे तो इस प्रकार से यह कहना ठीक नहीं है। अगर हम और आप चाहें कि पब्लिक का सब रुपया खर्च करके सबको लिट्रेट बना दें तो कैसे करेंगे। जो प्रगति हो रही है उसको आपको एक नजर से देखना पड़ेगा जिस अवस्था में कि आपको शिक्षा विभाग मिला था तो उससे अब तक आपने प्रगति की ओर कितना लाभ हुआ और कितनों को शिक्षित बनाया, कितने गांवों को सुविधा दी और उनके बच्चों को प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के लिये कितनी दूर जाना पड़ेगा तो इससे आप देखें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इन पिछले थोड़े वर्षों में आपकी प्रगति देश के कुल प्रान्तों से अधिक रही है और अगर आप अपने कार्य की ओर देखें तो आप पायेंगे कि हर बात के लिये प्रबंध किया गया है। जैसे आज मास्टरों की तनख्वाह का सवाल है। प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों की तनख्वाह कम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसको बढ़ा नहीं सकता, उसके पास साधन नहीं। तो इस २३ करोड़ के प्लान में उसका प्रबंध है। अभी यह २३ करोड़ का प्लान है और संभव है कि कुछ और बढ़ जाय। तो हम यह चाहते थे कि इस प्लान में हम यह सब कर दें और कांस्टीट्यूशन में एक डाइरेक्टिव भी है कि हमको इस ऐज लिमिट तक के बच्चों के लिये फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन करनी चाहिये लेकिन उसे हम कर नहीं पा रहे हैं अर्थाभाव के कारण और सूबे भी देश के नहीं कर पाये हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, किस की वृद्धि हम चाहते हैं, यह सब अपने स्थान पर होते हुये, हमारी इच्छा होते हुये कि हम इसको कम से कम धन और समय में कर दें कुछ ऐसी असुविधायें होती हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशन्स होती हैं, कुछ ऐसी सीमायें होती हैं कि जिन पर हम कोई बंधन नहीं कर पाते हैं और यह बात हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बिलकुल लागू है। तो इसलिये यह कहना उचित नहीं है। बहुत सी बातें परस्पर विरोधी कही गयी। किसी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को तोड़ देना चाहिये, किसी ने कहा कि हायर एजूकेशन नहीं होना चाहिये। लेकिन एक देश की योजना इस तरह से नहीं बनती। देश की योजना के लिये आपको हर स्तर पर एक सीमा बनानी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

पड़ेगी। आप यह नहीं कह सकते थे कि यह चीज तोड़ दो और वह चीज तोड़ दो और इस तरह से योजना बनाओ। देश के लिये यूनिवर्सिटी की जरूरत है। यह आप कभी नहीं कह सकते कि उन पर ताला लगा दीजिये। देश के लिये प्राइमरी एजूकेशन की भी जरूरत है इसलिये कि हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। वह कम से कम पढ़ना-लिखना जरूर जानता हो, लिट्रेट हो। हमारे यहां का तो यह ट्रेडीशन है कि हम पेड़ के नीचे बैठ कर उंगली से लिख कर पढ़े हैं। यदि आज भी कहीं कहीं वही अवस्था है तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यदि हम उंगली से जमीन पर बच्चों को क ख ग लिखना सिखाते हैं तो उसमें शर्म की बात नहीं है। उन्हें लिट्रेट बनाने के लिये क्या जरूरी है कि बहुत अच्छा भवन ही हो। हां, यह अवश्य है कि बरसात और पानी से बचने के लिये एक भवन की आवश्यकता होती है। तो यह जो प्लान बना हुआ है उसमें अगर आप देखें तो इस २३ करोड़ रुपये में हर चीज का प्रबंध है। अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे पुराने कल्चर को प्रोत्साहन मिले और इसीलिये संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात इसमें रखी गयी है। इसके लिये भी रुपया इसमें रखा गया है और उसका बिल भी अगले नवम्बर के सेशन में आपके सामने पेश हो जायगा। अगर यह हाउस और चलता तो इस सेशन में ही पेश हो सकता था। तो पहले पांच हजार प्राइमरी स्कूल हम खोल रहे हैं। हम इस बात का भी प्रबंध कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मदद करें। टीचर्स की तनख्वाहों के लिये हमने यह रखा है कि जितनी तनख्वाह हर एक टीचर को मिलती है उस पर जो महंगाई का भत्ता उनको मिलता है हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देता है। इन दोनों को, तनख्वाह और भत्ते को मिलाकर टीचर्स की तनख्वाह कर दी जाय और जितना इन्क्रीमेंट आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देता रहा है वह गवर्नमेंट देगी। अगर किसी को ६ रुपया इन्क्रीमेंट मिलता है तो वह ६ रुपया गवर्नमेंट देगी। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जितनी अपने पास से आर्थिक सहायता दे सकते हैं उनको देने का प्रबंध किया है। इसी तरह से सेकेन्डरी स्कूलों के टीचरों को बहुत कम हिस्सा उसका मिलता था। इस तरह से हम उनको भी सहायता देंगे। अगर किसी टीचर को १२ रुपया मिलता है तो ६ रुपये देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी और केवल ६ रुपया देने की जिम्मेदारी उन एडेड स्कूलों के पास रह जायगी। मैं देखता हूं कि इस में इस बात को किया गया है कि ५०० स्कूल ऐसे खोले जायं जिनमें लोगों को जो शिक्षा के लिये भूख है—यह दूसरी बात है कि गलत परिपाटी के कारण हमारा एक नुक्ते निगाह दूसरा हो गया है बच्चे जो पढ़ने के लिये आते हैं वह समझते हैं कि वे शिक्षित होकर नौकरी करेंगे लेकिन यह चीज बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। आखिर दुनिया में जो चीजें रही हैं वह यहां भी होंगी। दुनिया के और लोगों को शिक्षा अधिक से अधिक मिलती है और हर एक आदमी सीखता है और हर एक आदमी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ता है। हमारे यहां नौकरी के पीछे दौड़ने का कारण है। उनके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है दूसरा काम नहीं है। इसलिये यहां शिक्षा के साथ उसका सम्बन्ध है। वर्ना शिक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि उस प्लानिंग में इस बात का प्रबंध किया गया है कि हमारे यहां और ऐसे गृह उद्योग हों जिनमें लोगों के शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीविकोपार्जन का साधन मिल सके। इसमें आप देखेंगे कि काफी लोगों को हम इसमें भर सकेंगे और जीविकोपार्जन का साधन दे सकेंगे। इसी तरह से प्राइमरी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर और यूनिवर्सिटी स्टेज पर जो टीचरों की ट्रेनिंग है या ऐसी चीजें हैं उन सब पर काफी ध्यान दिया है और सबके लिये इस प्लान में योजना बनी गयी है कि इतना रुपया मिल जाने पर हम इस कार्य को इस तरह से कर सकेंगे।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

नियोजन मंत्री (श्री फूल सिंह)—अध्यक्ष महोदय, ४ दिन से इस पंचवर्षीय योजना नयी और पुरानी पर बहस चल रही है। इसमें आदरणीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत मुफीद बातें बयान कीं, जिनसे इस महकमें को काफी लाभ होगा। मैं इस थोड़े

समय में उन सब बातों को दोहराने की चेष्टा नहीं करूंगा कि जिन मुख्य बातों का चर्चा यहां पर हुआ है, परन्तु २,४ खास खास बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं।

यह कि कोई प्लान वैकुअम में नहीं बनता। किसी खास बैक ग्राउन्ड को सामने रखकर योजना खड़ी की जाती है। हमारे प्रान्त की परिस्थिति एक खास परिस्थिति है। इस बात का ध्यान माननीय सदस्यों को अवश्य होगा। यों तो कुल भारतवर्ष ही गांवों में बसा हुआ है। पर जहां भारतवर्ष के ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं हमारे प्रान्त के ७६ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इसी तरह से गावों में रहने वालों की संख्या इस प्रान्त में भारत के दूसरे प्रांतों के मुकाबिले में कहीं ज्यादा है और आश्चर्य है कि दुनियां के बड़े देशों में से किसी देश में भी इतने लोग गांवों में नहीं रहते जितने हमारे प्रान्त में रहते हैं जिनकी संख्या ८७ प्रतिशत है। केवल कोरिया ही एक ऐसा देश है जहां हमारे प्रान्त से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं लेकिन कोरिया का हमारे प्रान्त से कोई मुकाबिला नहीं हो सकता। जन संख्या के हिसाब से भी जितनी संख्या सीलोन और नैपाल की है उतनी जनसंख्या हमारे प्रांत में पिछले दस वर्षों में बढ़ गयी है। प्रति मील जो जन संख्या अमेरिका में है उतनी संख्या हमारे प्रान्त में १० सालों में बढ़ गयी है। कनाडा और आस्ट्रेलिया से इस प्रदेश का कोई मुकाबिला नहीं है। फिर कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा कृषि प्रधान प्रदेश विशेष कठिनाइयों में से गुजरा हो। इसलिये जब आप इस बैकग्राउन्ड को देखें और जब यह पहली योजना आरम्भ हुयी तब हम कितने थे और अब हम कितने हो गये हैं तो बावजूद उन सब त्रुटियों के जो हमारे कामों में रही हैं इस प्रान्त के लोग गौरव की दृष्टि से देख सकते हैं। मान्यवर, इस सदन में इसकी भी चर्चा रही है कि यह कहा जाना बिलकुल गलत है कि हमने खाद्य पदार्थों के मसले को हल कर लिया है। कुछ साथियों का यह कहना है कि हमारी अन्न की समस्या कुछ सुलझी नहीं है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९२१ से आज हमारी जो जनसंख्या है वह ३५ प्रतिशत बढ़ गयी है और सन् १९२१ में हमारे प्रान्त से ५ लाख टन अन्न दूसरे प्रान्तों को भेजा जाता था। यह संख्या सन् ४१ में घट कर २ लाख टन रह गयी तथा सन् ५१ में २ हजार टन बाहर से मंगाना पड़ा। यह सही है कि २१ और ४१ के मुकाबिले में सन् ५१ में पर केपिटा अवेलेबिलिटी घटी। सन् २१ में लगभग १० छटांक, ४१ में लगभग ९ छटांक, और ५०–५१ में ७.४ छटांक हुयी। अगर इन बातों को नजरअन्दाज कर दिया जाय तो सन् ५१–५५ तक भी लगभग १४ लाख टन की पैदावार में वृद्धि हमारे देश में हुयी। केवल इसी आंकड़े को निकाल कर सरकार यह अनुमान कर सकती है कि यह कोई ताज्जुब नहीं कि अब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी १०–११ छटांक के बीच में हो। मान्यवर, इस प्रदेश में दो मर्तबा सर्वे हुयी। एक सैंपिल सर्वे सन् ४८ में हुयी और दूसरी सैंपिल सर्वे सन् ५० में हुयी। इन दोनों सैंपिल सर्वेज में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी १० छटांक की रही। यह सैंपिल सर्वे देहात से संबंधित थी। यह जो सैंसस रिपोर्ट है, दोनों शहर और देहात सब मिला कर सर्वे हुआ है। अगर आप इस बात को भी ध्यान में रखें तो इस ६ करोड़ ३० लाख में जो १२ साल से कम के बच्चे और ६० साल से ऊपर के बूढ़े हैं, ये दोनों मिला कर दो ढाई करोड़ के करीब हो जायेंगे और इनकी खुराक एक तनदुरुस्त आदमी से कहीं कम होती है और तब आप इस अनुमान पर पहुंच जायेंगे कि हमारी जो पर कैपिटा ऐवेलिबिलिटी खुराक की है वह काफी बढ़ी है। मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि आंकड़े के फेर में न पड़ें। आंकड़े के फेर में को छोड़ते हुये भी यह बात स्पष्ट है कि आज देश में अन्न पर कोई कंट्रोल नहीं है, आज देश में अन्न के मूवमेंट पर कोई पाबन्दी नहीं है फिर भी सरकार को काफी रुपया इस वास्ते खर्च करना पड़ा कि अन्न का दाम बहुत ज्यादा न गिर जाय। मेरे ख्याल में इससे स्पष्ट प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता कि हमने खाद्य के मसले को सुलझा दिया है।

जहां तक शुगर की बातें हैं, शुगर की समस्या बिलकुल उल्टी है। जुलाई में जब कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुयी थी तो शुगर बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना था कि ७ लाख टन शायद जमा पड़ा है और अगले महीने जब मिलें चलेंगी तब भी कई लाख टन शुगर गोदामों

[श्री फूल सिंह]

में जमा रहेगा। केन्द्रीय सरकार के पास ४ लाख टन शुगर जो उन्होंने बाहर से मंगाया था। उनके गोदामों में जमा है। तो यह मोटा प्रमाण काफी है यह कहने के लिये कि हमने इस मसले को हल किया है। दूसरे पर कैपिटा इनकम की समस्या पर यहां बहुत बहस चली और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी कि सरकारी किताबों से ही पर कैपिटा इनकम घटी है, बढ़ी नहीं है। माननीय, यह बहुत मोटी बात है। अगर आप पर कैपिटा इनकम का हिसाब रुपये में लगावेंगे तो वस्तुओं का मूल्य बाजार से लगाया जायगा। देश रुपया नहीं शुगर पैदा करता है, अनाज पैदा करता है कपड़ा पैदा करता है और इन सब चीजों की तादाद अगर बढ़ती भी चली जाय और भाव गिरता चला जाय तो एक तरफ तो देश में उद्योग धंधे बढ़े मालूम होंगे और पर कैपिटा इनकम कम मालूम होगी। सच्चाई यह बात इन आंकड़ों में है। वे सालवार आंकड़े हैं। सालवार आंकड़े उस साल के भाव पर बनाये जाते हैं और जब कम्परेटिव आंकड़े बनाये जाते हैं तो एक एवरेज रेट निकाल कर उसी से बनाये जाते हैं। तो इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े बतलाये कि २२३ से २३१ रु० पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, वह उस दृष्टि से था और जो आंकड़े विरोधी दल की तरफ से बतलाये गये हैं वे सालवार रेट के आंकड़े थे।

श्रीमन्, यह बात भी कही गयी है कि जितना टैक्स यह प्रान्त देता है उतना कहीं नहीं है। टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो यह मालूम होगा कि इस देश के ९ ए० क्लास स्टेट्स में से ५ ए० क्लास स्टेट्स ऐसे हैं जिनका पर कैपिटा टैक्सेशन यू० पी० से ज्यादा है और बी० क्लास स्टेट्स सब की सब ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा टैक्सेशन यू० पी० से ज्यादा है। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि हमारे सूबे में टैक्सेशन की दर बहुत ज्यादा नहीं है। इन आंकड़ों और सब चीजों को कोट करने के लिये एक सच्चाई की आवश्यकता है। अगर सच्चाई को नजरअन्दाज कर के आंकड़े कोट किये जायं तो उन पुस्तकों से न मालूम क्या सिद्ध हो जायगा चूंकि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने सन् ५४ के दिसम्बर अंक से कोट कर दिया यू० पी० एन०ई०एस० ब्लाक के बारे में कि बहुत कम हैं। मैं यह यकीन नहीं करता कि उन्होंने मार्च सन् ५३ का अंक भी देखा होगा। अगर देखा होगा तो उन को मानना पड़ेगा कि हमारी प्रगति किसी से कम नहीं है। प्लान की दृष्टि तो खर्च के एतबार से हम तमाम भारतवर्ष में नम्बर ३ पर हैं। इस का कारण यह है कि दसों स्कीम ऐसी हैं जो हमारे सूबे में ५३--५४ में लागू की गयीं। सब स्कीम चालू की जाती है तो फौरन ही सब खर्च नहीं हो सकता, सारा ६ मास उसके खड़ा होने में लगाते हैं। एन०ई०एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की प्रगति को आप देखें तो इस सूबे में ११० एन०ई०एस० ब्लाक्स मुकर्रर थे और अब तक हम ने ११४ के करीब खोल दिये हैं और गालिबन २० इस साल में और खोल देंगे। यही नहीं काम का अन्दाजा रुपये के खर्च से लगाना ठीक नहीं है चुनांचे हमारी जो नम्बर ३ जगह खर्च में आयी उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि हमने जो २ हजार ट्यूबवेल कम्युनिटी प्रोजेक्ट में लगाये उनका खर्च हमने फाइव ईयर प्लान में न डालकर, २००० कुयें जो टी०सी०एम०से मिले थे उस में डाल दिये, उस दृष्टि से हम पीछे पड़ गये लेकिन एचीवमेंट की दृष्टि से हम औरों से आगे हैं। मैं नहीं समझता कि कहांतक सम्भव होगा कि मैं सब आंकड़े सदन के सामने रखूं जिन से मालूम होगा कि बहुत सी जरूरी मदें ऐसी हैं जिस में हमने टारगेट्स को पूरा ही नहीं किया बल्कि उसके दुगुने से भी आगे हम पहुंच गये हैं। हमारे प्रदेश में बहुत सी जो जरूरी चीजें थीं उनमें हमने और प्रदेशों के मुकाबिले में बड़ी भारी तरक्की की है। मैं उदाहरण के तौर पर अच्छे किस्म के बीज की तकसीम का जिक्र करता हूं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट में सन् ५२--५३ में जो ब्लाक्स खुले उन में इस बीज का एचीवमेन्ट २९८ प्रतिशत है और जो सन् ५३--५४ में खोले उनका इस बीज के बटवारे का प्रतिशत २२१ है और एन०ई०एस० में ३३९ प्रतिशत है। इसी तरह से सिंचाई का एचीवमेंट सन् ५२ में २५५ है और २०७, ५३--५४ में है और ३७४ एन० ई० एस० ब्लाक्स में है। सड़कों के बनाने का भी १२० प्रतिशत एचीवमेंट है। फील्ड डिमांस्ट्रेशन में भी हमने अपने टार्गेट से अधिक तरक्की की है। यह तो मैंने दो चार

ऐसे आंकड़े आपके सामने रखे जिन से मालूम होगा कि हमने कौन से टारगेट्स पूरे किये हैं और हम कहां बढ़ गये हैं और हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं कि जहां हम टार्गेट्स को पूरा नहीं कर सके हैं। उसके दो तीन कारण हैं। एक बड़ा कारण तो टेक्निकल परसोनेल की नानअवेलिबिटी है। चुनांचे इन दो-तीन सालों में पहले ही से आपने बजट में बेटरीनरी कालेज की यह सारी बातें रखी हैं। इसके साथ ही साथ एक और नया प्रयोग किया जा रहा है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश की प्रगति के लिये बहुत एक्सपर्टस की आवश्यकता नहीं है। मल्टी परपजेज मैन की ज्यादा आवश्यकता है। गांवों में जो मवेशियों का इलाज करते हैं जो मनुष्यों का इलाज करता है उसको न तो सारे साधन उपलब्ध हैं जो बड़े शफाखाने होते हैं और न वह वहां उपलब्ध होना सम्भव है। तो गांव के लिये थोड़ी सी कमी है इसलिये कि हर गांव में सरकार डैम नहीं बनाने जा रही है, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाने जा रही है छोटी मोटी सड़कें और छोटी मोटी पुलिया बनायी जायगी तो बड़े इंजीनियर्स बेकार रहेंगे। इसीलिये देखते हैं कि एक शार्ट कोर्स ट्रेनिंग का सिर्फ तजुर्बे के तौर पर जिसकी ट्रेनिंग का मिआर ओवरसियर से भी कम रखा है। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग सफल रहेगा और मैं समझता हूं कि देश का काफी लाभ होगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी थीं कि जहां हमारी कमी थी और कुछ चीजें ऐसी थीं कि जहां हम आगे बढ़ रहे थे श्रीमन् यह इत्तिफाक से हुआ या दानिश्ता हो कि इस महकमे का नाम प्लानिंग और डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में यह बनाम बहुत उपयुक्त है दरअसल प्लानिंग और डेवलपमेंट आफ प्लानिंग है। प्लानिंग और डेवलपमेंट कोई इनडिपेंडेंट चीज नहीं है। विकास करो, विकास की योजना बनाओ और जो योजना अब बनेगी उस योजना का विकास करो तो दोनों बातें मिली जुली हैं। इसीलिये यह कहा जा सकता है कि योजना दरअसल अब शुरू हुयी क्योंकि हमने अब देखा कि किस तरीके से दूसरी पंचसाला योजना को हम ऐसा बनावें जिसमें जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो। मुझे इस बात का खेद है कि बहुत से माननीय सदस्य यहां यह फरमा देते हैं कि जनता का सहयोग बिलकुल प्राप्त नहीं है। मैं यह कहने की धृष्टता कर सकता हूं कि वे माननीय सदस्य बिलकुल गांवों में नहीं गये। जितना रुपया आप प्लानिंग पर पास करते हैं यहां से तकरीबन दो करोड़ रुपया ऐसा है जो हर साल जिलों को दिया जाता है और इस शर्त पर दिया जाता है कि एक अंश इसमें से खर्च करो और एक अंश जनता के सहयोग से लगाओ। श्रीमन्, मैं कुछ महीने पहले मेरठ के एक गांव में गया था और मैं यह देखकर दंग रहा गया कि उस गांव ने अपने डेवलपमेंट पर ९० हजार से ज्यादा रुपया खर्च किया है हालांकि उस गांव को सरकारी सहायता केवल १० हजार रुपया के करीब मिली है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि यहां से तो यह तय है कि फलां फलां किसम के कामों में सरकारी सहायता क्या होनी चाहिये, कम तो होनी चाहिये ५० प्रतिशत तक होना चाहिये और फलां फलां कामों में ३३ प्रतिशत तक होना चाहिये। मगर वाकया यह है कि लोगों ने जो काम करना शुरु किया अगर उस पर हम २५ प्रतिशत भी रुपया देने लगें तो शायद सारा बजट खत्म हो जाय। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो नगद रुपया देता हो लिहाजा उन सड़कों की पुलिया बना कर ही संतोष कर लिया जाता है। यह निराधार बात है कि इस योजना को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है। प्लान में जनता का सहयोग किस तरह से प्राप्त किया जा रहा है वह बात भी चर्चा करने योग्य है। श्रीमन्, ४,३०० करोड़ रुपया का कुल प्लान था जिसमें २,२०० करोड़ के करीब रुपया ऐसा है है जो प्रान्तों में खर्च होगा। इस रुपये में से कितना रुपया हमारे प्रान्त को मिलने वाला है उसकी चर्चा माननीय मंत्री जी कर चुके हैं। अब इस रुपये को कई हिस्सों में बांटना चाहिये। एक हिस्सा तो वह योजना है जो प्रान्त की सरकार स्वयं चलायेगी जिस योजना में किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है जैसे सीमेंट फैक्टरी का एक्सटेंशन। दूसरा हिस्सा वह है जिसको आप डिपार्टमेंटल स्कीम कह सकते हैं। महकमों की योजनाओं के भी दो भाग हैं। एक भाग तो वह जिसको महकमे अपने आप बना देंगे, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों किस्म की योजनाऐं यानी डिपार्टमेंटल प्लान और स्टेट

[श्री फूल सिंह]

प्लान बना कर जिलेवार बांटे जा रहे हैं ताकि हर जिले को यह मालूम हो जाय कि कौन-कौन से काम हमारे जिले में सरकार की तरफ से होंगे। फिर दूसरे डिपार्टमेंटल प्लान्स हैं जो कांट्रिब्यूटरी बेसिस पर होंगे जिनका पूरा होना इस बात पर निर्भर है कि स्थानीय सहयोग किस कदर मिलता है। उसके आंकड़े भी जिलों में बांट दिये गये हैं। अब गांव सभाओं को दो बातें मालूम हो गयी हैं कि क्या फिजिकल टार्गेट्स हैं और क्या-क्या फायनेन्शियल टार्गेट्स हैं। गालिबन हर गांव सभा को दो हजार रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिल सकेंगे और ५ हजार रुपये कर्जे के रूप में। अब गांव सभाओं को यह आदेश जारी हो रहे हैं कि इस रकम को सामने रख कर और वह सरकारी योजना सामने रख कर जिसमें यह लिखा हुआ है कि तुम्हारे जिले में कौन-कौन से काम सरकार करने जा रही है बाकी जो काम आपको करने हैं उसकी योजना बनायें और यह उनको बतला दिया गया कि इन योजनाओं में सरकारी सहायता में और उनको सहायता में १/३ से आधे तक का रेशियो होगा। अब ये गांव सभायें इन सब बातों को सामने रख कर अपने विलेज प्लान्स करने जा रही हैं। ये विलेज प्लान्स फिर ब्लाक कमेटी के सामने आयेंगे। मान्यवर, आज इस सदन में यह चर्चा थी कि इस बात का पता नहीं है कि शेडो कमेटीज और ब्लाक कमेटीज को इसमें कंसल्ट किया जायगा या नहीं। मेरा यह निवेदन है कि उनका मशविरा लिया जा रहा है। तमाम प्रान्त को लगभग ९०० एन० ई० एस० ब्लाक्स में बांटा जा रहा है और इन ९०० ब्लाक्स में २०० से कुछ ऊपर ब्लाक्स इंटेंसिव डेवलपमेंट ब्लाक्स होंगे। वे जो इंटेंसिव डेवलपमेंट ब्लाक्स होंगे इन ब्लाक्स के पास गालिबन दो लाख से ढाई लाख तक रुपया इंटर विलेज प्लान के लिये होगा। तो जो योजनायें गांव सभाओं के दायरे से बाहर हैं जिन योजनाओं में गांवों के सहयोग की आवश्यकता है वह योजनायें इस रूप से होंगी और इस रूप में भी कितना अनुपात सरकारी सहायता का हो और कितना लोकल एफर्ट्स का हो, वह निश्चित कर दिया गया है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर फिर जिला प्लानिंग कमेटी के सामने कागज जायेंगे। जिला प्लानिंग कमेटी को यह आदेश गये हैं कि वह अपने आपको बहुत सारी सब कमेटियों में बांट ले, गालिबन १० सब-कमेटियां हर जिला प्लानिंग कमेटी में होंगी, इन सब योजनाओं को छानबीन करके जिले के स्तर पर टैबुलेट करने के लिये, इस तरह से यह प्लान बनने जा रहा है। हम लोग इसमें कितने सफल होंगे वह निर्भर करता है इस पर कि कितना सहयोग हम सब इसमें देने जायेंगे। इंसान स्वयं अधूरा, उसके किये सब काम अधूरे, लेकिन अगर हम छोटे-छोटे व्यक्ति भी भगवान का नाम लेकर और कमर बांध करके खड़े हो जायें और अपने देश को आगे बढ़ाने का निश्चय करें तो यह यकीनन है, कि हमें इतने ज्यादा प्वाइंट्स आफ डिफरेंस नहीं मिलेंगे। आज सारा जोर प्वाइंट्स आफ डिफरेंस पर है। लेकिन आवश्यकता यह है कि कौन-कौन खामियां हैं, उसको न देख कर कोशिश इस बात की करें कि कहां-कहां हम सहयोग कर सकते हैं। इस स्टेज पर बहुत उपयुक्त है आलोचना ताकि जो गलतियां होने जा रही हैं प्लान में वह न हों, लेकिन उससे आगे इस बात की आवश्यकता है कि जब योजना बन जाय उसके सफल कराने में पूरा सहयोग प्राप्त हो। कंडेम करने का मौका तो बाद में भी रहेगा। लेकिन यह मौका बार-बार नहीं आयेगा कि देश की जो आवश्यकता थी देश की गरीबी को दूर करने का जो कार्य था तो कितनी-कितनी किसने कोशिश की। मैं यह कबूल करने को तैयार हूं कि नयी पंचसाला योजना में जो बेकारी को दूर करने का प्रश्न है सबसे जटिल समस्या वही है। पर यह मानते हुये भी अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह आंकड़े दे सकें कि कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि सरकार को इस बात का पूरा अन्दाजा है कि यह समस्या कितनी बड़ी है और मुख्तलिफ योजनाओं को बना कर सरकार इस समस्या को हल करने पर लगी है। यह सही है कि इस प्लान में हमने सीलिंग फिक्स करने की बात नहीं की इनकम की। लेकिन जो पाजिटिव बात है लोगों को रोजगार देने की बात मेरे नजदीक यह ज्यादा सोशलिस्ट ऐक्ट है। आमदनी की सीलिंग फिक्स करने से भी आवश्यक, ज्यादा आवश्यक यह है कि जो लाखों आदमी बेरोजगार हैं उनके मुंह में पानी पड़ जाय रोटी का टुकड़ा पड़ जाय।

श्री गेंदासिंह—यही नहीं है ।

श्री फूलसिंह—मैं माननीय गेंदा सिंह से इस मामले में कोई बहस तो नहीं कर सकता । पर मेरा यह निवेदन है कि इसको उस दृष्टि से मत देखो । एक मौका दो । अभी मैंने कहा कि प्लान शुरू हुआ है, अभी जिलों को कागज गये हैं, वह चीज सामने आये । अगर पहले से ही हल्ला करना शुरू किया कि यह कुछ नहीं है तो यकीनन जो कहते हैं कि कुछ नहीं है उनको दिखेगा कुछ नहीं । थोड़े से पोजिटिव आउट-पुट की आवश्यकता है, एक का स्ट्रक्टिव ऐप्रोच की आवश्यकता है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आपके जरिये से जो त्रुटियां हमारे काम में रहेंगी भगवान हमें शक्ति दे हम उसका मुकाबला करने को तैयार रहेंगे, पर अभी यह नहीं है कि हमारी त्रुटियां निश्चय हो जायं । मुकद्दम बात तो यह है कि देश का काम आगे बढ़े तो इस लिये माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि अपना कीमती समय हमारी त्रुटियां निकालने में न लगायें, कुछ पाजिटिव काम कर डालो देश सेवा के लिये और वह काम हो जायगा हमारी आलोचना करने का फिर भी समय बाकी रहेगा ।

तो मैंने बहुत समय इस सदन का लिया और जो बेसिक बातें इस मामले पर हैं वे तो माननीय गुप्ता जी फरमायेंगे । मैं तो दो चार बातें जो मेरी समझ में आयीं उनको पेश किया ।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, हमने ४ दिन से उन पुस्तिकाओं के ऊपर जो कि सदन के सदस्यों में वितरित की गई थीं बहस की और अपने २ मत उनके सम्बन्ध में प्रकट किये । पूर्व इसके कि मैं उन आलोचनाओं के कुछ विषयों को लूं मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्योंकि इस बात की शिकायत की गई कि जो पुस्तिकायें सदन में सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित की गईं उनमें योजना की वह रूपरेखा और उस प्रकार से जिस प्रकार से सदन के सदस्य चाहते थे उन्हें देखने को नहीं मिली । मैं उनसे किसी अंश तक सहमत हूं इस आलोचना में क्योंकि जो रूपरेखा सदन के समक्ष उपस्थित की गई वह अभी अधूरी है और उसका मुख्य कारण यह है कि अभी कितना धन हमें मिलेगा और कितना किन-किन कार्यों में हम लगायेंगे उसका अभी कोई कतई निर्णय तो हम ले नहीं सके हैं । हमारा कोई विचार अभी इस योजना के विषय में सदन के समक्ष विचार करने का नहीं था । परन्तु जैसा कि मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि विरोधी दल के द्वारा यह कहा गया कि हमें उस योजना की रूप रेखा के समझने और उसके ऊपर विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाय और शीघ्र ही प्रदान किया जाय पूर्व इसके कि वह योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष उसके नियोजन विभाग के कतई फैसले के लिये पेश की जाय । इसलिये हमारे लिये यह सम्भव नहीं था कि हम....

श्री मदन मोहन उपाध्याय—विरोधी दल के किस माननीय सदस्य ने कहा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी श्री नारायणदत्त तिवारी जी गये थे और उन्होंने आग्रह किया था कि इस योजना के ऊपर सदन में बहस करने का अवसर प्रदान किया जाय और एक दफा नहीं २, ३ दफा गये थे । मुझसे जब मुख्य मंत्री जी से बात हुई तो मैंने कहा था कि अभी रूप रेखा तो पूरी तरह से तैयार नहीं है । जब पूरी तरह से पूरी रूपरेखा आ जाय तब सदन ठीक तरह से अवश्य उसके ऊपर विचार विनिमय कर सकेगा और अपने विचारों को प्रकट कर सकेगा । इसलिये जो रूपरेखा सदन के समक्ष उपस्थित की गई वह मोटे तौर से क्या-क्या हम योजना में धन प्राप्त करने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आशा रखते हैं और उस धन को हम किस प्रकार से विभिन्न विभागों में वितरित करना चाहते हैं और खर्च करना चाहते हैं, यह बतलाती हैं--हां, एक बात अवश्य घोषित कर दी गई योजना में और वह बात भी घोषित की गई उस घोषणा के बाद जो कि केन्द्रीय सरकार और उसका योजना विभाग स्वयं घोषित कर चुका है यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में हमें देश की २५ प्रतिशत आमदनी में वृद्धि करनी चाहिए और साथ ही एक करोड़ बीस लाख आदमियों को रोजगार प्रदान करना चाहिए और इस प्रकार से देश के निवासियों के स्तर को ऊंचा करना चाहिए। हमने भी जो यह योजना की रूपरेखा रची है उसके पीछे भी वे ही विचारधारायें और धारणाएं छिपी हुई हैं, हमने जहां-जहां किसी एक विभाग के तहत में खर्च करने के लिये योजना बनायी है हम बराबर उसी ध्येय से प्रेरित रहे हैं और उसी तक पहुंचने की हमने चेष्टा की है। यद्यपि जो धनराशि अभी टेंटेटिव ढंग से स्वीकृत की गई है, वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नहीं है और कदाचित वह उस ध्येय को भी पूरा करने वाली नहीं है जिसके तहत में करीब १९ या साढ़े अठारह लाख आदमियों को हमें रोजगार देना होगा। यदि हम यह मान कर चलें कि सारे देश में एक करोड़ २० लाख या २५ लाख आदमियों को हमें रोजगार देना है जैसी कि घोषणा केन्द्रीय सरकार और उसका नियोजन विभाग और कमीशन कर चुका है। इसलिए सारी योजना के पीछे एक ही भाव छिपा हुआ है और वह भाव यह है कि हम अधिक मात्रा में बेरोजगारी को अपने बीच से हटायें और बेरोजगारी को हटाकर अपने प्रदेश के रहने वालों के स्तर को ऊंचा करने के लिए उचित कार्यवाही करें। यह कह देना कि योजना की तो कोई शक्ल ही नहीं शेपलेस शकल है, मैं नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से योजना को कह देना निर्मूल ही बात है। यह योजना जो गांव में प्रत्येक पांच मील के दायरे में एक अस्पताल को निर्मित करना चाहती है, जो एक मैटरनिटी सेंटर की स्थापना करना चाहती है, वह योजना जो हर डिवीजन के हेडक्वार्टर के अस्पताल में गरीबों के लिए, किसानों के लिए वह सुविधायें प्रदान करना चाहती है जो सुविधायें आज के समय वह अपने क्षेत्र के नजदीक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उन्हें लखनऊ आना पड़ता है, जिस सुविधा को प्राप्त करने के लिये उन्हें आगरा जाना पड़ता है, जिस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उन्हें कानपुर जाना पड़ता है, बड़े-बड़े तीन चार जो अस्पताल हैं जहां आधुनिक विज्ञान को पंडित रहते हैं वहां जाना पड़ता है, यदि हम उस योजना के तहत में इन नौ जिलों के अस्पतालों में कमिश्नरियों के हेडक्वार्टर पर इस बात का प्रबन्ध कर दें कि वहां आधुनिक ढंग का इलाज हो सके और वहां ऐसे विज्ञान के पंडितों को रख दें जो अपने-अपने विषय के पंडित हैं तो क्या इस योजना के पीछे कोई प्लान नहीं है ? क्या इस योजना के पीछे कोई शक्ल नहीं है। मैं सदन से यह नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से यह कह देना कि इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसका कोई ध्येय नहीं है, यह बेमाने बात है। अगर इस योजना से हम दो तीन चार पांच मील के पीछे एक मैटरनिटी सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं, यदि हम १,६०० मैटरनिटी सेंटर सारे प्रदेश में इस पंचवर्षीय योजना में स्थापित करना चाहते हैं तो क्या उस योजना के पीछे उस ग्रामीण भाई की सेवा की बात छिपी नहीं है जिसकी कि हम सेवा करना चाहते हैं जिसकी अवस्था में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके स्तर को हम ऊंचा करना चाहते हैं जो कि अब तक असुविधाओं से घिरा हुआ है जिसे अपनी माता और बहन को इलाज के लिए बहुत दूरी तक जाना पड़ता है और कभी कभी वह बहुत दूरी तक जाने में असमर्थ रहता है। यदि हम अपने प्रदेश में २५ जिलों में, एक साथ अगर ५१ जिलों में नहीं कर सकते हैं, उन अस्पतालों में अगर हम मेंटल डिजीजेज के लिए इन्तजाम कर देते हैं, यदि हम टी० बी० के मरीजों के लिए इन्तजाम कर देते हैं, यदि हम लेप्रोसी का इन्तजाम कर देते हैं तो क्या सदन के सदस्य कहने के लिए उद्यत रहेंगे कि इस योजना

का भी कोई प्लान नहीं है, इसके पीछे कोई आदमी के स्तर को ऊंचा करने का भाव छिपा नहीं है, जिसके स्तर को हम उठाना चाहते हैं? मैं इसलिए नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस प्लान के पीछे महज लोगों के स्तर को ऊंचा करने की बात नहीं है, यदि हम लोगों को रोजगार में लाना चाहते हैं, उनकी बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं, यदि हम अन्डर इम्पलायमेंट को दूर करना चाहते हैं, तो क्या वह उन आंकड़ों से सिद्ध नहीं होता है? क्या वे आंकड़े इस बात के द्योतक नहीं हैं, जो यह बताते हैं कि हम गांवों में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ायेंगे और बढ़ा कर उन ग्रामीण भाइयों को अन्य उद्योगों में लगायेंगे, उनकी आमदनी बढ़ायेंगे और इस प्रकार उनके स्तर को ऊंचा करेंगे? जिन ग्रामीण भाइयों को अभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, जिनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, यदि उनके लिए हम ५ हजार स्कूलों की रचना करके उनको एक नयी रोशनी देने जा रहे हैं तो क्या इस योजना के पीछे कोई प्लान नहीं है? क्या शिक्षा ऐसे व्यक्तियों को देने के लिए हमारी कोई योजना नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक विभाग के क्षेत्र में जो हम व्यय करने जा रहे हैं उसके पीछे आदर्श हैं। सदन के सदस्यों ने यह कहा कि यह तो सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ ले जाने वाली योजना नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि सोशलिस्ट पैटर्न का क्या मतलब लोग लगाते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि सोशलिस्ट पैटर्न क्या कोई शाब्दिक बात है? क्या उस व्यवस्था से लड़ने की बात है, या उस वास्तविकता को लाने की बात है जिसके लिये हम प्रयत्नशील हैं जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं? आखिर को सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे हमारे बीच में आयेगा? वह तो तभी आयेगा जब असमानता हटेगी, जब समाज की कुरीतियां हमारे बीच से हटेंगी, जब अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देकर उनकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। साथ में उन्हें अधिक से अधिक युग की आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। क्या यह योजना उस ओर ग्राम के रहने वालों को नहीं ले जा रही है? मेरे सहयोगी ने बतला दिया कि असली हिन्दुस्तान गांव में रहता है। तो क्या इस योजना के पीछे ग्रामीण भाई की सेवा करने की चेष्टा नहीं है, क्या उसके स्तर को ऊंचा करने की बात नहीं है? यदि हम प्रदेश में ७५२ राष्ट्रीय प्रसार खंड स्थापित कर दें और यदि हम ३३२ या ३२२ इंटैंसिव ब्लाक प्रदेश के ग्रामीण उत्पादन के स्थापित कर दें तो क्या उनसे ग्रामीण भाइयों का स्तर ऊंचा नहीं होगा। क्या उनसे जो खेती का रोजगार करते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होगी, उससे उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनकी जो गरीबी है शीघ्रता के साथ दूर नहीं होगी? और क्या उसके तहत में विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित नहीं होंगे और क्या उन्हीं के तहत में जहां तक उनके इलाज इत्यादि का सम्बन्ध है उसका उचित प्रबन्ध नहीं होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी योजना है उसके पीछे लोगों के स्तर को उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है, चेष्टा की जा रही है। जो अब तक गिरे रहे हैं, जो असमानता में रहे हैं, जो पददलित रहे हैं और जिन्हें समाज ने ठुकराया है क्या यह योजना और इसका भाव और इसका ध्येय हमें उस ओर नहीं ले जाता है? उस समाजवादी व्यवस्था की तरफ नहीं ले जा रही है जो समाजवादी व्यवस्था हम सब चाहते हैं कि हमारे बीच से असमानता हटे, हमारे बीच में समानता स्थापित हो, हमारे बीच से बेरोजगारी हटे, हमारे बीच से लंगड़े और लूलों की व्यवस्था हमेशा के लिए दूर हो।

सदन में यह कहा गया, एक माननीय सदस्य ने जो पहले विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने तो यह कहा कि यह तो अमीरों को बढ़ाने वाली योजना है, यह गरीबों को गुर्बत को बढ़ाने वाली योजना है। मुझे बहुत अचम्भा है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जो कि विरोधी दल के नेता के पद को सुसोभित कर चुका हो इस तरह की बात इस योजना के सम्बन्ध में कह दे। इस ३२५ या ३७० करोड़ मान लीजिये, या वही मान लीजिये जिसकी अभी केन्द्रीय सरकार ने टेन्टेटिव मंजूरी प्रदान की है क्या उसके तहत में कोई यह कह सकता है कि इसमें अधिक से अधिक गरीबों के ऊपर व्यय किया जाने वाला नहीं है, असहायों के ऊपर व्यय होने वाला नहीं है। यदि हरिजन भाइयों के लिये ५, सवा ५ करोड़ रुपया व्यय होने वाला है तो क्या वे अमीर हैं, क्या वे ऐसे हैं जिनके पास सारे साधन मौजूद हैं। और यदि उनके उठाने का प्रबन्ध किया जा रहा है तो उससे क्या अमीरी बढ़ाई जा रही है? उससे क्या गरीबों की सेवा नहीं होती है। और वे राष्ट्रीय प्रसार खंड जिनका वर्णन अभी मैंने किया और वे तमाम अस्पताल जो देहाती क्षेत्रों में बनने वाले हैं और वे तमाम मैटर्नाटी सेन्टर्स जो देहाती क्षेत्रों में खोले जाने वाले हैं क्या वे अमीरों की सेवा करने जा रहे हैं? और ये गृह उद्योग धंधे किनको बढ़ाने जा रहे हैं? क्या ये अमीरों को बढ़ायेंगे? क्या ये उनकी शक्ति को बढ़ायेंगे? क्या ये हमारे देहात के रहने वालों की सेवा नहीं करेंगे? तो यह कहना कि यह तो सोशलिस्टिक पैटर्न से बिल्कुल भिन्न जाने वाला रास्ता है मैं नम्रता से यह कहूंगा कि इस प्लान के प्रति अन्याय करना है और उन बातों के प्रति विश्वास प्रकट करना है जो यदि प्रसारित होती रहीं तो वे उन लोगों को जिन्हें हमें नया प्रकाश देना है निरुत्साह कर सकती है। आखिर क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे देहात में रहने वाले ग्रामीण भाइयों का ध्यान अपने स्तर को उंचा करने की तरफ नहीं गया? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज यह कह सकता है कि उनका ध्यान उधर नहीं गया और यदि नहीं गया होता तो क्या यह सम्भव हो सकता था कि दो-दो करोड़ का कार्य मुफ्त दे कर देते, वे स्वयं अपने धन से पंचायतें बना लेते, कुओं का निर्माण कर लेते, वे स्वयं बाग इत्यादि लगा लेते और गांवों में सफाई इत्यादि का प्रबन्ध कर लेते? आज गांव-गांव में जो हमें दिखाई पड़ रहा है क्या वह प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसके प्रकाश की देन नहीं है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी तो हमें और तेजी के साथ ले जाने वाली है और ले जाकर प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ा कर और उनकी मात्रा को बढ़ा कर जो अंडर एम्पलायड और अनएम्पलायड लोग हैं उन्हें रोजगार देने जा रही है।

मैंने सदन से उस दिन कहा था कि देहात में आज ३ फी सदी व्यक्तियों में तो बिल्कुल बेरोजगारी है और सिर्फ ३० फीसदी आदमियों के पास जितना कार्य होना चाहिये उतना मिल हुआ है और ६६ फीसदी आदमी अन्डर एम्पलायड हैं। तो उन अन्डर एम्पलायड आदमियों के लिये तो इस योजना में ऐसा प्रबन्ध किया जाने वाला है कि उन्हें पूरा कार्य करने का अवसर मिले। मैं सदन के समक्ष यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने जो आंकड़े सदन के समक्ष उद्योग विभाग और उद्योगों के सम्बन्ध में दिए थे उनमें वे आंकड़े शामिल नहीं हैं जो केन्द्रीय सरकार से हमें विभिन्न बोर्डों की सिफारिशों पर मिलेंगे क्योंकि मैंने यह बतलाया था कि २० से ५० करोड़ की रकम जो ऐसी है उसे केन्द्रीय सरकार ने रेलवे के निर्माण के लिये, बड़े-बड़े उद्योगों के निर्माण के लिये और छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिये रख छोड़ा है। और वह जो हिस्सा छोटे छोटे उद्योग धंधों का है, जो धनराशि बोर्डों के पास होगी। यहां हैंडलूम बोर्ड है, खादी बोर्ड है और हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड है, उनका धन है वह भी प्रदेश को मिलता है और वह प्रदेश को ऐसी योजनाओं के अनुपात में दिया जाता है तो यदि १०० करोड़ रुपया रख जायगा तो उसमें से भी अपने प्रदेश में जो छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधे हैं, उनको विकसित करने के लिये धन मिलेगा और जो हमने यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना सदन के समक्ष उपस्थित की है, इसमें वह धनराशि सम्मिलित नहीं की है क्योंकि

वह हमें मिलेगी इन बोर्डों की सिफारिश पर, इन योजनाओं पर विचार करने के बाद जो प्रदेशीय सरकार ने इन बोर्डों के समक्ष उपस्थित की है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि इस योजना में गल्ले की बात और खाद्यान्न में सेल्फ सफीशियेन्सी की बात हमने कही और उसको भी सदन के चन्द माननीय सदस्यों ने आलोचना के रूप में यह कह कर रखने की चेष्टा की कि यह तो हमारी सरकार को ढिंढोरा पीटने की नीति है। वास्तव में बात यह है कि सात या साढ़े सात छटांक से अधिक किसी को खाना नहीं मिलेगा। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी श्री फूलसिंह इसका उत्तर दे चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बात ऐसी कही गई कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां तक प्रदेश का सम्बन्ध है, जो कपड़े की योजना रखी थी, उसके तहत में यह निर्धारित कर रखा था कि कम से कम दस गज कपड़ा प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके और उसके तहत में हमने अठारह साढ़े अठारह सौ गज करोड़ कपड़ा मिलों से बनवाया और साढ़े चौदह सौ करोड़ गज कपड़ा हैंडलूम से बनवाया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसे कि माननीय सदस्यों को ज्ञान है केन्द्रीय सरकार ने जो मिल से कपड़ा तैयार होता है उसको करीब साढ़े पांच सौ करोड़ गज की सीमा निर्धारित कर दी है यानी इससे ज्यादा कपड़ा मिलें नहीं बना सकतीं हैं। बाकी हैण्डलूम के द्वारा तैयार होगा और उसकी सीमा भी रख दी है। ३३० करोड़ गज कपड़ा हैंडलूम द्वारा और २०० करोड़ गज कपड़ा पावर लूम द्वारा तैयार होगा। यदि इतना कपड़ा हमारे यहां बनने लगेगा तो इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को १८ गज कपड़ा मिलने लगेगा। आप यह कहेंगे जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमको और स्त्रियों को कम से कम २५ गज कपड़ा चाहिये तो उत्तरोत्तर यह योजना हम को इसी ओर तो ले जा रही है। क्या हम चाहते हैं कि एक साथ ही हमारी यह कमी पूरी हो जाय। २५ गज कपड़ा हर एक को मिलेगा और इस से अधिक भी मिलेगा। लेकिन उसके लिये इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के तहत से गुजरना पड़ेगा। कोई मुल्क एक साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, कमियों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता और खामियों को एक साथ दुरुस्त नहीं कर सकता, इसलिये इस योजना का ध्येय है कि इसके तहत में १८ गज कपड़ा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को हम देना चाहते हैं। मिलों के कपड़े के अलावा हैंडलूम और पावरलूम द्वारा भी हम इस कमी को पूरा करना चाहते हैं जिससे १८ गज कपड़ा प्रत्येक प्रदेश के व्यक्ति को सुविधा से इस्तेमाल करने के लिये दिया जा सके।

आखिर क्या बात है, वह समय भूल गये। अभी ४–५ साल का समय बीता है जब हमें ९–१० गज कपड़ा भी पाना मुश्किल होता था। यदि हम अपने प्रदेश का उत्थान करना चाहते हैं, अपने प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिये हिन्दुस्तान का नया स्वरूप बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमें इन सुविधाओं के लिये इस प्लांड योजना के पीरियड में कुछ दिक्कतों से भी गुजरना पड़े। और हमारी आवश्यकतायें उस तरह से पूरी न हो सकें जिस तरह से कि हम उन्हें पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। आखिर को जो सोशलिस्टिक पैटर्न है वह एक दिन में हमारे बीच स्थापित होने वाला नहीं है। उसके लिये योजना बना कर, हमें अपने स्तर को ऊंचा करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुये आगे बढ़ने का प्रबन्ध करना पड़ेगा। यहां माननीय गेंदा सिंह जी ने कुछ बातें इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में भी कहीं थीं। उन्होंने यह कहा कि यह सरकार तो नेशनलाइजेशन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज का करती नहीं। उनका मतलब शुगर इंडस्ट्री से था कि शक्कर का रोजगार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है और उसका हम राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं। यद्यपि यह सदन

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

राष्ट्रीयकरण के विषय में बात करने का स्थान नहीं था क्योंकि राष्ट्रीयकरण का जो विषय है उसका केन्द्र से सम्बन्ध है। जो विधान हमने अपने देश में लागू कर रखा है उसमें राष्ट्रीयकरण की नीति का निर्धारित करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में अपनी नीति निश्चित कर रखी है। माननीय सदस्यों को कभी कभी प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को सुनने का अवसर मिला होगा। क्या उन्होंने यह घोषणा नहीं कर रखी है कि हम समाजवादी व्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं? जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है उसमें हम राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनायेंगे, लेकिन अपने साधनों को देखते हुए और अपने तरीकों पर चलते हुए हम अपनी राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनायेंगे। आज देश को आवश्यकता है अधिक लोगों को रोजगार में लगाने की, आज देश को आवश्यकता है अधिक वस्तुएं उत्पन्न करने की और यदि हमारी समाजवादी व्यवस्था हमें इस प्रकार का अवसर प्रदान करती है तो हम उस ओर चलने का प्रबन्ध करेंगे वरना हम देश के प्रत्येक नागरिक से सहायता और सहयोग लेते हुए अपनी उस समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय कर रखा है कि आज हम अपने प्रदेशों में, देश में, प्राइवेट सेक्टर में भी और उद्योग को चलाने के लिये इजाजत देंगे।

मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक व्यावहारिक नीति है। यह उसे ध्येय तक ले जाने वाली नीति है क्योंकि जहां तक राष्ट्रीयकरण का विषय है उसके विषय में हम कभी भी कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज जो आपको समस्याओं को सुलझाना है, लोगों को रोजगार में लगाना है, व्यवसाय को बढ़ाना है, उद्योग को बढ़ाना है, तो क्या वह बातों से हो जायगा, वह क्या तारीफ से हो जायगा या क्या वह शाब्दिक सोशलिस्टिक प्रस्ताव से आ जायगा? क्या उसके लिये हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा? और जब प्रयास करना पड़ेगा तो क्या यह बुद्धिमत्ता होगी, क्या यह दूरदर्शिता होगी कि जो व्यक्ति हमें सहायता दे सकते हैं, जो अपने अनुभव से हमें फायदा पहुंचा सकते हैं उनके अनुभव से हम फायदा न उठावें और उनसे सहयोग न लें? हां, जब हम समाजवादी व्यवस्था को रचने की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आज केन्द्रीय सरकार का भी और प्रत्येक प्रदेश की सरकार का भी कर्तव्य है कि जो लोग आज उद्योग विभाग में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं हम उन्हें ऐसा अवसर प्रदान न करें जिससे कि वे नाजायज मुनाफा उठायें, लोगों को चूसें और इसीलिये नियंत्रित प्राइवेट सेक्टर की आज केन्द्रीय सरकार इजाजत दे रही है। उसकी जो लाइसेंसिंग पालिसी है, उसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पालिसी है वह क्या बात साबित करती है? वह क्या बात सिद्ध करती है? आज वह लाइसेंसिंग पालिसी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पालिसी भी हमें समाजवादी व्यवस्था की ओर जाना है यह संकेत कर रही है। उस व्यवस्था के हित में है। सरकार अपनी नीति इस बात को विचार में रख कर निर्धारित करती है। क्या आज यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार जब अनुभव करती है कि किसी क्षेत्र में उद्योगपतियों ने अधिक धन कमा लिया है तो उसे टैक्स के रूप में वह उनसे वसूल करती है? आप अपने शक्कर के मसले में देखें। आपको जो ज्यादा शक्कर पैदा हुई और जिससे कदाचित केन्द्रीय सरकार को यह आभास हुआ कि अधिक मुनाफा होने वाला है तो उन्होंने उस टैक्स में वृद्धि कर दी और इस तरह से उनकी जो आमदनी बढ़ी थी, मिलों की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने राष्ट्र के कोष के लिये टैक्स के रूप में ले लिया।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि क्या वह समय को बढ़ाना चाहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, मैं अभी समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे हैंडलूम बोर्ड की मीटिंग में जाना है।

मैं दूसरी बातों में न जाकर अन्य बातों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो आदर्श इस योजना के तहत में रखे गये हैं उन भावनाओं की प्रेरणा से कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूपरेखा जिलेवार और तहसीलवार इस योजना के तहत में रखी गयी है उसकी जब मंजूरी आ जायगी तब वह सदन के सामने कदाचित रखने का प्रयास किया जायगा। वह विभिन्न स्थायी समितियों के सामने भी आयेगी जो विभिन्न विभागों से सम्बन्ध रखती हैं। मैं इस समय सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग इस योजना के पीछे केन्द्रीय सरकार को उपस्थित की जाने वाली है उन मांगों के पीछे इस सदन का सहयोग होना चाहिये और इस सदन की अनुमति होनी चाहिये। आपकी सहायता की पूरी-पूरी आवश्यकता है तब हम प्रदेश की अधिक सेवा कर सकेंगे और प्रदेश की आवश्यकताओं को उस मात्रा में पूरा कर सकेंगे जिस मात्रा में पूरा करने की जरूरत है। उस दिशा में यह सरकार चलना चाहती है। हम आशा करते हैं कि इस योजना के पूरा होने के लिये और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक सदस्य का, पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को विभिन्न सुझावों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। उन सुझावों के तहत में इस योजना की रूपरेखा में जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं उनको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से उनकी मन्शा को पूरा करने में पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जिस तरह से आखिर में बनेगी उसमें प्रत्येक सदस्य का सहयोग प्राप्त रहेगा, प्रत्येक दल के सदस्य का सहयोग प्राप्त रहेगा। इसमें देश का हित निहित है। इसमें अधिक मात्रा में उद्योगधंधे की तरफ जा सकते हैं, जिसकी हमें अभिलाषा है।

"भूमि-संरक्षण मंडल" के निर्वाचन विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष—"भूमि संरक्षण मंडल" के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का समय आज ३ बजे तक निर्धारित किया गया था। समय के अन्दर निम्न अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त हुये :

श्री टीकाराम

श्री कमलासिंह

श्री चिरंजीलाल पालीवाल

श्री दीनदयालु शास्त्री

परन्तु क्योंकि श्री दीनदयालु शास्त्री ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये तीन स्थानों के लिये केवल तीन ही अभ्यर्थी शेष रह गये हैं। अगर कल १२ बजे तक कोई नाम वापस न लिया गया तो इन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा। जिनके नाम घोषित किये जायंगे वह ये हैं :

श्री टीकाराम

श्री कमलासिंह

श्री चिरंजीलाल पालीवाल

आश्वासन समिति की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—दूसरी सूचना आश्वासन समिति के विषय में देनी है। ९ सितम्बर को सदन ने मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं यह समिति मुकर्रर कर लूं। यह अच्छा मौका है क्योंकि माननीय सदस्यों को महीने भर का मौका मिल जायगा। इस फुरसत में वह अपनी याददाश्त ताजा कर लेंगे. कि कौन-कौन आश्वासन उनको माननीय मंत्रियों ने दिये थे। यह समिति इस प्रकर से होगी :

श्री गंगा प्रसाद सिंह
श्री व्रजबिहारी मिश्र
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
श्री अजीज इमाम
श्री राम सुमेर
श्रीमती प्रकाशवती सूद
श्री गोवर्द्धन तिवारी
श्री नेकराम शर्मा
श्री जगदीश शरण (बरेली)
श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि
श्री जोरावर वर्मा
श्री मदनमोहन उपाध्याय
महाराजकुमार बालेन्दुशाह
श्री कृष्णचन्द्र शर्मा
श्री रामसुन्दर पांडेय

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—इस समिति का क्या नाम है ?

श्री अध्यक्ष—इस समिति का नाम आश्वासन समिति है। यह समिति देखेगी कि क्या आश्वासन थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई है फिर जो उचित कार्यवाही करनी होगी यह करेगी और सरकार को लिखेगी। इस समिति के जो पहिले सभापति होंगे वह श्री बालेन्दुशाह होंगे। मैं समझता हूं कि सभापति की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रथा कायम की जाय और उसकी मैं सूचना दे रहा हूं। श्री बालेन्दुशाह जो सभापति उस समय तक के लिये होंगे जब तक नयी समिति न बने। मैं समझता हूं कि इसके लिये तब तक नियम भी बना लिए जायेंगे। अगर एक-एक वर्ष के लिये एक-एक पार्टी का सभापति बनाने की प्रथा बना ली जाय तो अधिक अच्छा होगा। जैसे इधर से बालेन्दुशाह जी हैं, गेंदा सिंह जी हैं और उधर बहुमत की पार्टी के सदस्य भी हैं। रोटेशन से इन तीनों दलों के सदस्यों को सभापति होने का मौका दिया जाना उचित होगा। इससे हर एक पार्टी को मौका भी मिल जायगा और यह भी मालूम हो जायगा कि किस की याद्दाश्त अच्छी रहती है तथा उन आश्वासनों को कार्यान्वित कराने में सदन की कौन अधिक सहायता कर सकता है।

अब हम उठते हैं और २१ नवम्बर को, सोमवार के दिन ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५ को ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ;
२१ अक्तूबर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

वर्ष १९५४-५५ में हरिजन विभाग की तरफ से निम्नलिखित हरिजनों की उनके समक्ष लिखी गयी धनराशि उद्योग-धंधों के लिये स्वीकृत की गयी है :

क्रमांक	नाम	धन
		रु०
१	श्री अनूपराम	२५०
२	श्री बंजनाथ प्रसाद	१००
३	श्री पारसनाथ पासी	२५०
४	श्री शंकरराम	१००
५	श्री झूरी लाल	२५०
६	श्री पियारेलाल	२५०
७	श्री विश्वनाथ बास	२५०
८	श्री लल्लू राम	२५०
९	श्री महाबीर	२५०
१०	श्री रामजियावन	२५०
११	श्री राम खेलावन	२५०
१२	श्री छांगूराम	२५०
१३	श्री चन्द्र बली	२५०
१४	श्री खमलाल	२५०
१५	श्री बाबू राम पासी	२५०
१६	श्री वंश नारायन	३००
१७	श्री हरिहर प्रसाद	३००
१८	श्री रामनाथ	२५०

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

सूची जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १८ के उत्तर में किया गया है :

जिला मैनपुरी में स्थित सहायता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष १९५४–५५ में स्वीकृत आवर्त्तक अनुदान का विवरण

क्रम-संख्या	संस्था का नाम (कक्षा १२ तक)	स्वीकृत अनुपालन अनुदान	स्वीकृत महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति संबंधी अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०
१	नारायण हायर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद मैनपुरी	२१,४९२	७२० ९३।।)	३७२	२,४३०।।)
२	क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, मैनपुरी	११,६४०	४८०	५५२	१,५५३
३	गिरधारी ए० बी० हा० से० स्कूल, सिसोगंज, मैनपुरी	६,४३२	४२०	१२०	९२७
४	डी० ए० वी० हा० से० स्कूल, मैनपुरी ..	५,८४४	४२०		१,१८३
५	लोधी राजपूत हा० सें० स्कूल, जसराना, मैनपुरी	४,१८८	६००		७५६।।)
६	पालीवाल हा० सें० स्कूल, शिकोहाबाद, मैनपुरी	३,७३२	३६०		
७	क्षत्रिय हा० सें० स्कूल, सिसोगंज, मैनपुरी	३,१८०	४२०		
८	ए० के० हा० सें० स्कूल, शिकोहाबाद, मैनपुरी	८,७१२	६००	६३६	
९	अमर शहीद हा० सें० स्कूल, बेवर, मैनपुरी ..	शून्य	शून्य		
१०	नेशनल हा० से० स्कूल, भोगांव, मैनपुरी।	शून्य	शून्य		
११	श्री चित्रगुप्त हा० सें० स्कूल, मैनपुरी ..	शून्य	शून्य		
	संस्था का नाम कक्षा १० तक				
१२	एल० जे० ए० एच० हायर सें० स्कूल, करहल, मैनपुरी	६,२१६	२४०	१२०	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

सूची जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में किया गया है

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम जिनको हाई स्कूल तक की सहायता मिलती है	वित्तीय वर्ष जब से विद्यालय को कक्षा १० तक का अनुदान दिया जाता है
१	ए० के० हायर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद	१६२६–२७
२	पालीवाल हायर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद	१६५३–५४
३	क्षत्रिय हायर सेकेंडरी स्कूल, सिसोगंज	१६५३–५४
४	एल० जे० ए० एच० हा० सें० स्कूल, करहल	१६४७–४८
५	अमर शहीद हायर सेंकेंडरी स्कूल, बेवर	१६५५–५६
६	नेशनल हायर सेंकेंडरी स्कूल, भोगांव	१६५५–५६
७	श्री चित्रगुप्त हायर सेंकेंडरी स्कूल, मैनपूरी	१६५५–५६

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम जिनको हाई स्कूल और इन्टर दोनों की सहायता मिलती है	वित्तीय वर्ष जब से विद्यालय को कक्षा १२ तक का अनुदान दिया जाता है
१	श्री नारायण हायर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद	१६४५–४६
२	क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, मैनपुरी	१६५४–५५
३	गिरधारी ए० सी० हा० सें० स्कूल, सिसोगंज	१६५२–५३
४	डी० ए० वी० हा० सें० स्कूल, मैनपुरी	१६५४–५५
५	लोधी राजपूत हा० सें० स्कूल, जसराना	१६५३–५४

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर-पीछे पृष्ठ ४८२ पर)

विवरण-पत्र

ट्रेनिंग के लिए चुने गये हरिजन उम्मीदवारों

कमिश्नरी का नाम	की संख्या	ट्रेनिंग के स्थान
मेरठ ..	६	.. मेरठ
		गढ़वाल
आगरा ..	७	.. मुरादाबाद
		आगरा
बरेली ..	७	.. फर्रुखाबाद
		लखनऊ
लखनऊ ..	५	.. इलाहाबाद
		कानपुर
इलाहाबाद ..	४	.. नैनीताल
		अल्मोड़ा
		बनारस
योग ..	३२	बरेली
		फैजाबाद

टिप्पणी--३२ उम्मीदवारों में से केवल २२ ही ट्रेनिंग लेने आये हैं। इनमें से १२ ट्रेक्टर हैं और १० मिस्त्री।

पी० एल० यू० पी०—ए० पी० १२३ एल० ए०—१९५६-७९६।